सत्र-04(भाग-2) **27मार्च, 2026**

खण्ड- 08 ..... शुक्रवार, ...

अंक- 26 **06 चैत्र,1948(शक्)**

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-04(भाग-2) में अंक 23 से 26 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-04(भाग-2) शुक्रवार, 27मार्च, 2026/06 चैत्र,1948(शक्)अंक-26

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	विशेष उल्लेख(नियम-280)	6-
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश	10-13
4.	विशेष उल्लेख(नियम-280).....जारी	14-26
5.	माननीय अध्यक्ष द्वारा विभिन्न सीएजी रिपोर्ट्स के विषय में सदन को सूचना	27-28
6.	सी.ए.जी.रिपोर्ट(दिल्ली जल बोर्ड) पर चर्चा	29-34
7.	माननीय मंत्री का वक्तव्य(नियम-270)	35-42
8.	सी.ए.जी.रिपोर्ट पर चर्चा (...जारी)	43-59
9.	समिति के प्रतिवेदनों पर सहमति	60-82
10.	विधेयक पर विचार एवं पारण	83-84
11.	वार्षिक बजट (2026-27) पर चर्चा	85-113
12.	अनुदानों की मांगें(वर्ष 2026-27)	114-124
13.	दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026	125-127

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही
सत्र-04(भाग-2) शुक्रवार, 27मार्च, 2026/06 चैत्र,1948(शक्)अंक-26

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

दिनांक 27.03.2026 को सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्रं.सं.	सदस्य का नाम	क्रं.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	26.	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
2.	श्री अभय कुमार वर्मा	27.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
3.	श्री अजय कुमार महावर	28.	श्री पवन शर्मा
4.	श्री अनिल कुमार शर्मा	29.	श्रीमती पूनम शर्मा
5.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	30.	श्री राज करन खत्री
6.	श्री आशीष सूद	31.	श्री राज कुमार भाटिया
7.	श्री अशोक गोयल	32.	श्री राज कुमार चौहान
8.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	33.	श्री रवि कान्त
9.	डॉ. अनिल गोयल	34.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
10.	श्री गजेन्द्र दराल	35.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
11.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	36.	श्रीमती रेखा गुप्ता
12.	श्री हरीश खुराना	37.	श्री संजय गोयल
13.	श्री जितेन्द्र महाजन	38.	श्री सतीश उपाध्याय
14.	श्री कैलाश गहलोत	39.	श्रीमती शिखा रॉय
15.	श्री कपिल मिश्रा	40.	श्री श्याम शर्मा
16.	श्री करनैल सिंह	41.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
17.	श्री करतार सिंह तंवर	42.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
18.	श्री कुलदीप सोलंकी	43.	श्री तिलक राम गुप्ता
19.	श्री कुलवन्त राणा	44.	श्री उमंग बजाज
20.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	45.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
21.	श्री मनोज कुमार शौकीन		

22.	श्री मोहन सिंह बिष्ट		
23.	श्रीमती नीलम पहलवान		
24.	श्री नीरज बैसोया		
25.	श्री पंकज कुमार सिंह		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र 04(भाग-2) शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/ 06 चैत्र 1948 (शक)अंक-26

सदन पूर्वाह्न 11.06 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : नमस्कार, नमस्कार सभी को। विशेष उल्लेख (नियम 280) के तहत अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री गजेंद्र सिंह यादव।

<u>विशेष उल्लेख(नियम-280)</u>

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि महरौली विधानसभा में क्षेत्र की ओर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। महरौली विधानसभा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन है जो मां योगमाया मंदिर के साथ में एसडीएम ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस के बिल्कुल सामने एक जमीन है। वह जमीन कुतुब मीनार आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट है विश्व विख्यात उसकी बाउंड्री के साथ लगती है। उस जमीन पर मुझे क्षेत्र की जनता के द्वारा RWAs के द्वारा जानकारी मिली कि बहुत वर्षों से वहां कार और स्कूटर की पार्किंग चलाई जा रही है। मुझे यह भी जानकारी मिली कि दिल्ली में पार्किंग चलाने का जो काम है वो एमसीडी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह कार पार्किंग और स्कूटर पार्किंग एमसीडी के द्वारा दी गई नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जो अवैध पार्किंग चलाई जा रही है वो एसडीएम, डीएम और रजिस्ट्रार के संज्ञान में है क्या? यह जमीन पर जो पार्किंग चलाई जा रही है, वो किस संस्था या किस प्राइवेट कंपनी को दी गई है, उसके दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। कौन से सन् से यह पार्किंग दी गई है और इसमें अभी तक कितना पैसा वो दिल्ली सरकार को या किसी भी लोकल बॉडी को इसमें से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आपसे अनुरोध है व्यापक जनहित में देखते हुए इस मामले पर जरूर विचार करें और यदि यह पार्किंग माफिया की मिलीभगत से सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से यदि यह पार्किंग वर्षों से चलाई जा रही है तो कृपया इस पर उचित निर्देश दें और इस पर कार्यवाही करी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी एक मिनट लूंगा बस।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष : नहीं किस बारे में।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष इसी 280 के बारे में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हां बताइए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: ये है अध्यक्ष जी 280 का क्वेश्चन जो होता है हमारे सबका है, लेकिन देखो गैलरी खाली है अफसरों की, हमें पढ़ने का क्या फायदा गैलरी खाली है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मैं सुन रहा हूं ना।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: देखो ना आप कोई जवाब मंत्री ने अभी तक दिया ही नहीं किसी को भी मैंने 280।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: देखिये 280 जो है मैं आपको इसकी प्रक्रिया बता।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी 280 में, सुनना तो चाहिए ना, ये नहीं मैं कहता जवाब दो। मैं ये नहीं कह रहा किसी मंत्री जी को या जो वहां अफसर है हम नहीं चाह रहे कि जवाब दो लेकिन सुनाने का तो हमारा अधिकार है कि नहीं यह बताओ अध्यक्ष जी है कि नहीं अधिकार, इसका मतलब कोई मतलब वो नहीं ना, सीरियस नहीं ले रहा ना। हम पढ़ लेते हैं कोई जवाब दे ना दे, सीरियस कोई नहीं ले रहा। आप थोड़ी सख्ती रखो अध्यक्ष जी, आप पे हमें बड़ा यकीन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप तो शुरू से रहे हो ना एमएलए भी कितनी बार रहे हो, पूरा विपक्ष में बैठ के आपने पूरा देखा है, हम यह नहीं कह रहे हमें जवाब चाहिए। किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें ये जरूर।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए, अब माननीय सदस्य श्री चंदन कुमार चौधरी।

श्री चंदन कुमार चौधरी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिल्ली के निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध बेड तथा आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के उपचार की वर्तमान व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। किंतु जमीनी स्तर पर यह देखा जा रहा है कि निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों को उपचार प्रदान करने में नाकामी कर रहे हैं जो अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी ईडब्ल्यूएस के नॉर्म्स के अनुसार से 25% ओपीडी में

इलाज होना चाहिए। जिसको जमीन हमारे डीडीए के द्वारा आवंटित किया गया है और 10% जो एडमिट करके इलाज होता है उसमें 10% बेड अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन निजी अस्पतालों की मिलीभगत से यह व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। निजी अस्पताल अपने पैसों से बाउंसर रख के गरीब पेशेंट को वहां से भगाने का काम करते हैं और जो भी गरीब पेशेंट वहां जाता है तो सीधा कहते हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपका ध्यान विशेष रूप से अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां पर बत्रा हॉस्पिटल और मजीदिया हॉस्पिटल है और पास में मैक्स हॉस्पिटल है। वहां की स्थिति अध्यक्ष जी इतनी दयनीय है कि हमारे जो सरकार की तरफ से नोडल ऑफिसर हैं वो भी बदल दिए जाते हैं बगैर हम लोगों के राय लिए हुए और वो नोडल ऑफिसर का पता भी नहीं होता, ना वो मुझे, हमें कॉल करते हैं, ना वो जानकारी देते हैं कि हम नोडल ऑफिसर यहां हैं और जो निजी अस्पताल के नोडल ऑफिसर हैं उनकी मिलीभगत से और धांधली करते हुए हमारे गरीबों का जो सपना है जो एक विकसित दिल्ली बनाने का हमारी मुख्यमंत्री जी ने सपना संजोया है उसमें एक बाधा उत्पन्न हो रही है और गरीबों का सपना बिल्कुल अधूरा रह जाता है। लोग घर बेच के अपना इलाज करते हैं। वही पेशेंट यदि paid करके चाहता है कि हम यहां इलाज कराएं तो तुरंत अवेलेबल हो जाता है बेड, और यदि ईडब्ल्यूएस के तहत पर वो करना चाहते हैं तो वहां के बाउंसर उसको उठा के फेंक देते हैं। तो इस समस्या का निदान आपके ध्यान देने पर ही हो सकता है क्योंकि मंत्री जी भी आज नहीं है तो मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं अपने क्षेत्र में और निजी अस्पतालों में जिसको जमीन हमारे केंद्र सरकार की ओर से डीडीए के द्वारा आवंटित की गई है। इस पर शीघ्रातिशीघ्र संज्ञान लेकर इसकी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए और एक सुचारू ढंग से सभी हॉस्पिटल में एक पोर्टल पर दिया जाए कि कितने बेड हमारे अवेलेबल हैं और प्रतिदिन हमारे कितने ईडब्ल्यूएस मरीज का ओपीडी में इलाज हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री कैलाश गंगवाल जी(अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्रीमती पूनम शर्मा जी।

श्रीमती पूनम शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए खड़ी हुई हूं जो केवल एक नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं है बल्कि दिल्ली की आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ने का पवित्र संकल्प है। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की दिशा में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। यह भारत में सांस्कृतिक

पूर्ण जागरण का एक बड़ा अध्याय साबित होगा। अध्यक्ष जी यह शहर जिसे हम दिल्ली कहते हैं। इसका गौरवशाली इतिहास महाभारत से जुडा हुआ है। खुदाई के दौरान पुराने किले से निकले अवशेष पग-पग पर बिखरी हमारी विरासत इस बात की गवाह है कि यह वही भूमि है जहां धर्मराज ने धर्म की स्थापना की थी। दिल्ली शब्द तो बहुत बाद में आया है लेकिन, इंद्रप्रस्थ हमारी अस्तित्व का मूल आधार है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों होना चाहिए? इसके पीछे भी ठोस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तर्क है। इंद्रप्रस्थ नाम हमें गुलाम मानसिकता से मुक्त कर हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस युग की हमें याद दिलाता है। इंद्रप्रस्थ नाम होने से दिल्ली को विश्व स्तर पर एक नई और भव्य सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। अध्यक्ष जी रेखा गुप्ता सरकार का विज़न स्पष्ट है कि हम ऐसी विकसित दिल्ली बनाना चाहते हैं जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो लेकिन उसकी नींव हमारे सनातन गौरव धर्म पर टिकी हो। माननीय अध्यक्ष जी आज देश में कई शहरों में अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाम पुनः स्थापित किए गए हैं। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज और बॉम्बे को मुंबई और मद्रास को चेन्नई जैसे उनके ऐतिहासिक नामों से सांस्कृतिक गौरव और अधिक सुदृढ़ हुआ है। इसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय राजधानी का नाम भी प्राचीन और गौरवशाली पहचान के अनुरूप होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी महोदय इंद्रप्रस्थ नाम पहले से ही दिल्ली के अनेकों संस्थानों जैसे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन आईपी स्टेट में प्रचलित है। यह तो दर्शाता है कि इस नाम को समाज में व्यापक और स्वाभाविक प्रगति प्राप्त है। इंद्रप्रस्थ केवल एक नाम नहीं यह अनुशासन है, न्याय है, भव्यता है और सभ्यता का प्रतीक है। ऐसा ही एक प्रस्ताव हमारे माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने माननीय गृह मंत्री जी को भेजा हुआ है। अतः मैं आपसे इस सदन से मांग करती हूं कि दिल्ली को उसके वास्तविक नाम इंद्रप्रस्थ से अलंकृत किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने जड़ों से जुडने का काम हो और अपने आप पे हम लोग गर्व महसूस करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्रीमती शिखा रॉय।

श्रीमती शिखा रॉय: धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आपके समक्ष यहां खड़ी हुई हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहती हूं पोल्यूशन को लेकर के हमारी सरकार लगातार चिंता भी व्यक्त कर रही है और उसको ठीक करने के समाधान और साधन भी ढूंढ रही है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि ऐसी कुछ प्रयोजन रहते हैं जो सरकार के नित्य क्रम में या उसकी नित्य की देखरेख में नहीं आ पाते हैं। अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ा वर्ग है दिल्ली में जो वर्कशॉप्स के नाम पर खुलेआम सड़कों पर

कारों को धोने का डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है। यह बहुत बड़ा पोल्यूशन को क्रिएट करने का एक माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद खुलेआम में कारों की वर्कशॉप चलने को पूरी तरह से इसको चलने का प्रतिबंध है, यह नहीं चल सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर किसी भी चौराहे पर, किसी कोने पर, कोई खाली जगह देखकर, कोई शॉप में यह वर्कशॉप्स लगातार खुलेआम चल रही हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो सूर्यसेन मार्ग, एपीजे स्कूल रोड, केपीएस रोड, एस बैंड रोड, रविदास मार्ग इस पर 20-20, 25-25 गाड़ियां सड़क के ऊपर खड़ा करके उनको धोने का, पेंटिंग डेंटिंग या उनके ऊपर जो काम होता है उसका काम होता है। यह 20-25 गाड़ियां तो ठीक होने के लिए वहां खड़ी होती हैं और उनको ठीक करवाने आने वाले 20-25 और होते हैं। अध्यक्ष जी यह पानी कहां से लेते हैं, इनको कनेक्शन कैसे रेजिडेंशियल एरिया में इन वर्कशॉप्स में कारों को धोने का मिलता है, कोई जानकारी हमारे पास नहीं रहती है। यह बिजली के मीटर के कनेक्शंस कमर्शियल सड़क के ऊपर कैसे लेते हैं, कहां से आते हैं, इसकी भी जानकारी जब लेना चाहो तो नहीं मिल पाती है। अध्यक्ष जी, लगातार अपनी बात कहने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, डीएम ऑफिस में, एमसीडी ऑफिस में लगातार इस बात को कहती आई हूं, उठाती आई हूं लेकिन इन वर्कशॉप्स पे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रालय को निवेदन है कि इस तरह की चलती हुई खुले में कारों को धोने की डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप्स को बंद कराया जाए। यह पॉल्यूशन क्रिएट करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनती हैं और यह इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक अलग लोड करवाती हैं और जैम्स और कंजेशन अलग एक प्वाईंट बनता है इन के कारण। तो मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से इस विषय पर जरूर यह निवेदन करती हूं कि कोई ना कोई कार्यवाही की जाए और उसकी जानकारी भी हमें दी जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण मैं यह स्पष्ट कर दूं और अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि सदस्यों द्वारा 280 में जो मामला उठाया जाएगा वह प्रशासनिक व्यवस्था को सौंप दिया जाएगा चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से और उसका रिप्लाई मेंबर के पास आएगा उसके सॉल्यूशन के साथ। जिन माननीय सदस्यों को 280 के जो मुद्दे उठाते हैं उसको उसको उठाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आप उसमें पूरा मुद्दा दें जो आप क्षेत्र की या जो भी आपको बात कहनी है और जिससे कि अधिकारियों को यह स्पष्ट रहे कि

हमको इस पर क्या कार्यवाही करनी है और वो कार्यवाही करके आपको सूचित करेंगे और एक उसकी प्रति दिल्ली विधानसभा सचिव कार्यालय को भेजी जाएगी।

श्री राजकुमार भाटिया: मान्यवर, मैं इस विषय में मेरा सबमिशन है 280 के तहत जितने भी प्रश्न मैंने आज तक उठाए हैं, उसकी जानकारी तो पहुंचती है लेकिन समाधान की जानकारी नहीं पहुंचती है। कभी-कभी तो यह लिख दिया जाता है कि यह जानकारी हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। जब प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा लिख दिया जाता है कि यह जानकारी हमारे विभाग से संबंधित नहीं है तो who will take care of it?

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री राजकुमार भाटिया: मेरे पास ऐसी दर्जनों चिट्ठियां हैं जिसमें जो जैसे आरटीआई का जवाब आता है ना जी कि अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी बाद में होगा या इसमें जाइए officer should happy to inform all the time जी। काम करते समय खुशी-खुशी वो जानकारी दें जिससे उसका समाधान मिल सके मेरी प्रार्थना है आपसे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जो सदस्य रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है वो मुझे सूचित करें। उसके लिए व्यवस्था यह है कि जो हमारी क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी है जिसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर साहब करते हैं वो मैटर उनको सौंप दिया जाता है कमेटी को और कमेटी फिर उन अधिकारियों को बुलाती है और संबंधित सदस्य को आमंत्रित किया जाता है विशेष आमंत्रण उस बैठक में और वहां फिर वह उसका समाधान किया जाता है, यह प्रक्रिया है।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: अध्यक्ष जी, इसमें एक और मैं धन्यवाद करूंगा लवली जी ने भी अरविंदर सिंह जी ने भी उठाया मैटर को और नहीं हमारे मारवाह जी ने, राजकुमार जी ने भी इसको रिपीट किया। इसमें यह बहुत ही टेक्निकलटी से क्या करते हैं सपोज हमारा कोई हमने मैटर उठाए और उस मंत्रालय से संबंधित मैटर को जब हम यहां पर सदन में रेज करते हैं तो उसमें से गलती से अगर कोई किसी और विभाग का अगर उसमें लाइन जुड़ गई तो वह तीन मैटर जो उनके विभाग से संबंधित है, उसको छोड़कर उस आखिरी लाइन का जवाब दे देते हैं कि यह जो मैटर है यह हमारे उससे संबंधित नहीं है और वो हमारा बोलना, हमारा टाइम लेना, पूरे सदन का टाइम खराब करना और अधिकारी उसका जवाब देने से बचते हैं तो इसमें आपसे आग्रह यह है कि आप इस पर जरा गंभीरता से संज्ञान लें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक और स्पष्ट कर दूं जब आप 280 का जो आप विशेष उल्लेख लिखते हैं उसको क्वेश्चन फॉर्म में ना लिखें। उसमें आप सीधा अपना विषय रखें, अपनी

समस्या रखें। जो आप महसूस कर रहे हैं। मान लो पानी की दिक्कत आपको लगती है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई सीवर का कोई विषय है तो आप वह विषय उसमें उसकी व्याख्या उसको एक जानकारी के तौर पर उस पर लिखें। जब हम उसको 280 को अधिकारियों के पास भेजते हैं तो अधिकारियों को यह निर्देश है अध्यक्ष के कार्यालय से कि आपको इसका समाधान करके और समाधान की प्रक्रिया बताकर सदस्यों को सूचित करना है। इसका यानि कि रिप्लाई करना है। वह क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा, एक बात। वो जिस भी फॉर्म में है उसमें बात स्पष्ट होनी चाहिए। उसका समाधान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और समाधान करके सूचित करना या समाधान की प्रक्रिया जो अडॉप्ट की गई है उसकी जानकारी देना यह मैंडेटरी है। अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा, सूचना नहीं आ रही, प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिल रही है तो आप इस मैटर को अध्यक्ष को जानकारी दे सकते हैं कि मेरे 280 का रिप्लाई नहीं आया है। एक मिनट हम उस मैटर को अधिकारियों से पूछेंगे, करेंगे, नहीं तो फिर वह क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी को सौंप दिया जाएगा। आगे की कार्यवाही हमारे डिप्टी स्पीकर साहब बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। इसमें मैं चाहूंगा वह बताएं कि वह क्या जो हम आपको भेजते हैं तो आप उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष जी, यह विधानसभा की इस प्रक्रिया के तहत बहुत लंबे समय के बाद आपके माध्यम से क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी को और मेंबर्स की समस्याओं को पावरफुल बनाने के लिए आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैंने कभी ऐसा इस सदन के अंदर नहीं देखा कि 280 लगा हो, 280 का जवाब ठीक ढंग से अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया हो और आपके माध्यम से पिछले दिनों के अंतर्गत अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया रहा, जो अधिकारी खुद हाउस में यहां कमेटी के सामने पेश नहीं होते थे, एक पत्र चीफ सेक्रेटरी को आपके माध्यम से दिया गया और यही नहीं, उस कमेटी को पावरफुल बनाने के लिए जो काम आपने किया है वास्तव में अपने आप में अलग है लेकिन मैं मेंबरानों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, कमेटी का तब फंक्शन सफल होगा जब कमेटी के मेंबरान उस मीटिंग में पहुंचेंगे क्वेश्चन एंड रेफरेंस में। कई बार बहुत सी ऐसी स्थितियां बनती हैं अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूं हर कमेटी का महत्व को सबको समझना चाहिए। जो मेंबर उस कमेटी के सदस्य हैं उनको जरूर पहुंचना चाहिए। यह मेरे आपके माध्यम से निवेदन है और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपने जो शक्तिशाली एक क्वेश्चन रेफरेंस कमेटी बनाई है वास्तव में हम अधिकारी को इसके लिए बाउंड करेंगे, अधिकारी उसका जवाब देगा, उसका समस्याओं का समाधान होगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक बात मैं माननीय सदस्यगण आपको सूचित कर दूं कि मुझे डिप्टी स्पीकर महोदय ने जानकारी दी थी इस सारे विषय की। उस विषय को हमने फिर मुख्य सचिव को भेजा था। मुझे खुशी इस बात की है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसमें स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कमेटी की कोई भी रेफरेंस जो है उस पर तुरंत हमें रिप्लाई करना है और उसके कारण फिर चीजों में काफी सुधार हुआ है और हम इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी साहब के प्राम्प्ट सेंसिटिव इशू पर कार्यवाही करने पर भी उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। अभी जो विषय यहां पर आ रहा है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि अभी भी पिछले सदन के जो बैठकें थी उसके 280 के कई मैटर जिनके रिप्लाई पेंडिंग है। थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैठकों में आएं। यह बैठकें, यह कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह कमेटियां ही इस हाउस की ताकत हैं। हाउस के बैठने का समय और दिन सीमित होते हैं। लेकिन जब हाउस नहीं होता तो कमेटियां ही हाउस की तरह काम करती हैं। यह आपको मैं स्पष्ट कर दूं जो संवैधानिक व्यवस्था है यह जो कमेटी है यह एक तरह से हाउस द्वारा उनको यह काम दिया गया है और वह हाउस के बिहाफ पर वहां पर इन बैठकों में निर्णय होते हैं, चर्चाएं होती हैं, रिपोर्ट बनती हैं। और वह फिर सदन के सामने आती है। अगर कमेटी की बैठक ही नहीं होगी या होगी तो सदस्य नहीं होगा, सदस्य होगा तो अधिकारी का reply नहीं आएगा, अधिकारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकार है सदन का वो क्षीण होता है तो इसलिए इसमें एक तो हमारा कई बार 280 की फॉर्म ऐसी होती है कि सामने वाले को भी लगता है कि इस पर कैसे reply बनाए। वो भी आप देख ले कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो बहुत जरूरी नहीं है, 10 पेज, पांच पेज, सिर्फ आधा पेज में आप मुख्य रूप से उसको लिख दे। समस्या को अपने विषय को, अपनी बात को, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सीधा वो होना चाहिए जिससे कि उस पर reply आए और उसमें कोई दुविधा ना रहे। अब मैं हम एक मिनट एक मिनट एक मिनट।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, जो आपने चेयरमैनी बनाई थी, अभी तक कमरों की व्यवस्था नहीं हुई है। एक साल हो गया है।

माननीय अध्यक्ष: वो हो रहा है सब। अभी मार्च में भी मिलेंगे हमें, अप्रैल में कर देंगे व्यवस्था। अब बोलो दूसरा आज

श्री हरीश खुराना: एक निवेदन और है कि जो 10 होने के बाद अगर टाइम होता है तो एक लिस्ट जो होती है स्टैंड बाय वाली वो भी अगर जारी हो जाए तो पता लग जाए।

माननीय अध्यक्ष: कौन सा?

श्री हरीश खुराना: 10 के बाद अगर टाइम होता है तो स्टैंड बाय का जो स्पीकर्स है 280 के...

माननीय अध्यक्ष: देखिए, मैं आज चूंकि काफी बातें यहाँ हो रही है। मैं नाम पढ़ देता हूँ जो 10 के बाद जिन पांच लोगों का ड्रॉ में नाम है और वही बोलेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल, ग्यारहवें नंबर पे है, बारहवें नंबर पर माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट, तेरहवें नंबर पर माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना, 14 नंबर पे चौदहवें नंबर पे माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा, पंद्रहवें नंबर पर माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी।

श्री जितेन्द्र महाजन: अभी दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है और लोगों की हमसे अपेक्षाएं खूब है। तो मेरा निवेदन ये है कि पहले अनुभव ये आया है कि हम एमसीडी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई जानकारी मांगते हैं, वो हमें नहीं मिलती। इसी प्रकार डीडीए से और पुलिस से भी हमें जानकारी नहीं मिलती। मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो इन विभागों को भी जवाबदेही तय की जाए कि उस सदन द्वारा मांगी गई जानकारी को दे।

माननीय अध्यक्ष: अभी देखिये जो इस सदन का अधिकार क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाले हर विषय पर आपको जानकारी दी जाएगी। नगर निगम पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है और उसको और चुस्त दुरुस्त कर देंगे और उसमें और जो भी बेस्ट संभव होगा उसको जरूर करेंगे। अब माननीय सदस्य श्री वीर सिंह धिंगान (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह नेगी।

<u>विशेष उल्लेख(नियम-280).....जारी</u>

श्री रविन्द्र सिंह नेगी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय अपनी पटपड़गंज विधानसभा का लाया हूँ जो रोज़मर्रा के जीवन में लोगों के हैं, अतिक्रमण का मामला। अतिक्रमण इन्क्रोचमेंट जो रेहडी पटरी और शाम को गाड़ियों का जाम मेरे यहाँ श्री राम चौक है, जो कम से कम ढाई लाख आबादी का उसका रास्ता है श्रीराम चौक से नालंदा चौक और मंडावली गांव। ये रास्ता है पूरा शाम के टाइम यहाँ जाम रहता है और जिसकी वजह से वहाँ कई सारी एम्बुलेंस फंस जाती है और अभी हाल में एक साल के अन्दर वहाँ तीन, तीन मौत हो चुकी है एम्बुलेंस के अंदर। क्योंकि रास्ता मिलता नहीं है इसलिए

वहाँ मौत हो चुकी है। नगर निगम हमारे पास है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरा है सद्भावना चौक मंडावली। ये गवर्नमेंट स्कूल वेस्ट विनोद नगर से सद्भावना चौक यहाँ भी जाम की समस्या है। बड़ी भयंकर है। यहाँ भी लोग निकल नहीं पाते। बड़े लोग परेशान है और उसके बाद सुपर साइंस चौक। ईस्ट विनोद नगर मयूर विहार फेस टू। ये ये भी कई वर्षों से समस्या है। यहाँ भी जाम की समस्या है, जिसके वजह से एम्बुलेंस फंस जाती है। यहाँ भी तीन चार मौतें हो चुकी है अभी एक साल के अंतर्गत बड़ा गंभीर मामला है ये। और उसके बाद आचार्य निकेतन, आचार्य, निकेतन, फाइन होम ये भी बहुत जाम की समस्या है और यहाँ पे पटपडगंज गांव है जो हमारी धरोहर है, पटपडगंज गांव का रास्ता है जहां आबादी है वो जाने का रास्ता मिलता नहीं है लोगों को यहाँ भी बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ एनकॉन स्कूल है एलकॉन सीनियर सेकेंडरी और एलकॉन इंटरनेशनल। इन स्कूलों का आतंक है इनकी 40-40, 50-50 बसें ये बाहर खड़ी करते हैं स्कूल के टाइम पे छुट्टी के टाइम पे जिसके वजह से वहाँ पे जाम लगता है और लोग निकल नहीं पाते और बहुत अप्रिय घटनाएं वहाँ आए दिन होती रहती है इन स्कूलों के आगे। खिचड़ीपुर गांव खिचड़ीपुर गांव का जो मेन रोड है, उसमें भी जाम की समस्या बड़ी भयंकर समस्या है। खिचड़ीपुर 6,7,8 ब्लॉक टी कैंप यहाँ भी जाम की समस्या है। ऐसी बहुत गंभीर है समस्या जाम की है । मेरा निवेदन है आपसे ट्रिपल इंजन की सरकार में हम बैठे हैं। एमसीडी की जवाबदेही तय हो और वो बताएं कि इस पर क्या काम कर रहे हैं। ये मुद्दा पहले भी हमने उठाया था पर इसमें कोई जवाब हमारे पास आज तक नहीं आया। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को हल करा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सदस्य: माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत।

श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रख रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जी के संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूँ। दिल्ली में रया राजपूत वर्ग को दिल्ली की ओबीसी सूची में आरक्षण हेतु सूचीबद्ध किया हुआ है। इस सूची के क्रमांक 50 में यह रया तंवर के नाम से सूचीबद्ध है। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रिया तंवर, रया, राजपूत, रवा राजपूत यह एक ही समुदाय है। जैन आयोग ने इन समुदाय की समान पहचान को इंगित करते हुए इनको एक ही समुदाय के रूप में ओबीसी सूची में शामिल करने का समर्थन किया था। दिल्ली राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में 1908, 1909 के निपटारे में इन समुदायों का दिल्ली में ऐतिहासिक रूप से निवास को भी प्रमाणित किया था। इन समुदाय में विभिन्न गोत्र आते हैं। अध्यक्ष जी,

जैसे अन्य ओबीसी समुदायों को केवल एक नाम से सूचीबद्ध करके इस समुदाय में उनके सभी गोत्र आते हैं। इस प्रकार रया राजपूत, रवा राजपूत और रया तंवर इन विभिन्न गोत्र एक ही समुदाय से हैं। अध्यक्ष जी कई सालों से यह मामला पेंडिंग है। पहले भी समय समय पर इसके बारे में आवाज उठाई गई। बहुत सारे युवक और युवतियों इस सुविधा से वंचित है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची क्रमांक 50 पर शामिल रया तंवर को रया राजपूत, रवा राजपूत एक ही समान समुदाय के रूप में मानते हुए इसके लिए एक संशोधन आदेश पत्र जारी करें। आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया, अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजकरण खत्री।

श्री राजकरण खत्री: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में बस शेल्टर स्टैंड की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह समस्या आम जनता विशेषकर विद्यार्थियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए काफी परेशानी का कारण बन रही है। बारिश, धूप और ठंड के मौसम में यात्रियों को खुले में इंतजार करना पड़ता है। कई प्रमुख स्थानों पर अब तक बस शेल्टर का निर्माण नहीं हो पाया है। आपसे इनसे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों प्रभावित हो रही है। जनता द्वारा इस विषय पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल कराया जाए और नए बस शेल्टर स्टैंड बनवाए जाए। हमारे क्षेत्र में कई जगह बस शेल्टर है ही नहीं और जहाँ है वहाँ बहुत ही जर्जर और टूटी फूटी हालत में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंत्री जी के द्वारा इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री गजेंद्र दराल।

श्री गजेन्द्र दराल: धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जिस विषय को 280 के तहत सदन के मध्य रखना चाहता हूँ। उसमें मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व में हमारे बीच में सांसद आदरणीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी और नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली देहात को एक नई लाइफ लाइन देकर यूईआर-टू के रूप में जिस तरीके से दिल्ली देहात को एक सौगात दी वो सौगात मेरी दिल्ली देहात को एक नए विकास की गति और आर्थिक तौर पर मजबूत करने की गति है। मैं आज सड़क मंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि इस

नई लाइफ लाइन को जब धरातल पर उतारा गया और जब इसको हमने यूज करना शुरू किया तो उसमें एक दो खामियां जो एलिवेटेड रोड के नीचे जब हम रोहतक रोड से जीटी करनाल रोड के लिए चलते हैं तो इसमें सबसे पहला कट रसूलपुर गांव से मुंडका वाले रोड का पड़ता है। जिसमें गाड़ियां लगभग 80-90 की स्पीड से जब नीचे उतरती हैं तो एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा डर रहता है और अक्सर दो-तीन दिन में कोई ना कोई वहां पर एक्सीडेंट हो भी जाता है। इस यूईआर-टू का मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग साढ़े 11 कि.मी. का एरिया है। जिसके अंदर सबसे पहला कट है रसूलपुर से मुंडका। उसके बाद दूसरा जो कट है वो है रसूलपुर से घेवरा गांव और जो तीसरा कट है वो रानीखेड़ा से कंझावला-टू नरेला रोड। उसके बाद मदनपुर गांव से कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया और उसके बाद मुंडका से कराला रोड और उससे आगे चलकर जो मजरी गांव से रामा विहार के लिए जाता है। तो एक तो मेरा ये निवेदन है कि इन सभी फ्लाई ओवर के जो नीचे जो कट हैं उनके ऊपर एनएचएआई को सूचित करके और स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं ताकि कि वहां पर जो मेरे किसानों को, क्योंकि इस यूईआर-टू के दोनों तरफ किसानों की जमीन बची हुई है। किसानों को अपने खेतों में भी जाना होता है और वहां बड़ा डर लगता है कि अचानक कोई गाड़ी ना आ जाए। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि जब हमारी दिल्ली देहात को ये नई लाइफ लाइन दी है तो जितने भी गांव के अप्रोच रोड हैं वो लगभग सभी रोड दो गट्ठे के यानी कि साढ़े 16 फुट के रोड हैं और वो रोड अगर 50 फुट से लेकर 100 फुट तक कर दिए जाएं तो हर गांव को इस हाईवे से जुड़ने का इस यूईआर- टू से जुडने का एक नया माध्यम भी मिलेगा और जितने अनेकों दूसरे रोड हैं उन पे यातायात भी कम होगा। तो मैं आज सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो एनएचआई को ये गाइडलाइन जारी करके इन पर सभी पर स्पीड ब्रेक्कर और साथ में अगर इन सभी रोडों को चौड़ा कर दिया जाए तो मेरी दिल्ली देहात को बहुत फायदा मिलेगा। आपका आपने मुझे मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉ. अनिल गोयल।

श्री डॉ0 अनिल गोयल, माननीय सदस्य: बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसे विषय बेसहारा गाय जो सड़कों पर घूम रही हैं उनके विषय में आपका ध्यान मंत्री जी की तरफ और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस विषय में माननीय सदस्य अशोक गोयल जी ने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल पिछली विधानसभा में पेश किया था। उसके आगे की कार्रवाई के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। कृष्णा नगर विधानसभा में विशेष रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पंडित

पार्क है, पटपडगंज रोड है, चंदनगर रोड है, चंदनगर से पुरी लिंक रोड है और बहुत सारे मेन मार्केट जो कृष्णा नगर के हैं जैसे हमारे लाल क्वाटर रोड है या सोम बाजार रोड है। इन सब पर कुछ सहारा और कुछ बेसहारा दोनों किस्म की गायों की समस्या थी अतिगंभीर हो चुकी है। और ये दिन आए दिन अखबारों की सुर्खियां भी बनती हैं। जैसे कि आज के हिंदी अखबार में भी एक विशेष खबर है जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी हुई हैं। ये समस्या बेसहारा गाय कुछ पशुपालक भी अपनी गाय का दूध निकालने के बाद उनको सड़कों पर लावारिश छोड़ देते हैं अध्यक्ष जी। ये पशु दिन भर सड़कों पर घूमते हैं। ना केवल यातायात को बाधित करते हैं बल्कि सड़क दुर्घटनाएं और स्थानीय नागरिकों को चोट का कारण भी बनते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष जी सड़कों पर फैले गाय के गोबर, मूत्र के कारण क्षेत्र में गंदगी विशेष रूप से जो मेन मार्केट्स हैं उनमें बदबू का, गंदगी का माहौल रहता है। जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा ये भूखी गाय अक्सर हम लोगों ने देखा कि सड़कों पर पड़े हुए प्लास्टिक को भी खाती हैं जो उनके जीवन के लिए भी घातक हो रहा है। जब-जब एमसीडी के सरकारी अधिकारी उनके एसी, डीसी, उनके वेटनरी ऑफिसर्स ये बात करते हैं तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी करते हैं, ट्रकों की कमी करते हैं। एक ट्रक ले जाता है, छह गाय ले जाता है पूरे दिन। इस प्रकार से सैकड़ों गायों का समाधान इसको रेस्क्यू करने में ये असमर्थ दिखाई दे रही हैं या ये करना नहीं चाहती। इस संबंध में सख्त कानून बनाने और गायों को आवासीय क्षेत्र से हटाने की मांग की गई थी। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर जिले में गौशाला बनाने की योजना बनाई गई है। इससे युद्ध स्तर पर मेरा अनुरोध है कि दिल्ली में और मेरी विधानसभा में भी लागू किया जाए। हमने डीडीए को भी अध्यक्ष जी लिखा बहुत सारी खाली जमीन जो उनकी एनक्रोज्ड है उस पर डीडीए के अधिकारियों के कान पर कोई जू नहीं रेंगती और हमने लिखकर भी दिया डीएम को की ये जगह खाली है डीडीए की है या एमसीडी की है गौशाला बनाई जा सकती है इस संबंध में कुछ भी आज तक नहीं हुआ। अध्यक्ष जी मेरा आपसे आग्रह है कि डीडीए हो या एमसीडी दिल्ली सरकार की जमीन पर गौशाला बनाकर और हमारे बहुत सारे एनजीओ इसको संचालन के लिए भी तैयार हैं। पीपीपी मॉडल पर ये चलाया जा सकता है। एक इसके लिए रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए अलग से एसटीएफ का गठन हो। पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने, व्यक्तियों पर भी दंडात्मक कार्यवाही हो और जो गोबर है जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में कहा कि 1500 टन जो गोबर निकलता है वो बायोगैस प्लांट तक पहुंचाने की हमारी विधानसभा से भी व्यवस्था हो। एमसीडी के जरूर मैं कहना चाहता हूं संबंधित अधिकारी विशेष रूप से वेटनरी ऑफिसर एसी और डीसी की भी जवाबदेही इसमें तय हो और इन पर कोताही

बरती जाए इन पर तो कार्रवाई का भी प्रावधान हो। मेरा आग्रह है कि जनहित और पशु कल्याण को देखते हुए इस समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाए और ये पीपीपी मॉडल भी दिल्ली में लागू किया जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य एवं उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी आपने जो मुझे 280 के तहत मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद के एक गंभीर समस्याओं की ओर अपनी बात को कहने के लिए जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र एसी-69 में अवैध रूप से संचालित बैटरी व ई-कचरा गोदामों के कारण क्षेत्रवासी भयभीत हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों के अंतर्गत नेहरू विहार में मकान संख्या 18/4 एक गोदाम में आग लगने से ये घटना घटी। सर इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और दूसरा घायल हो जाता है। यही नहीं वहां पे वाहनों में आग लग जाता है। कई घंटों के बाद उस पर काबू किया गया। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। प्रदूषण विभाग वाले कहते हैं कि साहब वहां तो कोई घटना नहीं घटी। मैं एक एफआईआर की कॉपी भी लेके आया हूं। अध्यक्ष महोदय उसमें एफआईआर दर्ज की गई और साफ तौर से कहा गया कि इस मकान के अंदर आग लगेगा क्योंकि अवैध कबाड़ के गोदाम हैं और यही नहीं वहां पे लगातार मैं इस प्रकार की बातों को लेकर के अधिकारियों को पत्र भी देता हूं। उनको बार-बार भी कहा जाता है लेकिन उनका नकारात्मक रवैया रहा। अध्यक्ष महोदय ऐसे अवैध गोदाम जैसी फैक्ट्रियां जहां ई-कबाड़ का कार्य चल रहा हो इन पर रोक लगानी चाहिए जिससे कि लोगों का पलायन भी ना हो और लोग अपने क्षेत्र में ठीक ढंग से जी सकें ये मेरा माध्यम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। गली 15 फीट की है। कबाड़ की दुकानों की वजह से, कबाड़ के गोदामों की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे जो 25 गज के अंदर 5-5, 6-6 मंजिले मकान बनाए गए हैं और वहां रहने वाले की लोगों की स्थिति ये है ना तो उनको बिजली मिलेगी, ना उनको पानी मिलेगा, ना वो ठीक ढंग से सुरक्षित रह सकेंगे। वहां से बहुत ही विस्तृत रूप में लोगों का पलायन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इन फैक्ट्रियों अवैध रूप से जो खुली हैं पर्यावरण विभाग के माध्यम से इन पे कारवाई की जाए और जिससे कि ये फैक्ट्री और गोदाम उन एरियाओं के ना अंदर ना चले, ये मेरा आपसे निवेदन है और निवेदन ही नहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि तुरंत इनको सील की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद,नमस्कार।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: इससे पहले कि कार्रवाई आगे बढ़े। हमारे बीच में हमारे एक वरिष्ठ माननीय सदस्य उनका जन्मदिन है, वो मैं इंतजार कर रहा था कि वो आ जाए। लेकिन प्रारंभ में ही जन्मदिन की बधाई दी जाती है। तो मैं, आज माननीय सदस्य- श्री राजकुमार चौहान जी का जन्मदिन हैं, मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि वे अपने व्यक्तिगत और तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और उनके गहन राजनीतिक अनुभव का लाभ हमें सदैव मिलता रहे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ ये बधाई संदेश हम श्री राजकुमार चौहान जी को सदन के बिहाफ पर उनको भेजेंगे भी। अब....

....व्यवधान....

श्री राज कुमार भाटिया: अध्यक्ष जी, जो सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं उनकी तरफ से पार्टी का इंतजाम होना चाहिए, रहते तो शुभकामनाएं लेते, नहीं तो बाकी सब की और पार्टी मिलनी चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): बिलकुल ठीक बात है। माननीय सदस्य- श्री हरीश खुराना जी।

श्री हरीश खुराना: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरी मोती नगर विधानसभा के अंदर और दिल्ली के अंदर आवारा कुत्तों के काटने से जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, इन कुत्तों के काटने की वजह से बुजुर्गों पर, महिलाओं पर और महिलाओं पर और बच्चों पर सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है अध्यक्ष जी। सो सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी संख्या नियंत्रण पर, नसबंदी पर एवं जो आक्रामक कुत्ते हैं उनकी पहचान कर के.. ठोस कदम उठाए जाएं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मोती नगर विधानसभा के अंदर जो हाई रिस्क एरियाज हैं जहाँ पर, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो पार्क हों, ऐसी जगह को चिन्हित कर कर वहाँ पर विशेष कोई इंतजाम किए जाएं। एक एसओपी क्रिएट किए जाए ताकि जो ये कुत्तों की समस्या बढ़ रही है उसपे तुरंत एक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे, क्योंकि एक बार घोषणा भी हुई थी कि डॉग शेल्टर्स बनाए जाएंगे, इसपे भी तुरंत थोड़ा कार्रवाई जल्दी हो ताकि जो एक समस्या बढ़ रही है और जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाया जाए। बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): माननीय सदस्य- श्री कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे विशेष उल्लेख के तहत अवसर दिया, बहुत-बहुत आभार आपका। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक लंबे अरसे से और पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी के कारण दिल्ली में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं की संख्या भी बड़ी हैं, ट्रैफिक की भी संख्या बढ़ गई हैं और सड़कों का आकार उतना ही है। और दिल्ली में जो कार्य औसत हैं, पहले एक व्यक्ति एक दिन में चार कार्य करता था तो आज उसकी औसत एक कार्य की है। ये बहुत भयावह स्थिति बन चुकी है दिल्ली की। और अक्सर देखते होंगे आप कोई भी एक गाड़ी खराब हो गई सड़क पे और वो सड़क पे ही गाड़ी रिपेयर करना शुरू कर देता है। उसका बोनट उठाया या वो थ्री व्हीलर है, मालवाहक है। ऐसी कोई क्रेनो की व्यवस्था नहीं कि वो उसको उठाया, साइड में कर दिया ताकि बाकी ट्रैफिक में बाधा ना आए। और घंटों-घंटों लोग फंसे रहते हैं। इससे हमारा तेल भी ज्यादा खर्च होता है, हमारा समय तो खर्च होता ही है और दिल्ली का प्रत्येक नागरिक तनाव में, बीपी बढ़ा होता है उसका। तो ये बहुत बड़ा, एक बड़ी समस्या है दिल्ली की, इसपे हम सबको मिलकर के इसकी एक पूरी बड़ी व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। और नई सड़कें हम कैसे बनाएं? प्रत्येक 10 किलोमीटर पर किसी कंपनी को हम वो सड़क दे दे और सड़क देने के बाद उसके एक क्रेन की व्यवस्था भी हो ताकि कोई भी गाड़ी अचानक खराब हो जाती, किसी की भी गाड़ी साहब खराब हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट है तो तुरंत प्रभाव से उस गाड़ी को वहाँ से उठा करके एक साइड में करके, चाहे वो एक्सीडेंट भी हो उसमें, खराबी भी हो तकनीकी, तो उसको एक तरफ करके ताकि बाकी लोग उसके कारण से तनाव में न आए, उसका सफर समय से पूरा हो, तो इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। नई सड़कें हम कैसे और बना सकते हैं।

उसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय कार पार्किंग। अब कुछ लोग सड़कों पे, मुख्य सड़कों पे बाजार लग रहे हैं, रिंग रोड- प्रीतमपुरा पे बाजार लगता है संडे का। उसका क्या मतलब हुआ अध्यक्ष जी वहां बाजार लगने का? अगर वहाँ बाजार लगेगा तो जाम तो होगा। तो लोगों की चिंता कम है हमें, आम लोगों की और ऐसे बाजार वालों को एक दूसरा विकल्प देना चाहिए। और उसके अलावा अध्यक्ष महोदय सड़कों पर कार पार्किंग हो रही हैं, चाहे वो राजौरी गार्डन भी हो, चाहे वो पीरागढ़ी भी हो। आप, दिल्ली के हर एक हिस्से में ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। तो कारों की पार्किंग मुख्य सड़कों पर न हो, सड़क चलने के लिए हैं। सड़कों पर यातायात चले, ट्रैफिक चले बिना बाधा के चले, लोग सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसको एक फीलिंग आये कि दिल्ली में हैं। एक प्रवर्तनकारी सरकार आई है और दिल्ली में

दिल्ली के लोगों की सरकार है। हमको इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि लोगों का आवागमन बेहतर हो।

उसके अलावा अध्यक्ष महोदय नए और पुल कैसे बनाया जाए? जो पुराने पुल बनाए गए और डिजाइन किए गए थे वो पुलें ही भर जाती हैं सड़कें। उन पुलों पर चढ़ना ही अब तो जोखिम हो जाता है। अभी आप देखते होंगे कभी भी बाईपास जाओगे तो बाईपास पे ही आधा घंटा लग जाता है उस पुल पर चढ़ने में। इसी प्रकार का पीरागढ़ी का विषय था, ऐसे देखने को बहुत, मधुबन चौक चलो कुछ ठीक हुआ है पहले से। सड़कों का डिजाइन जो है वो बहुत खराब है। जो दिल्ली के लोगों ने पहले नाले बनाए, नाले बनाने थे बाउंडरी वाल के साथ, बीच में नाला बना दिया, सर्विस लेन लोग ब्लॉक करके उसको एन्जॉय कर रहे हैं। आपके यहाँ मधुबन चौक रोड से और रिठाला तक मेट्रो स्टेशन तक वो डिजाइन गलत कर दिया। दुकानदार 20-20, 30-30 फुट की सड़क, मुख्य सड़क उसके ऊपर एन्जॉय कर रहे हैं। वो सड़क काम में आनी थी वो नाकाम हो गई। तो डिजाइन कौन करता है, उस डिजाइन पे भी चिंता करनी चाहिए। और पुलों से अतिक्रमण और जो सड़कों से अतिक्रमण भी हटे। और हम दिल्ली को नई सड़कें कैसे दें, कौन सी सड़क है और कहाँ बना सकते हैं, जैसे मैं बधाई देता हूँ अभी जो सिंचाई विभाग मंत्री को कि जिन्होंने नजफगढ़ नाले की तरफ दोनों तरफ इस बजट में प्रावधान किया गया कि दोनों तरफ हम सड़क बनाएंगे। ऐसे ही रोहिणी के अंदर सप्लीमेंटरी ड्रेन है, जो आपकी विधानसभा रोहिणी से प्रारंभ होती है रिंग रोड से और वो जाती है नजफगढ़- नांगलोई ड्रेन तक, पश्चिम विहार होते हुए नांगलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रिठाला, बड़ी ड्रेन है और उसको भी एलिवेटेड रोड अगर हम बना दे तो निश्चित रूप से एक उत्तर पश्चिमी जिले के अंदर काफी लोगों को लाभ मिलेगा, रिंग रोड पे दबाव कम पड़ेगा। और एक बार मैंने उपराज्यपाल महोदय से इस विषय में बात भी की तो उन्होंने, उनके अधिकारियों ने बताया कि बारापुल्ला में पानी की निकासी की चिंता हो गयी, वो दिक्कत है। डिजाइन ऐसे करो कि पानी का बहाव भी ठीक ढंग से बहे और पिल्लर के साइड में अपने दोनों तरफ डबल पिलर बन जाएं और पुल भी बन जाएं, ट्रैफिक भी जाए, पानी भी आराम से जाए। तो ये गलती कहीं हो गई तो उसके बाद उस काम पे विश्राम नहीं लग सकता। उस पर दिमाग कैसे लगाए, डिजाइन कैसे करें ताकि दोनों काम हो। हेलिकॉप्टर उड़ते हैं, गिरते हैं, कितने नेता हमारे मारे गए, लेकिन हेलिकॉप्टर तो उड़ते हैं, बंद नहीं किएं। हमारा एक ट्रेंड बन चुका है दिल्ली में या देश भर में किसी भी एक योजना में त्रुटि आ जाए उसकी जांच नहीं करेंगे, इसमें कौन दोषी हैं, उस तक नहीं पहुँचेंगे, योजना बंद कर दी जाती है।

इसी प्रकार से स्कूलों के आवंटन था, अस्पतालों के स्कूलों का आवंटन था भूमि का, उसको भी एक बार किसी ने स्कैंडल किया, बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कम्युनिटी हॉल भी दिल्ली में जो ना हम नहीं देंगे बनाएंगे डीडीए वाले। कुछ भी, कोई भी एक घटना होती है, बंद कर देते हैं। तो पूरा मूल्यांकन करके और दिल्ली के पूरे ट्रैफिक पे एक रोड मैप बनना चाहिए। जिस प्रकार से ड्रेनेज का रोड प्लान बनाया है, मैप, रोडमैप बनाया है, उसी प्रकार से दिल्ली के ट्रैफिक का भी एक रोडमैप बने ताकि सुगमता से दिल्ली के लोगों को आवाजाही में सहूलियत मिले ऐसा मेरा सुझाव है सदन के माध्यम से आपको और सरकार को आपके द्वारा और सरकार इस पर संज्ञान लेगी तो निरंतर दिल्ली के लोगों का जीवन बेहतर होगा। आपने मुझे समय दिया आत्मिक रूप से आपका बहुत- बहुत आभार। भारत माता की जय।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): माननीय सदस्य- श्रीमती नीलम पहलवान जी। बहुत शार्ट में करना है।

श्रीमती नीलम पहलवान: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का तथा माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। दिनांक 23 दिसंबर, 2025 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा डेम्स को हटाने का जो निर्णय लिया गया है उसके परिणामस्वरूप दिल्ली की क्लस्टर बसों में कार्यरत लगभग 6 से 7 हजार कर्मचारी, जैसे संभाग टिकट चेकर और ऑफिसर स्टाफ का रोजगार पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। जिससे लगभग 800 से 1000 कर्मचारी मेरी नजफगढ़ विधानसभा से भी आते हैं। यह सभी कर्मचारी वर्ष 2011 से लगातार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, जिसमें से अधिकांश कर्मचारी दिल्ली के ग्रामीण परिवेश से आते हैं। भले इन कर्मचारियों की नियुक्त अनुबंध के आधार पर हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये लोग दिल्ली की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। टिकटिंग, किराया संग्रह, यात्री सेवा संचालन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के माध्यम से होते हैं। लेकिन 31 मार्च, 2026 को अनुबंध समाप्त करने के निर्णय ने इन कर्मचारियों के रोजगार, संरक्षण एवं भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट नीति और दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इससे हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। महोदय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, राजघाट, सुनहरी पुला, कंझावला, दिचाऊकला और बीबीएम जैसे से कई डिपो पहले ही बंद किये जा चुके हैं। इसके कारण हजारों कर्मचारी पहले से ही बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए इस विभाग में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं जिनके परिवार की रोज़ी रोटी इसी रोजगार

पर टिकी हुई है। इनका रोजगार अचानक समाप्त हो जाता है और उनकी आयु सीमा और कहीं भी अप्लाई करने के लिए निकली जा चुकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील करती हूँ कि उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर जो असर पड़ेगा। इनमें अधिकांश कर्मचारी 40 से अधिक आयु वर्ग के हैं। अध्यक्ष जी, यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है अपितु यह हजारों परिवारों की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ विषय है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि डिम्स के सभी कर्मचारियों और संवाहकों के लिए रोजगार संरक्षण की स्पष्ट नीति तत्काल बनाई जाए। इन सभी कर्मचारियों को दिल्ली परिवहन निगम या अन्य ऑपरेटर एजेंसियों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवा अवधि एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत अवसर प्रदान किया जाए। जिन कर्मचारियों के एरियर व बोनस लंबे समय से बकाया है उन्हें शीघ्र नियमानुसार दिलवाए जाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए हजारों कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस सदन के समक्ष एक ऐसे मुद्दे बोरवेल सबमर्सिबल जो की दिल्ली में सरकार का perception को खराब कर रहा है। दो तरह के, एक वैध बोरवेल और एक अवैध बोरवेल, वैध बोरवेल वो है जैसे कार वाशिंग सेंटर है, आपके कार सर्विस सेंटर है, होटल हैं या बड़े-बड़े प्रतिष्ठान हैं जो की पैसे देते हैं मंथली और पैसे देकर उनके बोरवेल खुलेआम दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी संख्या मैं समझता हूँ कम से कम भी 50,000 की संख्या होगी। ऐसे बोरवेल जो की पानी का जल का भूजल का दोहन कर रहे हैं और वो पैसे देकर वैध हो जाते हैं। लेकिन एक जब घर एक जो है निवासी अपने घर को बनाने के लिए क्योंकि पानी हम दे नहीं पाते, पानी ने देने की वजह से वो जब बोरवेल करता है तो बोरवेल करते समय अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की डिमांड की जाती है और जब अधिकारी को पैसा नहीं दिया जाता तो उसको सील कर दिया जाता है, उसका सामान उठाकर पुलिस ले जाती है और पुलिस ले जाकर एसडीएम के पास चला जाता है वो केस। मेरे समक्ष मेरी विधानसभा में कई बार मुद्दा आया। जब मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि भाई आप इसको क्यों कर रहे हैं तो उठाकर उन्होंने कहा जी इन्होंने आपके अवैध है ये तो एनजीटी के नियम हैं। लेकिन वो नियम कहाँ चले जाते हैं जो बस्तियों में, सेवा

बस्तियों में आरओ प्लांट हैं जो की पानी को ट्रीट करके आधा पानी नाली में बहाते हैं, जो भूजल को आपको दोहन करके और आधा पानी सेल करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक जब उसके हम एक हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं तो पता लगता है जी इन्होंने तो हमारे साथ बदतमीजी की। अब बदतमीजी की जब वीडियो मंगाते हैं जो निवासी वीडियो भेजता है उसमें सिर्फ ये कहता है की मैडम ये क्या नाम है आपके बराबर में भी तो सबमर्सीबल लगा हुआ है कोई ही मेरे घर में आप सबमर्सीबील को कार्रवाई करने के लिए आए हैं। तो उसी को क्योंकि इतना पूछना हमारे अधिकारियों को, उनकी ईगो की प्रॉब्लम को, ईगो को हर्ट करता है और वो ईगो कहाँ चली जाती है जब वो पैसे लेकर वो सारे खुलेआम इस गोरखधंधे को चलाया जाता है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है क्योंकि आज की डेट में हर 10 घर के अंदर कम से कम में एक एवरेज बता रहा हूँ एक बोरवेल लगा हुआ है क्योंकि आज चार-चार मंजिल, पांच-पांच मंजिल मकान बने हुए। मजबूरी है, उसको नहीं रोक सकते और लाखों की संख्या में दिल्ली में आपके अवैध बोर लगे हुए हैं जिनको सरकार के हिसाब से अवैध है लेकिन जहाँ पैसा मिलता है वो वैध हो जाते हैं और जहाँ पैसा नहीं मिलता नहीं हो पाता। ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया है मेरे यहाँ। अब मजबूरी में फैक्ट्री में पानी चाहिए, दिल्ली जलबोर्ड पानी नहीं दे रहा है या तो फैक्ट्री बंद करिए या आप बोरवेल लगाइए। उसके लिए एक ऐसा नियम बनाना चाहिए की आने वाले समय में मैं समझता हूँ यदि एक प्रतिष्ठान से, कमर्शियल सेंटर से या क्या नाम है फैक्ट्री ओनर से 10 हजार रुपये महीने लेते हैं और एक, मैंने एक क्वांटिटी 10 हजार आपको एक संख्या मैंने बताई, 10 हजार बोरवेल चल रहे हैं तो 1000 करोड़ रुपए का लगभग सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, पुलिस और एसडीएम कार्यालय के माध्यम से जहाँ पैसा मिलता है उस पर भी रोक लगेंगी और सरकार की जो perception है वो भी आपके अच्छी होगी और इससे क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं, पानी हम दे नहीं रहे, मजबूरी है उनकी करना है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से आने वाले समय उन सभी बोरवेल के सर्वे कराये जाएं दिल्ली में। बेसिक देखा तो जाए कितने बोरवेल लगे हुए हैं और बोरवेल की संख्या के अनुपात में एक ऐसे निर्णय लिए जाएं जो दिल्ली के निवासियों के लिए हितकारी हों। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का वक्त दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल: धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी

माननीय कुलवंत राणा जी और कई सदस्यों ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ध्यान दिलाया की ट्रैफिक की जो व्यवस्था है दिल्ली में बहुत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है और माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली में तीन बार शादी का सीज़न आता है। अभी अप्रैल आने वाला है, फरवरी मार्च गया है, फिर नवंबर से फरवरी के बीच में करीब दिल्ली में 365 दिन में करीब 50 दिन शादियों का सीज़न होता है और विशेषकर हमारी मॉडल टाउन विधानसभा में जीटी करनाल रोड है, छत्तरपुर है, अलीपुर है, महिपालपुर है, मोती नगर है, पंजाबी बाग है, जीटी करनाल रोड है। अगर आप शादी के दिनों में हालात देखेंगे पूरी दिल्ली में, जब एक आदमी शादी में जाता है तो शादी के वेन्यू के बाहर एक-डेढ़ घंटे आराम से ही गाड़ी में बैठना पड़ता है और उसमें माननीय अध्यक्ष जी आप भी जाते होंगे शादी में, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के आम नागरिक सब जाते हैं और हेल्पलेस महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि ये कैसी दिल्ली है क्या और जब हम एक-डेढ़ घंटे के बाद आगे निकलते हैं तो देखते हैं की एक गाड़ी खराब हो गई थी। उस गाड़ी को देखने वाला कोई नहीं है। लोग बैंक्वेट हॉल के बाहर घुड़चढ़ी करते हैं, सड़क के ऊपर ही कब्जा कर लेते हैं और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। क्या हम इन 50-55 दिन 1400 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं क्या हम इसके लिए कोई प्लान नहीं बना सकते? क्या ये 15 साल से, 20 साल से लगातार जो दिल्ली चल रही है क्या ऐसी ही चलती रहेंगी? क्योंकि इसके अंदर माननीय अध्यक्ष जी मरीज भी होते हैं, एम्बुलेंस भी होती है, आम नागरिक भी होते हैं और जो शादियों में जा रहे हैं वो लोग भी होते हैं। इससे बुरी हालत शायद नहीं हो सकती। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन दिनों में विशेषकर कोई ट्रैफिक मनेजमेंट प्लान जरूर करें, पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, वैले पार्किंग कंपलसरी हों। जो ये बैंक्वेट हॉल है, जो रिसोर्ट है, जो लगातार बन रहे हैं तो इसके अंदर बहुत जरूरी है कि शादी के सीज़न के अंदर निश्चित रूप से कोई व्यवस्था, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जरूर सरकार इसके ऊपर बनाए और इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा विभिन्न सीएजी रिपोर्ट्स के विषय में सदन को सूचना

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्यगण, 23 मार्च 2026 को सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा सीएजी की विभिन्न रिपोर्ट्स पटल पर प्रस्तुत की गई थी। 25 मार्च, 2026 को सदस्यों ने रिपोर्ट संख्या-5, वर्ष 2024, ये रिपोर्ट्स जो है ये इनके मैं वर्ष पढ़ता जाऊंगा और आपकी जानकारी में डाल दूंगा की ये रिपोर्ट कब की है। ये जो रिपोर्ट सदन में liquor पर जो बात हुई थी वो वर्ष 2024 की है। तो संख्या रिपोर्ट संख्या-5 पर अपने विचार व्यक्त किए जिसमें शीशमहल से संबंधित निष्कर्ष शामिल थे। इसके अलावा सीएजी ने उस रिपोर्ट में जीएसटी, वैट, स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और उत्पाद शुल्क लगाने में गंभीर अनियमितताओं का भी खुलासा किया है। उस रिपोर्ट में सूचना एवं प्रचार निदेशालय, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और राजस्व विभागों के कामकाज में कमियों की भी जानकारी दी गई है। आज सदन में, वो तो हमने चर्चा कर ली है। आज सदन ने उन अन्य रिपोर्ट पर चर्चा की उन्हें 23 मार्च को सदन में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट संख्या-3 वर्ष 2022 में सीएजी ने गृह, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, शहरी विकास, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, यूटीसीएस, एनएसयूटी आदि विभागों में अनियमितताओं पर और कमियों का खुलासा किया है रिपोर्ट नंबर-3 में। अपनी रिपोर्ट संख्या-1 वर्ष 2023 में सीएजी ने देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखा परीक्षा परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट 18-19 से 2020-21 तक की रिपोर्ट है ये क्योंकि पहले सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर आती ही नहीं थी। ये 15 वर्ष से यह प्रक्रिया बंद थी एक प्रकार से वो मैं आपको पूरा स्पष्ट कर दूंगा अभी आगे। यह रिपोर्ट 18-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अवधि को कवर करती है। लेखा परीक्षा ऑडिट के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल देखभाल संस्थानों के अभिलेखों की जांच की गई है। ये जो रिपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं संख्या-1 यह जो अपने स्पेशल चाइल्ड हैं चाइल्ड केयर जो हैं उनके ऊपर यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जरूरतमंद बच्चों को देखभाल और संरक्षण प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कई कमियों की ओर इशारा किया गया है। विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए संस्थानों के निर्माण में देरी और बच्चों के कल्याण हेतु अन्य उपायों जैसे बाल देखभाल, संस्थानों को राशि जारी करने, बच्चों को गाद लेने के लिए मुक्त घोषित करने आदि में हुई देरी का उल्लेख किया गया है। बाल देखभाल संस्थानों को कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे और

चिकित्सा सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने प्रायोजन योजना स्पोंसरशिप स्कीम और फोस्टर केयर योजना को भी लागू नहीं किया। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना और व्यक्तियों को ऐसे बच्चों के फोस्टर पेरेंट्स पालक माता-पिता बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। विश्वविद्यालयों के कामकाज पर सीएजी की रिपोर्ट संख्या-4, 2025 में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस और रिसर्च विश्वविद्यालय के विस्तृत ऑडिट से जुड़े हुए निष्कर्ष हैं। यह ऑडिट अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए किया गया है। सीएजी ने शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों, विश्वविद्यालयों के एक्रिडेशन और संबद्धता प्रक्रिया, मानव संसाधन, प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, सुविधाओं, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रणों में कई मुद्दों की जानकारी दी है। रिपोर्ट संख्या-3, 2025 में सीएजी ने दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज का विस्तृत विवरण दिया है। जिसमें वर्ष 17-18 से वर्ष 21-22 तक की अवधि शामिल है। सीएजी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित थे। दिल्ली में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर, रेणुका लखवार और किशाऊ बांध परियोजनाओं के क्रियान्वयन से में अत्यधिक विलंब, पानी की आवश्यकता को योजना बनाने के लिए कोई जल नीति मौजूद नहीं है, ट्रांसमिशन हानियों में वृद्धि और प्रति व्यक्ति उपलब्ध पेयजल की मात्रा का अत्यंत कम होना, भूजल संसाधनों को विनियमित करने, नियंत्रित करने और विकसित करने के लिए कोई योजना नहीं है। गैर राजस्व जल नॉन रेवेन्यू वाटर के कारण दिल्ली जल बोर्ड को प्राप्त ना हो सकी अनुमानत राजस्व राशि 4 हजार 988 करोड़ रूपये थी। 1080 अनधिकृत कॉलोनियों में उत्पन्न 212.59 एमजीडी सीवेज को बिना उपचारित किए ही पानी की नालियों में बहा दिया गया। 25 एसटीपी द्वारा यमुना नदी में छोड़े गए उपचारित अपशिष्ट जल ने डीपीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया। एनआईटी की शर्तों पर सीपीडब्ल्यूडी के निर्देशानुसार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्य के अनुमान आवंटन और क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाई गई। राजस्व प्रबंधन प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी और उसमें कार्य संबंधी कमियां व्याप्त थीं। कर्मचारियों की गंभीर कमी थी, साथ ही नियमों और औपचारिकता का उल्लंघन करते हुए अनियमित नियुक्तियां भी की गई थी। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 21, 22 और 23 के लिए राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट भी मार्च 23, 2026 को सदन के पटल पर रखी गई है। जो दिल्ली सरकार के वार्षिक खातों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है। हमारे नियमों के अनुसार सरकारी उप/उपक्रम समिति कोगू, डीजेबी पर बनी रिपोर्ट की जांच कर सकती है बाकी सभी रिपोर्टों की जांच पीएसी द्वारा की जाएगी। मैं विधानसभा

सचिवालय को इस मामले में अभी चर्चा के बाद संबंधित विभागों को भेजने के संबंध में इस पर बातचीत करेंगे और यह अब मैं इस पूरे मामले पर श्री प्रवेश।

श्री अभय वर्मा(चीफ व्हीप): इसमें जो आइटम नंबर दो से लेकर छः तक को तो पीएसी में भेज दिया जाए क्योंकि जो आइटम नंबर जल बोर्ड है उस पे माननीय मंत्री जी के साथ कुछ मेंबर अपना विचार रखेंगे।

माननीय अध्यक्षः ठीक है।

श्री अभय वर्मा(चीफ व्हीप): और एक जो विश्वविद्यालय से संबंधित है उस पे माननीय मंत्री जी अपना विचार रखेंगे।

माननीय अध्यक्षः ठीक है तो अब मैं।

श्री अभय वर्मा(चीफ व्हीप): बाकी सभी रिपोर्ट्स को पीएसी में भेज दिया जाये।

माननीय अध्यक्षः अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री, दिल्ली सरकार श्री प्रवेश वर्मा जी को।

<u>सी.ए.जी.रिपोर्ट(दिल्ली जल बोर्ड) पर चर्चा</u>

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी नमस्कार और सबसे पहले आपको और सभी सदस्यों को देशवासियों को राम नवमी की बहुत-बहुत बधाई। मैं आप जैसे बता रहे थे कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स आई है तो उनका कार्यकाल क्या है उनकी समय अवधि क्या है? वो अच्छा किया आपने बताया क्योंकि पीछे मैंने एक अखबार में पढ़ा उसकी बहुत बड़ी हेडलाइन थी कि दिल्ली के ग्राउंड वाटर के आधे से ज्यादा सैंपल फेल हो गए तो उसमें डेट नहीं लिखी थी। बहुत सारे लोग होते होंगे जो खाली हेडलाइन पढ़ के और अखबार को बंद कर देते होंगे। तो जब मैंने हेडलाइन पढ़ी तो मैं भी घबरा गया कि मेरे डिपार्टमेंट के आधे से ज्यादा सैंपल ग्राउंड वाटर के फेल हो गए। मैंने नीचे खबर पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि 2027 से 2023 तक की रिपोर्ट है। यह हम नहीं कह रहे। ये जैसा आपने कहा।

माननीय अध्यक्षः 2017 से 2023 तक।

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्रीः 2017 से 2023 तक की रिपोर्ट है। यह हम नहीं कह रहे ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। मैं सबसे पहले हमारे सीएजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सारे तथ्यों को देश की जनता और खासतौर पर दिल्ली की जनता के सामने

लेकर आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था अध्यक्ष जी कि 280 में यहां पर उपस्थित 30 सदस्यों में आपने लगभग 16-17 सदस्यों को बोलने का मौका दिया और मैं यह भी देख रहा था कि सारे सदस्यों ने आज क्यों हमारे सामने विपक्ष गायब है ये सारे सत्ता पक्ष के हमारे सदस्य हैं माननीय सदस्य हैं। ये सारे सदस्य अपने-अपने विधानसभा की कमियों को हमको गिनवा रहे थे। जो इनके पास में जनता आती है सुबह दो घंटा-तीन घंटा ये जब उनसे मिलते हैं, उनकी परेशानियों को क्योंकि उसी जनता ने इनको जिता कर भेजा है कि आप हमारी आवाज उठाइए विधानसभा में। एक भी सदस्य ने जो सरकार बजट लेके आई है, मुख्यमंत्री जी जो काम कर रही हैं, उसकी बडाई नहीं करी मगर सबने अपनी-अपनी खामियों को, अपनी-अपनी परेशानियों को जो जनता इनको कहती थी उनको उठाया। यही सारी बातों के लिए विपक्ष के सदस्यों को भी चुना गया है। आज वहां की जनता दो बार, तीन बार इनको कईयों को जिताकर भेजी है मगर आज ये सारे के सारे पूरा इन्होंने सत्र के लिए वॉकआउट किया। वॉकआउट क्यों किया? क्योंकि यह जानते थे कि सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पीएसी की रिपोर्ट आ रही हैं, हम क्या बोलेंगे। शीश महल के ऊपर में क्या बोलेंगे, पानी के ऊपर क्या बोलेंगे। स्कूल की बिल्डिंग में जो घोटाला किया, मोहल्ला क्लीनिक की बिल्डिंग में जो घोटाला किया, उस पर क्या बोलेंगे। तो यह सब लोगों ने सोचा कि हम लोग पूरे सत्र का वॉकआउट कर दें और हमें आज यह होते तो अपने-अपने क्षेत्र की परेशानियां बताते। यहां पर यह आ नहीं रहे क्योंकि एक व्यक्ति का डर है जो दिल्ली के डकैत है उनका डर है मगर यह सारे विपक्ष के सदस्य मेरे पास आते हैं और जब ये मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाई साहब हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है तो मैं इनको बोलता हूं कि भाई 11 साल क्या किया तो ये लोग मुझे कहते हैं भाई साहब 11 साल कोई काम नहीं हुआ। हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता था। केजरीवाल जी के सामने अगर कोई बोलते थे तो वह हमको गालियां देकर बाहर भगा देते थे, निकाल देते थे। ये सारे विपक्ष के लोग हमें आकर कमरे में ऐसी बातें कहते हैं और हमसे आज वो पानी सीवर की बात करते हैं। मगर जहां पर उनको उठाना चाहिए विधानसभा सत्र में वहां पर वो उठा नहीं रहे।

अध्यक्ष जी, दिल्ली जल बोर्ड ये जब हमारी सरकार थी, 1993 से 1998 के बीच में उस समय, पहले वाटर का डिपार्टमेंट होता था, उससे दिल्ली जल बोर्ड बनाया गया। दिल्ली जल बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको पूरा अधिकार मिले। ये सारे काम, सारे निर्णयों का फैसला खुद बिना बहुत जगह पे फाइल जाए, अपना ही बोर्ड इस बात के लिए सक्षम है कि वो बड़े बड़े फैसले ले सकता है। हमने कई बार सुना था दिल्ली के रहमान डकैत को कि वो कहते

थे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहें, हमें एलजी जमीन नहीं दे रहें, हमें एलजी पैसा नहीं दे रहे। मगर दिल्ली जल बोर्ड की तो फाइल दिल्ली सरकार के पास ही जाती है, कभी एल जी साहब के पास जाती नहीं। चाहे कोई बड़े से बड़ा फैसला हो, उसकी फाइल भी दिल्ली जल बोर्ड की ये एल जी साहब के पास नहीं जाती। यानि कि मुख्यमंत्री जो थे वो सारे फैसले लेने में, ले सकते थे। मगर उनको दोष देना था, काम नहीं करना था। दिल्ली जल बोर्ड जो आज दिल्ली में 2,50,00,000 लोगों को पानी, सीवर ये सारी सुविधा मुहैया कराने का काम करता है। दिल्ली में 60,00,000 घर है दिल्ली जल बोर्ड का मुख्य कार्य है पानी को ट्रीट करना, नई पानी की लाइन डालना, मेंटेनेंस करना, सीवर की लाइन डालना हर घर को सीवर कनेक्शन से जोड़ना, सारे सीवर को ट्रीट करना, यमुना मैय्या को साफ रखना। दिल्ली में हमको अध्यक्ष जी लगभग 1200 एमजीडी पानी की जरूरत, मगर आज हमको कुल मिला कर 1000 एमजीडी पानी मिलता है और इसमें से लगभग पौने नौ सौ 875, 870 एमजीडी पानी हमको कैनाल से मिलता है और लगभग 135 से 140 एमजीडी पानी हमको बोरिंग से ट्यूबवेल के माध्यम से मिलता है। दिल्ली में डिमांड ज्यादा है मगर डिमांड ज्यादा होने के साथ साथ दिल्ली में वाटर लॉस भी ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में एक एक जनरल फेनोमेना है कि 15% तक एनआरडब्ल्यू वाटर लॉस जो आपका ट्रांसमिशन लॉस ये चलता है, मगर दिल्ली में ये ट्रांसमिशन लॉस वाटर लॉस और हम जिसको एनआरडब्ल्यू कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर ये लगभग 45 से 53 परसेंट, मगर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है कि दिल्ली के हर घर को साफ पानी हम लोग दे। दिल्ली में बार बार हम सुनते हैं यमुना मैया, यमुना मैया को साफ करना। यमुना मैया को साफ करना ये हमारा कमिटमेंट है ये हम दिल्ली की जनता से वायदा किए कि हम अपने कार्यकाल में यमुना मैया को साफ करेंगे। यमुना मैया कौन है? यमुना मैया सूर्य भगवान की बादल की देवी की पुत्री है। यमुना मैया शनि की बहन है, यमराज की बहन है, यानि क्योंकि केजरीवाल जी ने यमुना मैया को खराब किया, गंदा किया, ना केवल सूर्य भगवान बल्कि शनि महाराज, यमराज जी का भी उनको प्रकोप लगा और आज उनकी ये हालत हुई। मैं ये बात हर अधिकारी से भी कहता हूँ, हमारे जल बोर्ड के जितने अधिकारी हैं मैं सबको ये बात कहता हूँ कि भैया यमुना मैया यमराज जी की बहन है, शनि महाराज की जो है शनि भगवान की बहन है इसलिए गलती मत करना। यमुना को साफ करना ऊपर जाकर हमको सूर्य भगवान को शनि भगवान को यमराज जी को जवाब देना है, वो यमराज जी तो जब बुला ले, कब बुलाले पता नहीं। इसलिए जो अच्छा काम करेगा वो ज्यादा दिन रहेगा। ऐसा मैं जल बोर्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबको हम बताते रहता हूँ। तो यमुना मैया को साफ करना, ये हमारा संकल्प है ये मैं आज यहाँ पर आपके सामने फिर से दोहराता हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करने

से पहले एक और यहाँ पे बात दिल्ली की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा, किनके कार्यकाल में होता क्या था, इनके कार्यकाल में वाटर टैंकर माफिया को बढ़ावा मिलता था। 2020 की घटना है, 2020 में एक डॉक्टर भी था और वो वाटर टैंकर का काम भी करता था, उसके पास में टैंकर भी थे और उसने 2020 को सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड करते हुए सुसाइड नोट लिखा उसने और उसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रकाश जारवाल और उनके साथियों को उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया । उन्होंने कहा कि मैंने 2007 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के एमएलओ को इनके जो सारे चेले हैं, उनको 6,00,000 से 10,00,000 रूपये दे चुका हूँ रिश्वत। मगर और पैसा मांग रहे हैं कि और पैसा दो। तो वो अपने जीवन से यानि कि जल बोर्ड को लूटना, दिल्ली को बर्बाद करना, दिल्ली को साफ पानी नहीं देना ये ऐसे लोग थे। सीएजी की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई है मैं वो क्या क्या फाइंडिंग्स से अभी आपने भी कहा मैं एक बार उसको दिल्ली की जनता के सामने कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उनकी प्लानिंग एकदम फेल थी। क्यों फेल थी, क्योंकि उनके पास में आंकड़े ही नहीं थे। दिल्ली में, दिल्ली की जनता कितना पानी इस्तेमाल करती है, कितना पानी हमको ट्रीट करना है, ये कभी उन्होंने कोई भी स्टडी नहीं करी और जब कोई स्टडी नहीं करते थे, तो फिर उसको कितना कपैसिटी में हमको एसटीपी प्लांट लगाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, ऐसी कोई प्लानिंग वो कर ही नहीं सकते थे। जो दिल्ली में 35 एसटीपी लगते थे, उसमें से 25 हमारे एसटीपी का जो बीओडी टीएसएस लेवल था, वो 10 से ऊपर था यानि कि फैल था, ये भी सीएजी रिपोर्ट बताती है। सारे एसटीपी में फिकल क्लीफॉम मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। 56 जो सीवेज मास्टर प्लान बना 2031 का, उसमें 56 नए एसटीपी प्लान किए गए, उसमें से आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी नया एसटीपी अपने कार्यकाल में नहीं बना पाई। 212 एमजीडी के लगभग में दिल्ली की 1080 अनोथराइज्ड कॉलोनी है। जहाँ पे सीवर लाइन नहीं डली, कहीं पे सीवर के पाइप वहाँ पे दिखाने के लिए डाल दिए, तो वहाँ पे एसटीपी प्लांट नहीं बनाया। यानि कि 212 एमजीडी पानी डायरेक्ट बिना साफ किए यमुना के अंदर में चला जाता है, इसलिए यमुना हमको बिल्कुल काली दिखाई देती है, गंदी दिखाई देती है। अध्यक्ष जी, 1000 कॉलोनियों से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां है जहाँ पे सीवर लाइन आज भी नहीं थी। ये सब के ऊपर में हमने काम करना शुरू किया, अब जहाँ पे सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक लोगों ने बना रखे अनोथोराइज्ड कॉलोनी में गांव में और ये सारे सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे अपने चेलों को कंट्रैक्टर को ठेका दिया कि आप वहाँ पे जाके 2000- 3000 रूपये लेकर और उनको साफ कर सकते हैं। मगर उसमें एक लाइन तो लिखी थी कि आपको ये साफ करके निकालकर हमारे

एसटीपी प्लांट पर डालना है। मगर इसकी मॉनीटरिंग नहीं हुई यानि कि 1000 से ज्यादा अनोथोराइज्ड कॉलोनी का झुग्गियों का, गांव का जो सेप्टिक टैंक का सीवर था, जो सारा सेप्टेज था, वो सीधा यमुना में जो भी आसपास की वहाँ पे नाला होता था, ड्रेन होता था, उसमें डालने का काम करते थे, मगर उसको एसटीपी प्लांट में नहीं लेकर जाते थे। चूंकि केजरीवाल जी को पता था कि ये सारा सेप्टेस सेप्टिक टैंक का सीधा नालों में डाल देते हैं और वो सीधा यमुना में चला जाता है, यही एक कारण था कि केजरीवाल जी ने यमुना में डुबकी नहीं लगाई। वो हर साल कहते थे, मैं लगाऊंगा, लगाऊंगा, लगाऊंगा क्योंकि उनको मालूम था वहाँ पे डुबकी लगाऊंगा, तो फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगा। वहाँ पे कितना गंदा है, उन्होंने कितना गंदा किया यमुना को, इसलिए उन्होंने कभी यमुना में डुबकी नहीं लगाई अध्यक्ष जी और ये सारे एसटीपी का जो ट्रीटिड वाटर है उसमें 74% पानी वो किसी भी, हम उसका रियूज़ नहीं कर सकते थे, पार्को में भी नहीं कर सकते थे, हॉर्टिकल्चर में भी नहीं कई। तो इतना गंदा पानी एसटीपी का निकलता था ये भी सीएजी की रिपोर्ट में आया है। जो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए पानी के सोर्सेस को बढ़ाना है, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जो हमारे हिमाचल में जो रेणुका डैम बन रहा है और जो केशवा डैम है, लखवा डैम जो वहां पर बन रहा है उसमें जो दिल्ली ने पैसा देना था, दिल्ली ने अपना शेयर देना था, आम आदमी पार्टी ने वो भी पैसा उनको नहीं दिया इसलिए वह जो डैम बनाने की योजना धीरे चल रही थी, मगर आपको बताते हुए खुशी होती है कि अब दिल्ली का जो हमारा शेयर का पैसा है वो हमने वो डैम बनाने के लिए रिलीज करना शुरू कर दिया है इसीलिए वहां पर काम आज के दिन में तेजी से हो रहा है और मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में लगभग चार से 10 मीटिंग चार मीटिंग प्रधानमंत्री जी, 10 मीटिंग गृह मंत्री जी वो सारे अधिकारियों को बुलाकर हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, उत्तरांचल के ये सारे चीफ सेक्रेटरी वहां की सरकारों को बुलाकर हम लोगों को बुलाकर हमारे गृह मंत्री जी 10 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं कि यमुना में पानी कैसे आएगा। दिल्ली में पानी जो है और कैसे आएगा? यमुना का पानी का हम लोग कैसे करेंगे इसकी चिंता वो खुद ही कर रहे हैं। जो हमारे हमने जो हिमाचल के साथ में एमओयू किया 29 साल पुराना एमओयू वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो दिल्ली में 45% एनआरडब्ल्यूए था। नॉन रेवेन्यू वाटर कि पानी तो जाता है हमको वहां से रेवेन्यू नहीं मिल रहा। यानी कि हमारे कनेक्शन नहीं है। आज जो है बिजली के कनेक्शन दिल्ली में ये लगभग 50 लाख के करीब है। 60 लाख के करीब हैं। हैं आशीष जी। 60 लाख के करीब में दिल्ली की जनता ने पावर कनेक्शन लिए हुए हैं। मगर

पानी के कनेक्शन केवल 30 लाख लोगों ने ले रखे हैं। यानी कि 30 लाख लोगों ने आज भी पानी के कनेक्शन लेने हैं। पानी तो मिल रहा है। मगर पानी का कनेक्शन नहीं है। या तो इल्लीगल है या और कोई कारण है। मगर जब आम आदमी पार्टी आई तो 45% एनआरडब्ल्यूए से बढ़ाकर वो हमको 53% पे छोड़ के गए जिसको हमारी सरकार का संकल्प है कि हम इसको 15% तक लेके आएंगे अपने प्रयासों से अपने कार्यकाल में। जो एनआरडब्ल्यूए का लॉस अकेला लॉस ही 5000 करोड़ रूपए है। अगर ये हम इसको 15% तक ले आएंगे तो हमको 5000 करोड़ रूपए इसमें और मिलना शुरू होगा। मतलब सीएजी ने इतनी गंभीर, गंभीर कमियां इसमें बताई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें से एक कमी है कि जो पानी को ट्रीट करने के लिए यह कैंसरस मैटेरियल का इस्तेमाल करते थे। कैंसरस मैटेरियल, जिससे लोगों को कैंसर हो सकता है। ऐसे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर सकते थे। वो भी रिपोर्ट में बताया गया है। दिल्ली में कोई वाटर मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली में वाटर टैंकर माफिया का वो दबदबा बढ़े जा रहा था। यहां तक कि जो चंद्रावल और वजीराबाद की परियोजना थी वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार में केवल कमीशन खाने के चक्कर में वो भी सालों साल तक सालों साल तक उसको डिले होता रहा। आज हमारे आने के बाद में जहां पर हमने जो है चंद्रावल वो सारे टेंडर कर दिए, अवार्ड कर दिए, काम शुरू हो गया जिससे 10 विधानसभा को फायदा मिलेगा। उसी के साथ ही वजीराबाद की भी योजना को हमने शुरू कर दिया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एडीबी बैंक पहले ये योजना के साथ में हमसे जुड़ा था। मगर क्योंकि उनसे बड़ी-बड़ी कमीशन मांगी जाती थी तो वो यहां पे दिल्ली सरकार के साथ में काम करने के लिए मना करके और वो छोड़कर चले गए थे। हमारी सरकार बनते ही आप देखिए कुछ हमारी गुडविल भी होती है। हमारी मोदी जी की पार्टी की गुडविल भी होती है। परसेप्शन भी होता है कि जैसे ही हमारी सरकार बनी वापस एडीबी बैंक ने हमको अप्रोच किया कि हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं और आज हमने उनको सारी मंजूरी दे दी है एडीबी बैंक और हमने जैसे चंद्रावल स्टार्ट किया वैसे वजीराबाद उसमें भी 10 विधानसभाओं को फायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं। एक साल में हमने क्या-क्या किया। ये सारे सदस्यों को बताना चाहता हूं क्योंकि ज्यादातर सदस्य ज्यादातर नहीं बोलूंगा 100% सदस्य

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नेगी जी, रविंद्र नेगी जी प्लीज आप।

माननीय मंत्री का वक्तव्य(नियम-270)

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: सभी की हमसे सबसे ज्यादा मेरे विभागों से चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाला हो, सभी की मुझसे शिकायत रहती है और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोग मुझे शिकायत करते हैं और मुझे मौका मिला कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। आपकी सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। पहले दिल्ली के विधायकों को मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 से 2025 तक आप लोग मेरे से आप लोग हमारे विभाग से अपने अपने क्षेत्रों के लिए मेंटेनेंस का पैसा मांगते। 2024 से 25 तक दिल्ली के विधायकों को मेंटेनेंस का 1 करोड़ रूपए भी नहीं मिलता था। हमने सारे विधायकों की विधानसभा में 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ और कई-कई विधानसभा ऐसी हैं यहां बैठे हैं हमारे मेरे सरकार में सहयोगी डॉक्टर पंकज साहब। इनकी विधानसभा में तो सौ-ढेड सौ करोड़ रूपए के काम चल रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए चंदन जी आपकी विधानसभा में भी 40-50 करोड़ के काम चल रहे हैं। मगर क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉक्टर पंकज सिंह जी की विधानसभा बहुत ही दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है। बहुत ही अनथराइज कॉलोनियां है। 90% अनथराइज कॉलोनी की विधानसभा है। उसके बाद में गांव की संख्या आती है। शहर की संख्या बहुत ही छोटी है। तो वहां पर पिछले 11-15 साल में काम ही नहीं हुआ। इसलिए वहां पर आज क्योंकि हमको हर घर को जोड़ना है सीवर से। तो अध्यक्ष जी मैं सब एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि हम ये सोच रहे थे कि दिल्ली में 1000 एमजीडी सीवर को हमको ट्रीट करना है मगर एक बैठक में गृह मंत्री जी हमको बोले भैया 1000 की प्लानिंग मत करो, सीधा 1500 एमजीडी की प्लानिंग करो। आने वाले 50 साल का सोचो। ऐसे एसटीपी प्लांट बनाओ कि आने वाली जो पपुलेशन हो ये 50 साल तक हमने यमुना को साफ रखना है, उसके बाद भी साफ रखना है। तो आज ही से इसकी प्लानिंग करना स्टार्ट करो। क्योंकि आज हमको कहीं पे जमीन की दिक्कत होती है, हम जाते हैं डीडीए के पास में तो जमीन मिल जाती है। मगर ये धीरे-धीरे जमीन भी खत्म होती रहेगी। इसलिए जमीन को आइडेंटिफाई करना आने वाले 50 साल के लिए उसको 1500 एमजीडी तो आने वाले 50 साल तक ये हमारे गृह मंत्री जी की सोच थी। आज दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में 1500 एमजीडी सीवर को ट्रीट करने की प्लानिंग करने में लग गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं हमारी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको 9000 करोड़ रूपया

हमको दिल्ली जल बोर्ड में दिया और इसी के साथ में हमको बहुत सारा पैसा अध्यक्ष जी सेंट्रल फंड से मिलता है। जैसे 1500 करोड़ रूपए एनएमसीजी ने हमको 480 एमजीडी, डीएसटीपी के लिए उसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए एनएमसीजी ने दिया। ऐसा नहीं है कि ये पहले हमारे प्रधानमंत्री जी मना कर देते थे। ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी वो पैसों को अपने विज्ञापन पे खर्च करता था, अपने शीश महल पर खर्च करता था, उन पैसों को गोवा में डाइवर्ट करता था, उन पैसों से पंजाब में चुनाव लड़ता था। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे भई ये पैसा ले जाओ मगर इससे यमुना साफ कर देना। मगर जब उन्होंने देखा कि वो यमुना वमना तो छोड़ो वो वहां पे डुबकी लगाना तो छोड़ो, दिल्ली को दिल्ली की जनता को पानी पिलाने की बजाय जब उन्होंने शराब पिलाना शुरू कर दिया शराब के ठेके खोलने शुरू कर दिए। गली में मंदिरों के साथ में, स्कूलों के साथ में तो ऐसी सरकार को पैसे कौन देगा भला? मगर आज हमारी सरकार को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद कि वो कोई पैसे की कमी नहीं। हम उनके पास में शायद हमारे शब्द कम हैं। हम उनको जब भी कोई उनके पास में एप्लीकेशन ले जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये पैसा इनको दे दिया जाए। इसी कारण से मुख्यमंत्री जी हमको पैसा दे रही हैं। प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे हैं। हमको सूर्य भगवान का आशीर्वाद है। शनि भगवान का आशीर्वाद है। ये हमारा संकल्प इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यमुना मैया को साफ करेंगे। आज साफ करने के लिए हमको एसटीपी प्लांट बनाने पड़ेंगे। आज मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि हमने दिल्ली में नए 35 एसटीपी के ऊपर में काम करना और आज भी हमारे 20 से 25 टेंडर लाइव हैं जो कि 10-15 दिन में, 20 दिन में खुल जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे और अगले 2 साल में आपके यहां पे भी बन रहा है। अगले 2 साल में ये सारे एसटीपी बनकर तैयार हो जाएंगे। ये भी मैं आपको कह रहा हूं दिल्ली में आज 20 लाख मकान ऐसे हैं जो सीवर के कनेक्शन से नहीं जुड़े हुए। जब तक सीवर का कनेक्शन नहीं जुड़ेगा और उसका आउटले वहां से कोई एसटीपी पे नहीं जाएगा और एसटीपी वो हमारे मानकों के अनुसार में पानी ट्रीट नहीं करेगा, उसके बाद में ड्रेन छोड़ेंगे, उसके बाद में यमुना में आएगा, तब तक दिल्ली में यमुना मैया साफ नहीं होगी। हम अगले ढाई साल में जितना सीवेज का हमारा गैप है उससे ज्यादा 115% दिल्ली में एसटीपी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम आपके बीच में करके दिखाएंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 35 एसटीपी में हमारा fecal coliform disinfected system वो हमारा हमने उसको अप्रूव कर दिया है ताकि वहां पर उसकी मॉनिटरिंग हो। इसी के साथ में 401 अनओ थराइज कॉलोनी में हमारा सीवर कनेक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, टेंडर हो गया है, पैसा दे दिया गया है और तो जैसा अभी मैं कह रहा था डॉक्टर पंकज जी, वही काम सीवर कनेक्शन का सीवर लाइन डालने का काम वहां पर चल

रहा है। और इसी के साथ ही एक और मैं आपको अच्छी बात यह बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि लाखों घरों में सेप्टिक टैंक है, सीवर कनेक्शन नहीं और ये प्राइवेट लोग आते हैं टैंकर लेकर वहां से 2000, 3000 रूपये लेते हैं, उसको साफ करके सीधा नाले में डाल देते हैं। जबकि उनको डालना चाहिए एसटीपी प्लांट ताकि हम उसको साफ करें। जल बोर्ड बहुत ही जल्दी टेंडर कर रही है, वो अपने टैंकर ले रही है, अपना सिस्टम बना रही है, जो यह सारे जो हमारे सेप्टिक टैंकर माफिया हैं इन सबको हटाकर जल बोर्ड अपना सिस्टम बना रही है। अपना एक जो है पोर्टल स्टार्ट कर रही है। वहां पर कोई भी आदमी अपनी रिक्वेस्ट डालेगा। केवल उससे 50 रूपया, 100 रूपये हो सकता है 20 रूपया, अभी तय नहीं किया। मगर बहुत ही मिनिमल, यह अमाउंट लेकर जल बोर्ड ही सारा उसका सेप्टिक टैंक को क्लियर करेगी। यह सारे जो सेप्टिक टैंक के माफिया हैं इनको भगाएगी। यह सुविधा अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगी तो फ्री में भी कर देंगे। मगर 5, 10 रूपये, 20 रूपये लेना वह भी ना के बराबर ही है। मगर ये 150, 200 टैंकर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ताकि यह भी बहुत बड़ा कदम है यमुना मैया को साफ करने में, ताकि पूरा septage को निकालकर अगर हम करेंगे तो हमारी गारंटी है कि सबको लाकर उसको एसटीपी प्लांट में डालेंगे। वहां पर साफ करेंगे, उसके बाद में ड्रेन जाएगा, उसके बाद में यमुना मैया में जाएगा। आज लगभग 550 करोड़ रूपये के टेंडर हो चुके हैं सीवर कनेक्शन के लिए जिससे 30 लाख लोगों को फायदा मिलने वाला है। दिल्ली में अध्यक्ष जी 1799 अनओथराइज कॉलोनी है जहां पर 1265 कॉलोनियों में सीवर लाइन वहां पर डल चुकी है। मगर ज्यादातर कॉलोनी अभी वहां पर कोई भी एसटीपी से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए सीवर कहां पर निकलता है? जैसे किराड़ी का उदाहरण आया। वहां पर हमने देखा कि सारा पानी भर जाता था। अब वहां पर सीवर लाइन तो डल गई। मगर सीवर लाइन का पानी कहां जाएगा, कौन से एसटीपी प्लांट में जाएगा, वो एसटीपी प्लांट कभी आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया। हम बना रहे हैं। हम वह सारे सीवेज को रोहिणी में 35 एमजीडी का नया एसटीपी प्लांट बना रहे हैं। ताकि उस पानी के निकासी सीवेज की निकासी वहां तक जाए जो हमारा रोहिणी में बना हुआ है। अब आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। आप यह मत सोचना कि हम आपके यहां पे नया एसटीपी प्लांट बना रहे हैं। आपके यहां पे एसटीपी प्लांट बना हुआ है। वहां पे 100 एकड़ जमीन है। हम उसको केवल अपग्रेड कर रहे हैं और ऐसा अपग्रेड कर रहे हैं। आप हमारे नए एसटीपी प्लांट में जाएंगे, आप वहां पर बैठकर चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, आपको इतनी सी भी स्मेल नहीं आ सकती है। जरा सी भी स्मेल नहीं आ सकती। एसटीपी प्लांट के वहां पर बैठे हुए स्मेल नहीं आ सकती। आसपास के घरों की बात तो छोड़िए, क्योंकि हमारे जो नए मानक हैं वो जो दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड हैं उनके बराबर हमने मानक लिए हैं। हमने

अब आज की डेट में अध्यक्ष जी हमारे पास में लगभग 201 कॉलोनियों में टेंडर कर दिए हैं, 135 कॉलोनियों में वर्क इन प्रोग्रेस है यानि कि लगभग सवा चार सौ, 440 कॉलोनियां, मैं यहां पे सदन के सामने दिल्ली का जल मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर-अंदर में सारी 1799 कॉलोनियों का सीवर कनेक्शन 100% कर देंगे और सबको एसटीपी प्लांट से जोड़ देंगे। और इसी के साथ में एक हम और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी हम दिल्ली की जो बड़ी-बड़ी ड्रेन है उनका इनसीटू ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमने जल बोर्ड में अप्रूव कर दिया है। उनका इनसीटू ट्रीटमेंट यानी कि ड्रेन के ऊपर ही ट्रीटमेंट होगा। अभी हम उसके लिए दिल्ली गेट का हमारा टेंडर आ चुका है। उसके बाद में डिफेंस कॉलोनी ड्रेन, फिर सेन नर्सिंग होम ड्रेन, आईएसबीटी ड्रेन, उसके बाद में नजफगढ़ ड्रेन, जिसको साहिबी रिवर कहते हैं, अब नाम तो उसका साहिबी रिवर ही था पौराणिक। मगर इतना काला हो गया बिल्कुल नाले की तरह तो सब लोग उसको नजफगढ़ ड्रेन कहने लग गए। ये भी मैं सारे सदन के सामने दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि हम उसका नाम जो है नजफगढ़ ड्रेन को दिल्ली की सारी जनता की जुबान से हटाकर वापस से हर जनता जब वो साफ पानी देखेगी वहां पर नेचुरल लाइफ देखेगी वहां पे अंडर वाटर लाइफ देखेगी तो अपने आप ही मुंह से निकलेगा यह तो साहिबी रिवर है नजफगढ़ ड्रेन नहीं। पिछले एक साल में 180 किमी नई सीवर लाइन हम दिल्ली में डाल चुके हैं और 110 किलोमीटर के ऊपर में हमने लाइनों को बदलने का उसको रिप्लेस करने का काम किया है। और अध्यक्ष जी एक और अच्छी बात जो हमारी सरकार ने किया है वो यह किया है कि ये सारे एसटीपी जब हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। वहां का जो ट्रीटेड वाटर है वो 10 बीओडीटीएसएस से कम लेकर जा रहे हैं, 10 बीओडीटीएसएस से कम लेकर जाने का मतलब है पानी का कलर आपको एकदम क्लीन दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, जैसा पानी पीते हैं वैसा दिखाई देगा। उसको हमने टेस्ट करवाया। वो पानी दिल्ली के सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं। दिल्ली के हॉर्टिकल्चर में तो कर ही सकते हैं। अब जो सारे एसटीपी के आसपास में बड़े-बड़े पार्क हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए विधायक हमारे भाई जो सारे एसटीपी के आसपास में बड़े-बड़े पार्क हैं एमसीडी के, डीडीए के, किसी भी विभाग के पार्क हैं। उन पार्कों में आपको पानी नहीं मिलता है। वो पार्क की घास सूख जाती है, पेड़ सूख जाते हैं, आपकी शिकायत आती है। डीडीए भी क्या करें? एमसीडी भी क्या करें? पानी नहीं मिलता। यह जल बोर्ड विभाग ने जिम्मा उठाया है कि हम अपने एसटीपी के आसपास के सारे पार्कों तक अपने विभाग द्वारा वहां पर ट्रीटेड वाटर की लाइन डालकर पार्कों में देंगे ताकि पार्कों में पानी की दिक्कत ना हो। इसी के लिए अभी हमने

यहां पे यमुना विहार में कौन सा एरिया है वो विधायक को मैं बाद में बताऊंगा ताकि वो आप ही का है।

....व्यवधान.....

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: आपके यहां पे भी हो गया।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: एक मेरे यहां पर भी...।

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: इसके लिए हमने 74 पार्कों का टेंडर भी कर दिया अध्यक्ष जी और जिसका साइज एक एकड़ से ऊपर है ऐसे 74 पार्कों की हमने जो है टेंडर भी कर दिया, अवार्ड भी कर दिया, लाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा, अब आप देखिए जब हम 1000 एमजीडी पानी को 1000 एमजीडी सीवेज को ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं कि वो अच्छा ट्रीट हो जाए अच्छा पानी निकल जाए अब उस सारे पानी को यमुना में छोड़ देना नालों में छोड़ देना, यह कोई समझदारी नहीं। वह सारे पानी को कहां-कहां पे यूज़ कर सकते हैं? दिल्ली के हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, दिल्ली के हम सारे पार्कों में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी अगर सूर्य भगवान ने चाहा, अगर शनि भगवान ने यमराज जी ने चाहा तो बहुत ही जल्दी हम यह भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि ये सारे एसटीपी के ट्रीटेड वाटर को दिल्ली की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी यूज़ करने के लिए परमिशन दें। ताकि सबसे पहले तो हम अपने सरकारी बिल्डिंगों में इस पानी को यूज़ करें। बहुत सारी बिल्डिंग इसलिए जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि खारा पानी होता है क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता, कहीं ना कहीं से पानी लेके आते हैं, पानी की टेस्टिंग होती नहीं है, नीचे का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो बिल्डिंग जल्दी खराब हो जाती है। मगर ये सीवर का पानी तो जो है कोई खारा नहीं होता, मीठा ही होता है ना, हमारा नहाने का, किचन का, बाथरूम का पानी होता है। तो उसी पानी को अगर हमने ट्रीट किया तो वह खारा पानी नहीं है, मीठा ही पानी है उसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। तो यह भी काम हम दिल्ली में लेकर आ रहे हैं। कैसे हजार के हजार एमजीटी को पूरा ट्रीट करके दिल्ली में उपयोग में कैसे लाया जा सके ताकि दिल्ली की आपूर्ति हम इससे पूरी कर सकें। अब लोग सारे मीठे पानी को यूज़ कर रहे हैं दिल्ली के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, जब हम इस पानी को हम सबको परमिशन देंगे तो वो पानी की खपत बचेगी। दिल्ली के पार्कों में यह सारा पानी यूज़ हो रहा है। जो बड़े-बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, स्विमिंग पूल में रहते हैं। वहां पर यह सारे पानी को मीठे पानी को यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस पानी को अच्छा कर देंगे तो दिल्ली में कितना सैकड़ों एमजीडी पानी

हमारा मीठा पानी बचेगा। उस सारे पानी को हम दिल्ली में पीने के लिए और ज्यादा उपयोग में ला सकते हैं। ऐसी योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। दिल्ली में सोच की कमी थी, मैनेजमेंट की कमी थी। आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यह सारे कामों के ऊपर में कदम उठा रही है। जिससे आपको आने वाले सालों में फर्क दिखाई देगा। पिछले एक साल में 60 लार्ज न्यू ट्यूबवेल हम लोग

लगाकर 10 एमजीडी पानी हमने बढ़ाया और अभी 203 नए बोरवेल के ऊपर में हमारे टेंडर हो चुके हैं जिससे हमको 36 एमजीडी पानी और मिलेगा। तो ऐसे ऐसे एक और अभी जैसे संजय गोयल जी कह रहे थे, कहां बैठे संजय जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं सारे जो है दिल्लीवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर भी आपको सुना रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा बोरिंग के ऊपर में यह चलता है, वह चलता है। ऐसे नोटिस बैठे, जो अशोक गोयल जी ने भी कहा। तो कोई पैसा भी मांगता है, कहीं से पैसा मिल जाता है तो उसको नहीं काटते, नहीं मिलता तो काट देते हैं। ये सब चल रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली में कितने बोरवेल हैं लोगों ने अपने घरों में कितने बोरवेल कर रखे हैं, कोई गिनती नहीं। सरकार बहुत ही जल्दी नई पॉलिसी लेकर आ रही है। सारे बोरवेल को जो भी डोमेस्टिक के लिए बोरवेल को अपने घर में लगाना चाहता है। आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी ने कहा जब हम वहां पर बैठे थे सारे मंत्रीगण, तो बात यह आई कि यह सारे लोग वहां पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद में डीएम साहब की जो कमेटी होगी वह उनको परमिशन देगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा किस बात की परमिशन भाई? अगर कोई भी अप्लाई करता है उसको डोमेस्टिक बोरवेल की कनेक्शन दो। यानि दिल्ली में अगर किसी के पास परमिशन नहीं होगी तो उसके ऊपर में केवल कार्यवाही होगी। जो हमसे घर के लिए बोरवेल की परमिशन मांगेगा सारे लाखों घरों को नए बोरवेल की परमिशन देंगे। केवल इसमें एक छोटी सी बात बोरवेल का थोड़ा सा शुल्क, थोड़ा सा शुल्क थोड़ा सा शुल्क दिल्ली वालों को ताकि वह जो भार उसको ट्रीट करने का सीवर को ट्रीट करने का जल बोर्ड उठाएगा उसके लिए भी हमको पैसा चाहिए। केजरीवाल जी 70 हज़ार करोड़ में डूबा कर गए दिल्ली जल बोर्ड को। अब हमको थोड़ा बहुत तो दिल्ली के हमारे भाई बहनों का सहयोग चाहिए। तो सभी को अब आप जो है एक एक लाख दे रहे हैं, आप जो है इल्लीगल चला रहे हैं, आपसे एक एक लाख कोई मांग लेता है, कोई भी मांग लेता है, कोई विभाग चला जाता है भैया आपको यह नोटिस है, फलाना है, एक लाख भी कितना, कोई भी मांग लेता है। ये सारे झगड़े खत्म। जैसे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कहा कि आपको रेस्टोरेंट चलाने के लिए

पुलिस की परमिशन नहीं चाहिए। इतनी सारी हजारों परमिशन एक साल में खत्म कर दी गई है सरकार में। आज ये सारी परमिशन भी खत्म।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कंक्लूड कर दो आप।

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: बोरवेल जिसको चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब प्रवचन भाग दो में कर लीजिएगा।

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: मतलब मैं तो इतनी अच्छी-अच्छी बातें बता रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप।

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: तो इसी के साथ, इसी के साथ अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं मैं अभी इसको क्लेरिफाई कर दूंगा।

श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय जल मंत्री: चलिए मैं मैं जो है मैं इसको खत्म करता हूं। अब आपने बोला एक और अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी बता देता हूं। एक और अच्छी बात कर रहे हैं कि जैसे आप यह देखते हैं कि आपका बैंक में अकाउंट होता है तो आपका केवाईसी होता है, आपको हर साल केवाईसी कराना पड़ता है अपना एड्रेस, फोन नंबर, सारा डाटा उसको अपटूडेट, तो दिल्ली जल बोर्ड में सिस्टम नहीं था। कौन सा कनेक्शन है, किसके नाम है, क्या एड्रेस था, आदमी की डेथ हो गई। फिर कौन आया, किराएदार आया, क्या नंबर है, कोई मालूम नहीं। इसीलिए जो हम यह ले के आए थे एलपीएससी माफ करने की स्कीम, तो हम कहां पर बिल भेज रहे हैं वहां पर कोई रहता, नहीं रहता, फोन नंबर कोई नहीं। अब हमने ई केवाईसी कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली के सभी हमारे जो भी हमारे क्लाइंट हैं, जिनके पास भी कनेक्शन है ताकि पूरा डाटा अप टू डेट, हर घर का उसका एड्रेस, उसके मालिक का नाम, मकान मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, यह पूरा अप टू डेट। यह आज तक कभी नहीं हुआ 20 साल में, 25 सालों में। यह काम भी हमने कराना शुरू किया। अध्यक्ष जी, मैं आखिर में एक बार फिर से क्योंकि बिना प्रधानमंत्री जी, बिना गृह मंत्री जी के सहयोग से मेरा विभाग का काम तो नहीं हो सकता, जितना पैसा एनएमसीजी से मिलता है, जितना पैसा जो केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलता है, वो पैसा ना मिले, हम यह यह काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप हमको इतना पैसा दे रहे हैं जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं। एक बार मैं

आपके माध्यम से आज पूरे दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हम अगर एक-एक व्यक्ति एक-एक घर में यह संकल्प कर लें, दिल्ली में ढाई करोड़ की पाप्यूलेशन रहती है, ढाई करोड़ लोग रहते हैं। हर व्यक्ति अगर यह संकल्प कर ले कि मैं दिन का एक लीटर पानी बचाऊंगा, या मैं एक लीटर पानी बचाऊंगी, ढाई करोड़ लीटर पानी बच जाता है। हम अपने नहाने में, बाथरूम में, मुंह धोने में, हाथ धोने में। जब हम किसी घर जाते हैं या मेरे विभाग में कोई भी मीटिंग में वहां पर अधिकारी होते हैं, जनता आती है उनको पानी तो वह पानी का गिलास वो आधा पीते, आधा छोड़ देते हैं। ऐसा हर व्यक्ति अगर यह संकल्प कर ले कि मैं दिन का एक लीटर पानी जितना मैं यूज़ कर रहा हूं वह एक लीटर पानी बचाऊंगा। यह मैं सारे दिल्ली वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है हम केवल वाटर मैनेजमेंट करेंगे अच्छा होगा। मैं सीएजी साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि वह यह सारी फाइंडिंग्स को दिल्ली की जनता के सामने लेकर आए हैं और एक बार फिर से मैं यहां पर जो दिल्ली के रहमान डकैत हैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर हम दिल्ली को आबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वह दो भागों में इसमें जो नोट किया जाए। पहला जो है वह है रिपोर्ट संख्या 3, 2025 में जो सीएजी पर दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज का विस्तृत विवरण दिया है 17 से 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि, उस पर उनका उनका जो प्रतिक्रिया है वह है एक। और एक आइटम इसमें और जोड़ी जाए बुलेटिन में 271 बी में मंत्री जी का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रम सारे बताए हैं तो जिससे कि यह रिकॉर्ड पर प्रॉपर्ली सारी चीजें दो भागों में आए और यह सीएजी की जो चर्चा का है वह उसको सीएजी की चर्चा के उसमें ही जोड़ा जाए और इसको 271 बी से एक अलग से स्टेटमेंट लगाया जाये इसमें रिकॉर्ड में। अब माननीय सदस्य श्री अजय महावर जी।

<u>सी.ए.जी.रिपोर्ट पर चर्चा</u> (...जारी)

श्री अजय महावर, माननीय मुख्य सचेतक: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने दिल्ली जल बोर्ड सीएजी रिपोर्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया यह प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च को रखा था। दो लाइन से शुरू करता हूं। पिछली सरकार विज्ञापन की सरकार थी, झूठे वादों का दौर था, विज्ञापन की सरकार थी, झूठे वादों का दौर था, हकीकत में पानी गंदा और सिस्टम पूरा कमजोर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएजी की यह रिपोर्ट पिछली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाती है। पिछली सरकार के पानी, सीवर, वित्त के कुप्रबंधन को उजागर करती है। आज मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, यह किसी अखबार की हेडलाइन नहीं है। यह सीएजी की वो गंभीर रिपोर्ट है जो पिछली सरकार के कामकाज का आधिकारिक आईना है। जो 2017-18 और 21-22 तक के दिल्ली जल बोर्ड के निष्पादन लेखा परीक्षा पर आधारित है। यह रिपोर्ट साफ कहती है कि पिछली सरकार दिल्ली के नागरिकों को निरंतर स्वच्छ पेयजल, पूर्ण सीवरेज सुविधा और कुशल वित्तीय प्रबंधन देने में पूरी तरह से असफल रही है। सवाल यहां पक्ष या विपक्ष का नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता के हक का है, पानी का है, यमुना सफाई का है, हजारों करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का है। अध्यक्ष जी] 27 साल हम दिल्ली में सत्ता में नहीं रहे, बाहर थे लेकिन पिछली सरकारों ने नकारापन की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली में जब आदरणीय मदन लाल खुराना जी की सरकार थी तब नवंबर 1994 में यमुना जल बंटवारे के तहत रेणुका, किशाऊ और लखवार जैसे बांध बनाने का प्रावधान बना ताकि दिल्ली को और उसके नीचे राज्यों को अतिरिक्त जल मिल सके। सीएजी रिपोर्ट यह बताती है कि रेणुका बांध के लिए ₹214.84 करोड़ रूपये किशाउ के लिए 8.10 करोड़ रूपये और लखवार के लिए 7.7 करोड़ रूपये यानि कुल मिलाकर ₹230.73 करोड़ इन बांधों के लिए दिए गए। लेकिन 30 साल बाद भी आज इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ। ये 27 साल पुरानी सरकारें इस गुनाह के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के पैसे जा रहे लेकिन पानी नहीं आ रहा है और केवल योजना ये केवल योजना की विफलता नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये अंतर-राज्यीय वार्ता और फॉलो अप की नाकामी भी है। क्या ये पिछली सरकारों का राजनीतिक दायित्व नहीं बनता था। क्या उन पर प्रश्न खड़े नहीं होते और दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 वह भी हमारी सरकार की समय की बात है। जब धारा आठ के अनुसार जल परामर्श परिषद बनना था। लेकिन उसमें पंचवर्षीय योजना हो, Administration

हो, financial हो, टेक्निकल हो, इस पर advice के लिए योजना बनाने के लिए इसकी गठन की बात थी, ये भी नहीं हुआ। 2011 में ये सीएजी कह रहे हैं हम नहीं कह रहे अधिकारी की रिपोर्ट में कि जो जल नीति पर draft बना 2011 में, वह भी कभी भी आज तक अधिसूचित नहीं हुआ। इन लोगों ने दिल्ली की हालत ये बना दी कि एक माँ उठकर सुबह कहती है कि बेटा पढ़ लिख ले नहीं तो तुझे भी पानी की लाइन में लगना पड़ेगा। ये स्थिति बना दी। अध्यक्ष जी, पिछली सरकारों की नाकामी का। आलम के अलावा। दिल्ली में जब पानी हरियाणा बॉर्डर से अध्यक्ष जी एंट्री लेता है तो वहीं से टैंकर माफियाओं की मिलीभगत और चोरी शुरू होती है। पिछली सरकारें कहती रही अपनी रिपोर्ट में ही कि 52% जल वेस्ट जाता है। वो वेस्ट जल के पीछे चोरी भी है अध्यक्ष जी। कहीं न कहीं टैंकर माफियाओं से मिलीभगत भी है और उसका प्रमाण ये है कि 2017-18 और 21-22 में अध्यक्ष जी, 30% गाड़ियों में ही जीपीएस लगा था, 70% गाड़ियों के सरकारी टैंकरों में जीपीआरएस नहीं लगाया गया और ये सिर्फ चोरी के लिए ये खेल खेला गया। अब जब रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है मुख्यमंत्री जी और हमारे जल मंत्री प्रवेश जी, इन्होंने टैंकारों में 100% जीपीआरएस लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता की ओर से बधाई देता। जैसा दिल्ली को पता है कि यहाँ के अनुमानित आबादी के हिसाब से अभी मंत्री जी भी कह रहे थे 1200 एमजीडी पेयजल की जरूरत है, लेकिन less than एक हजार एमजीडी पानी आता है, लेकिन सरकार की ये रिपोर्ट कहती है कि पानी अगर चोरी और वेस्ट रोका जाए तो भारी गैप को पूरा किया जा सकता है। एक तो पानी की किल्लत, ऊपर से नमूने इनके फैल होते रहे। जो पानी दे रहे हैं उसके भी हालात खराब थी। जो दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक रिपोर्ट है, वह भी आठ लैब्स में इन्होंने 16,234 नमूनों की जांच कराई अध्यक्ष जी और उसमें से 8935 नमूने पानी के फेल हो गए। ये बड़े शर्म की बात है दिल्ली के लिए और जो कि 55% लगभग बैठता है। ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, ये तो दिल्ली सरकार की जल बोर्ड ने ही। अध्यक्ष जी आप भी थे उस समय नमूने में आई थी ये बात। अध्यक्ष महोदय, सीवर यमुना जी की हालत तो खराब है। और 594 एमजीडी जो सीवरेज जेनरेशन होती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बताती है मार्च 2022 की रिपोर्ट में कि 1080 अनऑथोराईज्ड कॉलोनी के उत्पन्न से 212.5 एमजीडी सीवरेज बिना किसी शोधन के ही स्टॉर्म वाटर नालों के माध्यम से सीधे यमुना में जाकर के यमुना माँ को गंदा कर रहा है। 25 एसटीपी तो मानक पर ही खरे नहीं है और पिछली सरकार क्लीन यमुना की सिर्फ बातें करती रही। बल्कि आपको ध्यान होगा अध्यक्ष जी, पिछले सदन में जब ये बात उठी थी कि केंद्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने चिट्टी लिखी थी यमुना जी पर जो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए दिए केंद्र सरकार ने, सफाई नहीं हुई, वो पैसे कहाँ गए, कौन डकार

गया? आज तक पता नहीं, लेकिन गजेन्द्र शेखावत जी ने जब जवाब मांगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देते कहाँ से, जवाब होता तो देते। इनके पास कोई जवाब नहीं था इसका अध्यक्ष जी। भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम ये है अध्यक्ष जी कि दिल्ली वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एरिया के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 2243 करोड रूपये 2243 करोड रूपये अध्यक्ष जी फंडिंग स्वीकृत थी, लेकिन क्या देरी थी, क्या खामियां थी और क्या उसके पीछे का हिडन एजेंडा था? क्या कोई भ्रष्टाचार का एजेंडा था जो उसको किस कारण से ये वापस लेनी पड़ी? यानी कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से मिला हुआ हजारों करोड़ रुपए का भरोसा भी खो दिया। ये प्रशासनिक चूक नहीं...

(समय की घंटी)

श्री अजय महावर : बल्कि दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं सीएजी ये भी कहती है एक कंपनी थी मेसर्स विप्रो प्राइवेट लिमिटेड। दिसंबर 2017 में ये 81.56 करोड का एक कांट्रैक्ट साइन करती है और कांट्रैक्ट साइन करने के बाद निर्धारित समय पर काम नहीं करती। उस पर 10% की पेनाल्टी लगनी थी, यानी आठ करोड से ज्यादा की पेनल्टी लगनी थी अध्यक्ष जी, लेकिन इन लोगों ने एक रूपये की penalty पलटी नहीं लगाई और पूरे का पूरा भुगतान कर दिया अध्यक्ष जी। इसके पीछे क्या कोई kickback money थी या क्या कारण था ये आज तक नहीं बताया गया। इतना ही नहीं 2017 में 281 इन्होंने टैबलेट खरीदे। एकल बोली पर खरीद लिए। एक करोड 52 लाख रूपये जो 43.09% प्रतिशत अधिक थी। इन्होंने एकल बोली से खरीद लिए। सीएजी की रिपोर्ट पैरा 6.3.2 के अनुसार ये लगभग 66,595 करोड़ का कर्ज मार्च 2022 तक के वित्तीय कुप्रबंध के कारण खड़ा हुआ जो अब 71,000 करोड़ से भी ज्यादा है अध्यक्ष जी और इस इस दौरान नॉन रेवेन्यू वाटर से भी दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 4988 यानी 5000 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ। मतलब हिसाब मांगा तो कागजों में उलझाया, सवाल उठाया तो मुद्दों से भटकाया दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद कर कर्जों का पहाड़ बनाया और दिल्ली वालों को पानी और सीवर के लिए सिर्फ रुलाया ही रुलाया, सिर्फ रुलाया ही रुलाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी दस्तावेज नहीं है। ये कम पानी, गंदा पानी, बिना ट्रीटमेंट का सीवेज, डूबता हुआ जल बोर्ड, बढ़ता हुआ कर्ज, भ्रष्टाचार का मर्ज, ये दिल्ली के हर नागरिक की पीड़ा का दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय। ये दिल्ली के हर नागरिक की पीड़ा का दस्तावेज। माननीय अध्यक्ष महोदय सीएजी की कड़ी टिप्पणियां बताती है कि पिछले विज्ञापन वाली सरकार ने जमीन पर जल और सीवर

प्रबंधन में पूरी तरह से फैल रही उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को भी इंगित किया है। मैं सदन से आग्रह करता हू इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेते हुए आप इसको जरूर पढ़ें और एक समयबद्ध निगरानी तंत्र बनाया जाए। दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी.....

माननीय अध्यक्ष: चलिये।

(समय की घंटी)

श्री अजय महावर: और माननीय जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन होगा और दिल्ली की जनता को उसके हक का साफ पानी और बेहतर सीवर सुविधा मिल पाएगी। आपने अध्यक्ष जी मौका दिया आपका बहुत, बहुत हृदय से धन्यवाद। आभार।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेंद्र गुप्ता) पीठासीन हुए।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सीएजी पर माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह:अध्यक्ष जी सबसे पहले तो जिस दिन से सदन चालू हुआ है आपकी ड्रेस रोज चेंज होके आती है स्पेशल कोई डिजाइनर है जो अध्यक्ष जी की जब शुरू होती है विधानसभा तो एक-एक दिन डिजाइनर अलग-अलग डिजाइन के होते हैं। इसके लिए हम और आपका चेहरा भी अध्यक्ष जी आपका चेहरा भी खिला रहता है। ये भी है।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चर्चा को आगे बढ़ाइए।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह, माननीय: एक एक जैकेट हम लोगों को भी दे देनी चाहिए। अध्यक्ष जी आज बड़ा गंभीर मामला जो मंत्री जी ने अभी आपके सामने रखा उसको आगे बढ़ाता हूं और अजय महावर जी ने दिल्ली में 11 साल अध्यक्ष जी, 11 साल दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान पे नुकसान नुकसान पे नुकसान और एक दिन ऐसा आया 2025 में जब हमारी सरकार बनी तो 70 हजार करोड़ दिल्ली जल बोर्ड का नुकसान अध्यक्ष जी 70 हजार करोड़ दिल्ली को कई

साल पीछे छोड़ गए। 11 साल में दिल्ली जल बोर्ड को अध्यक्ष जी 11 साल दिल्ली जल बोर्ड का खोखला कर दिया। जहां पर डैम बनना चाहिए थे, बांध बनने चाहिए थे तीन-तीन पास हुए। रेणुका बांध 2014 करोड़, 84 लाख, केशु बांध 8 करोड़ 10 लाख, 8.10, लेखवार बांध 7.7 करोड़। कुल मिलाकर अध्यक्ष जी 230 करोड़ दिए थे। इसके बावजूद 11 साल में क्या 30 साल में कोई बांध नहीं बना अध्यक्ष जी। जब सेंटर मंत्री जी ने उनसे पूछा शेखावत जी ने कि दिल्ली जल बोर्ड का हिसाब क्या है, तो उस टाइम के मुख्यमंत्री ने उनके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया अध्यक्ष जी इससे बड़ी बात क्या है। और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि 2015 से लेके 2024 तक सीएजी की रिपोर्ट सदन पटल में नहीं रखी गई अध्यक्ष जी। इससे क्या साबित करना चाहते हैं थे। साबित ये करना चाहते थे कि हां दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार फैला जा रहा है उसको उजागर नहीं करना चाहते थे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी इसी बात पे नहीं एक कंपनी को टेंडर दिया गया 836 करोड़ का, कंपनी का नाम भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। विपरो प्राइवेट लिमिटेड। 2017 में 81.56 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कंपनी से, निर्धारित समय पर काम नहीं किया गया। उसके लिए सरकार की तरफ से 10% की पैनल्टी होती है अध्यक्ष जी। लेकिन इन्होंने पैनल्टी नहीं ली और उसका भुगतान पूरे का पूरा कर दिया जितने का काम 81.56 का पूरा भुगतान कर दिया अध्यक्ष जी। उससे सरकार को 8 करोड़ का जो उन्होंने जुर्माना भरना था वो भी नहीं भरा अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी और छोड़ो कोई एसटीपी ट्रीटमेंट जो अभी हमारी मुख्यमंत्री जी ने और प्रवेश वर्मा जी ने मंत्री दिल्ली जल बोर्ड ने इतना बजट सीवर को दिया उसके ट्रीटमेंट के लिए और अभी बताया भी गया यहां पर मंत्री जी ने कि किस तरह उस सीवर के पानी को साफ करेंगे और पार्कों के लिए इस्तेमाल होगा। लोगों की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगा और लोगों को जो बाथरूम में पानी होता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। ऐसी परियोजना जो रेखा गुप्ता सरकार लेकर आ रही है, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी कि 11 साल का जो कार्यकाल था दिल्ली के लिए एक भयानक कार्यकाल था। लोग कोरोना में, अध्यक्ष जी लोग कोरोना में किस तरह दिल्ली की हालत थी यह हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए नहीं हिंदुस्तान में कोरोना का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरी टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोरोना के टाइम सड़कों पे घूम रही थी, वालंटियर बनके काम कर रही थी। लेकिन ये घर में सोया हुआ था। आलीशान जो बंगला मैडम ने अभी, रेखा गुप्ता जी ने बताया वो शीश महल, शीश महल आज लोग देखने को तरस रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहूंगा उसकी टिकट लगा दें जिससे कि कुछ दिल्ली

सरकार को आ जाए.... और उसका जो रेवेन्यू आ जाए और साथ में जो उसके काले कारनामे हैं वह लोगों में उजागर हों।

अध्यक्ष जी, इससे ही नहीं अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो आज करने जा रही है एक साल में मैं रेखा गुप्ता जी की सरकार को बधाई देता हूं रेखा जी को कि आपने दिल्ली जल बोर्ड के हर एमएलए को कम से कम किसी को 40 करोड़, किसी को 50 करोड़, मेरे यहां पर भी कम से कम 120 करोड़ रूपया सीवर का आया है, मैं रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। कहां था 11 साल, कहां गया था केजरीवाल? 11 साल केजरीवाल क्या करता रहा? आलीशान बंगले में बैठ के ऐश करता रहा। कहां क्या नहीं हुआ वहां पर? महिला का योन शोषण हुआ, अपमान हुआ और उसी की महिला जो राज्यसभा की सदस्या थी स्वाति मालीवाल.....

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, वो भी झगड़ा मुझे पता है। किस बात पे हुआ, लेकिन मैडम अब बैठे हैं, कुछ महिलाएं हमारे यहां बैठी हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मेरे को मालूम है, 100% बिल्कुल मालूम है, अध्यक्ष जी, वो झगड़ा क्या था मुझे मालूम है और भ्रष्टाचार का भी झगड़ा मुझे मालूम है अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: ये सारी गेम जो थी, अध्यक्ष जी, ये सारी गेम जो थी, दो चीजों की थी, एक भ्रष्टाचार का पैसा कहां था और दूसरा जो संबंधों की बात थी केजरीवाल की, जो संबंधों की बात थी, जो महिलाओं का शोषण करने की बात थी, यह दो कैटेगरी थी जो आलीशान महल जो इसने बनाया।

अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या किया एक साल में। दिल्ली जल बोर्ड की लाइनें....

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): अभी आप जब बजट भी बोलेंगे न, तो ये तो हो गई बात। आगे....

....व्यवधान....

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अभी कहां हुई अध्यक्ष जी। अभी....

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): नहीं-नहीं मैं फिर, समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा न। फिर कैसे बनेगी बात।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः या तो मुझे समय दिया करो पूरा या मत दिया करो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): नहीं, 5 मिनट का समय प्रत्येक सदस्य के लिए है। आपके 8 मिनट हो गए हैं।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, जब मंत्री जी 50-50 मिनट अध्यक्ष जी बोल सकते हैं, हम भी कोई एमएलए जीत के ही आए हैं ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): नहीं नहीं, देखिए.....

....व्यवधान.....

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः तो उसमें थोड़ा टाइम का तो वो करो ना। हम भी एमएलए जीत के आए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): चेयर की जो रूलिंग है वो साफ है पांच मिनट प्रत्येक सदस्य के लिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः मैं अभी खत्म कर देता हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी अभी मैं खत्म कर देता हूं।

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): चलिए, कन्क्लूड कर दीजिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, आज हमारी सरकार, पूरे जो इसके कारनामे थे वो सारे कारनामे उजागर भी हो रहे हैं। आज सड़कों पर गाली दी जा रही है कि हमारे साथ क्या करके गया है। 5 साल बिल इसने, 7 साल कोरोना के लोगों को कहता रहा, इलेक्शन भी मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं, कहता था मुझे जिताओ तब मैं आपके बिल माफ करूंगा अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ये बात कहता था। तो इसलिए पूरे 11 साल दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाला

आज क्यों नहीं आ रहा सामने, कि आज सीएजी की रिपोर्टें आ रही हैं। आज फलानी रिपोर्टें आ रही हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): चलिए। बस।

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैं ज्यादा ना कहता हुआ अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): धन्यवाद। माननीय सदस्य- श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल: अध्यक्ष जी, आपका विशेष धन्यवाद, आपने सीएजी रिपोर्ट के जल बोर्ड के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया। और जब जिस दिन मैं विधायक बना अध्यक्ष जी उस दिन मेरे पास 100 कंप्लेंट आईं दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित और मैं सोचने लगा यह हो क्या रहा है, ये तो सुबह से शाम तक कंप्लेंट ही कंप्लेंट। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय जल मंत्री जी का हम धन्यवाद कहते हैं कि वह संख्या मात्र 20 तक रह गईं और वह भी आने वाले समय में वो जो कंप्लेंट्स की संख्या हैं वह भी कम हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं और लगातार मैनेजमेंट के सिस्टम से काम हो रहा है। जब हमने यह सीएजी रिपोर्ट जो पढ़ी, जो सात अध्याय में लिखी हुई है, इस, एक-एक अध्याय सीएजी रिपोर्ट में उनके भ्रष्टाचार, कुशासन, मैनेजमेंट सिस्टम का फेलियर दर्शाता है। और समय पर उन्होंने किसी भी सेक्टर में, यदि हम वाटर लीकेज की बात करें तो 935 एमजीडी पानी की प्रोडक्शन 2022 में हुई। 2022 तक की रिपोर्ट है। 5 सालों की रिपोर्ट है। लेकिन यूजीआर तक जो पानी पहुंचा 742.81 एमजीडी यूजीआर तक पहुंचा जो कि 20.56% वाटर लॉस रहा। यदि हम बात करें एसटीपी प्लांट की तो 35 एसटीपी प्लांट आपके वर्किंग में हैं। जिसमें से 697 की कैपेसिटी रही और अवेलेबल 622 रहा और यूटिलाइज 545 एमजीडी का रहा और जो कि 9200 किलोमीटर की ये पाइप लाइन के माध्यम से हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब विधायक बना तो मेरे को कुछ समस्याएं शुरू में आईं तो मैंने समझा, वो उन्होंने अधिकारियों ने बताया कि सीवर ओवरफ्लो इसलिए हो रहे हैं कि सीवर की पाइप लाइन साफ हो रही है। लगातार डेढ़ महीने वो इधर से उधर होता रहा तो मैंने कहा भई इसका देखना चाहिए कारण क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री का होने के नाते व्यवस्थाओं की पता है क्योंकि ऐसे एसटीपी प्लांट अपनी इंडस्ट्री में भी लगे हुए हैं। तो मैं जब देखने गया तो एक ऐसा काला अध्याय वहां देखने को मिला कि दिल्ली सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिनके

आपके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं वो 90 एमजीडी पानी साफ करके क्रिस्टल क्लियर पानी आपके यदि सामने रख दिया जाए तो आप पी लेंगे और उसको शाहदरा ड्रेन में डाला जा रहा था, गंदे नाले में डाला जा रहा था, ये इनकी, जबकि 90 एमजीडी पानी कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यह इनके कुशासन की भ्रष्टाचार की स्वयं मैंने देखा और मैंने जब अपनी इस बैठक में इस विषय को भी कहा।

और ऐसा यदि हम देखें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके अंदर भी जो आपके जो अकाउंट्स ऑफिसर जिनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, भई जो बिल यदि जनरेट हुए हैं उनकी व्यवस्थाएं करनी हैं किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, उसमें आपके 90 में से ओनली 25 असिस्टेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट ऑफिसर रहें, लगभग 65 गायब, पूरी दिल्ली को सिर्फ 25 लोगों ने देखा। तो आप यह देखिए ये समझ सकते हैं कि रेवेन्यू का लॉस किस तरह से इन्होंने पहुंचाया दिल्ली की सरकार को, जनता के पैसे का रेवेन्यू का लॉस किस तरह से इन्होंने पहुंचाया।

इस तरह से इर्रेगुलर हायरिंग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 1530 की संख्या इन्होंने सीएजी ने स्पष्ट लिखा। अनेकों अनेक विभाग में एमटीएस के नाम पर 1530 लोगों को रख लिया और 1530 को बिना किसी सिस्टम के रख लिया जो भी एक बहुत बड़ा आपके भ्रष्टाचार को दिखाता है, दर्शाता है।

इसी तरह से स्टाफ जो इनको रखना चाहिए था क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है, जीवन ही नहीं है। इन्होंने 24 हजार 93 जो रिक्वायरमेंट है उसको मात्र 16 हजार 354 ही फिल कर पाए, 7754 वैकेंसी वह खाली रहीं। यह 2022 की रिपोर्ट है माननीय अध्यक्ष जी।

और साथ में जो पीने के पानी का आपके आउटस्टैंडिंग पीने का पानी का जो बिलिंग होनी है, 371 एमजीडी जो कि 40% पीने के पानी का बनता है वो अमाउंट उसमें से 244 एमजीडी के पानी के बिल ही मीटर रीडिंग के माध्यम से जनरेट हुए। आप समझ सकते हैं 950 एमजीडी पानी और बिलिंग आपके 244 एमजीडी, कितना डिफरेंस है इसके अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, एक, और इसी तरह से इसी की वजह से जो लोन था, आपके आउटस्टैंडिंग लोन उसके अंदर सीधे-सीधे माननीय अध्यक्ष जी 66,595 करोड़ में से 34,540 का आपके एक्चुअल लोन और साथ में 32,000 का उसमें इंटरेस्ट का लोन।

इसी तरह से आप देख सकते हैं अध्यक्ष जी कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का आलम बनाए रखा और आलम बनाने के साथ-साथ क्योंकि दिल्ली में तो रहते ही नहीं थे। हर राज्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रहती थी। प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे। दिल्ली को इन्होंने

बर्बाद कर दिया और साथ में माननीय अध्यक्ष जी केंद्र सरकार ने इनसे कहा था 2013-14 के अंदर जब इनकी सरकार बनी, 15 के अंदर तब इनसे कहा था कि वाटर पॉलिसी लाइए दिल्ली की और वाटर पॉलिसी आज तक उन्होंने जब तक सरकार में रहे 2025 तक कोई वाटर पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई। ऐसे ही आपके जो, आपके जो टैंकर्स थे, जिन पर जीपीएस लगना था, जो इन्होंने अपने चेलों के, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के टैंकर्स को लगाया था किसी पे सिस्टम में जो जिससे कि जीपीएस ट्रैकर्स इसलिए नहीं लगाए जिससे की पानी की चोरी को बढ़ावा और दिया जा सके और इसी तरह से जो इनकी जो आपके जो कंप्लेंट्स आती थी। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कंप्लेंट को जो पूरा करने का समाधान का 154 दिन से 2152 दिन तक 2152 मतलब 6 साल कंप्लेंट का आपके जो करना है कि ये ठीक हो गई है 154 दिन से यह स्थिति थी इनकी आपको बताएं। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, जो अपना वाटर है उसका जो ट्रांसमिशन लॉस, जो पानी गायब हो जाता है जमीन के अंदर वो भी 20.56% का लॉस रहा। इसीलिए इन्होंने कोई rain water harvesting system जो जमीन में पानी जाना चाहिए बरसात का वह पानी की भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जिससे की भूजल हमारा बढ़े। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे अनेकों अनेक विषय यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह जो सरकार है काम की राजनीति नहीं प्रचार की राजनीति करती थी और जमीन पर विफलता, टीवी पर सफलता इनका उद्देश्य था और सिर्फ और सिर्फ जनता को इस मैं यह कहता हूं आपके माध्यम से इस सीएजी रिपोर्ट में जितने विषय हैं इनकी नाकामियां हैं, कुशासन है जो कहते थे कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। इन्होंने दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कारवाई की जाए जिससे आने जिससे इनको पता लगे कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बहुत बढ़िया, माननीय सदस्य श्रीमती शिखा रॉय। सभी को समय का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है इस बैठक का इस सीटिंग का तो लास्ट सीटिंग है आज और एजेंडा बहुत सारा अभी बाकी है। अभी बजट पर पूरी चर्चा बाकी है। तो सबसे ही अनुरोध है मैं टोकूंगा हर एक को अब मतलब समय को लेके।

श्रीमती शिखा रॉय: माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय है यह जो सीएजी की रिपोर्ट जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर आई जो 2017-18 से 2021-22 का लेखा-जोखा देती है। यह रिपोर्ट साधारण रिपोर्ट नहीं है, यह दिल्ली की जनता के साथ हुए विश्वासघात का दस्तावेज है।

सीएजी की रिपोर्ट साफ कहती है कि दिल्ली में पानी की कोई कमी अचानक नहीं आई। यह समस्या अचानक अचानक ही नहीं बनी थी बल्कि यह वर्षों की गलत नीतियां और लापरवाही का परिणाम है। 2017-18 से 20-21 के बीच पानी की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर लगातार बढ़ता गया। potable water की कमी 24% से बढ़कर 26% हो गई। सवाल यह है कि जब सरकार को समस्या दिख रही थी तो समाधान साथ-साथ क्यों नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इतनी बड़ी राजधानी में जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वहां एक स्पष्ट वाटर पॉलिसी तक नहीं बनाई गई। water consultative council तक का गठन नहीं किया गया। यानी बिना दिशा, बिना योजना दिल्ली की जल व्यवस्था को चलाया गया और इसका खामियाजा यहां की जनता भुगत रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पानी की measurement और मॉनिटरिंग प्रणाली बहुत कमजोर थी। कई water treatment plant, reservoirs, UGRs, water emergencies और बोरवेल्स पर फ्लो मीटर्स या तो लगे ही नहीं थे या कार्यशील नहीं थे या calibrated नहीं थे। जब तक आप यह नहीं जानते कि पानी कितना आ रहा है या कितना जा रहा है तो लीकेज और चोरी कैसे रोकेंगे। यही कारण है कि ट्रांसमिशन लॉस 16% से बढ़कर 21% हो गया। स्थिति यही नहीं रुकती, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी से निकलने वाला 212 एमजीटी से ज्यादा सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ड्रेंस में जा रहा था। 25 एसटीपीस का ट्रीटेड वाटर भी स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं उतर रहा था। यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता ही नहीं है, यह दिल्ली की सेहत और यमुना जी के साथ खिलवाड़ था। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्थिति भी उतनी ही चिंताजनक है। नॉन रेवेन्यू वाटर 50% से ज्यादा रहा जिससे लगभग 5000 करोड़ का नुकसान हुआ और इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड का कर्ज का बोझ 66,000 करोड़ तक पहुंच गया। यह बताता है कि व्यवस्था सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी, वित्तीय रूप से भी चरमराई हुई थी। सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी की पूरी कमी थी। 2021-22 में उत्पादित पानी का केवल 40% ही बिल्ड हुआ और इसमें यानी बिलिंग सिर्फ 40% की हुई और उसमें भी केवल 66% मीटर रीडिंग पर आधारित था। यह साफ दिखाता है कि सिस्टम में पारदर्शिता और नियंत्रण दोनों की कमी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन की स्थिति भी चिंताजनक थी। रेगुलर स्टाफ शॉर्टेज 2017-18 में 23% था जो 21-22 में बढ़कर 32% हो गया। रिपोर्ट में स्टाफिंग डाटा में मिसमैच है, irregular appointments, transfer policy के अमल में विफलता और ट्रेनिंग की कमी भी दर्ज है। जब संस्था के भीतर अनुशासन, नियोजन और क्षमता ही कमजोर हो तब जनता को अच्छी सेवा कैसे मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी समस्याएं अलग-अलग नहीं है, यह एक ही शासन की संयुक्त विफलताएं हैं और उस समय सत्ता में कौन था यह इस सदन से छुपा नहीं है। दिल्ली

की जनता को अब भरोसे के नाम पर धोखा नहीं, अपने हक का साफ पानी और अच्छी व्यवस्था चाहिए। इसीलिए आज मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि दिल्ली की जल व्यवस्था की इस बदहाली के लिए तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इसीलिए इस रिपोर्ट की अच्छे से जांच होकर जो भी इसके निर्णय पर, जिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात दो लाइनों से कह के समाप्त करूंगी कि-

''ना नीति बनी, ना नियत दिखी, बस वादों का जाल था

दिल्ली का हर प्यासा घर उस झूठ का सवाल था।''

धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। अब एक सीएजी, हां जी।

श्री कुलवंत राणाः .... धमकी की ईमेल आई है आज भी।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः कल फिर आई थी और उसको भी पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिया है। लगातार तीन दिन से यहां पर असेंबली को उड़ाने को लेकर के।

श्री कुलवंत राणाः अध्यक्ष जी, दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा को हर रोज धमकी मिल रही है। दिल्ली विधानसभा को हर रोज धमकी मिल रही है। सर चिंता का विषय है यह तो और कभी उड़ा देंगे तो फिर क्या करोगे आप, इसकी कोई योजना बनाई आपने?

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः नहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारी भी आए थे आज।

श्री कुलवंत राणाः नहीं इस पर गहन चिंता होनी चाहिए अध्यक्ष जी, कोई उड़ा देगा तो क्या करोगे फिर आप?

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः यह बहुत विषय तो गंभीर है।

श्री कुलवंत राणाः यह तो हर रोज ऐसा विषय है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में है।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः यह देखिए अब।

श्री कुलवंत राणाः इसको आप संज्ञान में लाओ ... इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप?

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल फिर उसी प्रकार से तीसरा मेल आया है। लगातार 24, 25, 26 शायद तीन दिन से हमारा सेशन चल रहा है, चौथा दिन है आज और ये गंभीर विषय है। पुलिस से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले में कोई कोताही ना बरतें और इसकी तह में जाए। 24 फरवरी को पहली मेल आई थी और इसमें से कुछ मेल बाय नेम मुझे आई हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से एक मैं उसको उसकी गंभीरता उसको मानता हूं कि व्यक्तिगत नाम से मेल आना और अलग-अलग आईडी से आ रही है। अलग-अलग आउटफिट है उनसे आ रही है। तो यह गंभीर मामला है इस पर पुलिस ने आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। असेंबली की सिक्योरिटी जो है वह बढ़ा दी गई है और यहां पर सुरक्षा के लिए भी मैंने दिल्ली विधानसभा के सचिवालय से स्पष्ट रूप से कहा है कि यहां के सभी सीसीटीवी कैमरा जो गेट की एंट्री है वह पूरी उसको भी कंप्यूटराइज कर दिया जाए जिससे की जितने आगुंतुक आ रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास रहे कितनी बार कौन कहां कब आया। तो पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम जो है वह उठाए जा रहे हैं। बाकी अभी देखिए माननीय सदस्यगण ये तो फिर सदन आज पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हम सब इतना इसमें हर विषय पर बोलने के लिए नाम आ रहे हैं तो यह समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। मैं पांच-पांच मिनट अभी मैं वही तो नहीं तो 8:00 बजे तक भी नहीं हो पाएगा।

श्रीमती शिखा रॉय: समय का तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जी, ये तो समय का तो ध्यान रखना पड़ेगा अब। अब इसमें शुरू इसको करते हैं, जो नाम आए हैं मेरे पास।

श्री अभय वर्मा: एक विश्वविद्यालय वाला है।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: विश्वविद्यालय वाले को पहले ले लें।

श्री अभय वर्मा: हां पहले वही है ना।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ठीक है, तो अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर प्रतिवेदन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-4 यह जो रिपोर्ट है सीएजी की ये 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के संदर्भ में है यानि कि 22-23 के लिए। इस पर माननीय मंत्री श्री आशीष सूद जी अपना वक्तव्य देंगे।

सी.ए.जी.रिपोर्ट(दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप) पर चर्चा

श्री आशीष सूद(माननीय शिक्षा मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सीएजी की रिपोर्ट संख्या-4 जो 2018 से 2023 के बीच में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों के संदर्भ में गंभीर विषय दिल्ली की जनता के सामने लाती है। उस पर आपने मुझे कहने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी जैसे विजिटिंग कार्ड और क्रेडिट कार्ड चलते हैं उसी तरह दिल्ली में विक्टिम कार्ड चलते हैं। अपनी जेब में विक्टिम कार्ड ले घूमते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। जब से यह सदन चला है बजट पे चर्चा और बाकी सब विषयों पर, आप सभी ने कल देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के और किसी विषय पर तो पिछले सालों में बोला नहीं पिछले लगभग एक वर्ष में, कल एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि दिल्ली में सरकार केवल उनको गाली देने का काम करती है यही विक्टिम कार्ड खेलने का, जेब में रखकर घूमते हैं और यह विक्टिम कार्ड पहले भी चला गया, चलाया गया कि अगर मेरे को वोट नहीं दोगे मुझको लोकसभा में वोट दे दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जनता ने नकार दिया। जेल भी जाना पड़ा, चुनाव भी हार गए वो सब घटनाक्रम सबके सामने है। अब करें क्या? अगर सरकार में आने के बाद यह देखने को मिलता है कि 2019 में अर्पित होटल में आग लगने के बाद ब्रोंटो मशीनें खरीदनी थीं और छः साल तक नहीं खरीदी गईं तो उसकी तो निंदा की ही जाएगी। अगर यह देखने को मिलेगा कि दिल्ली के सरकारी दिल्ली के कॉलेजेस को लगातार समय पर फीस मिलनी, तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, वहां के बच्चों की बिल्डिंग के लिए पैसा मिलना चाहिए था, ग्रांट इन एड मिलना चाहिए था और अगर वर्षों नहीं मिला तो उसकी तो चर्चा की जाएगी अगर यह अरविंद केजरीवाल जी को गालियां लगती हैं अगर आज सीएजी की टिप्पणियों के बारे में अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे विपक्ष के लोग यहां पर भाग सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। हम तो जब देश में एक समय में दो लोकसभा सांसद थे तब भी जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका निभाते थे। उन दो लोकसभा सांसदों के दौर से जब चले थे तो 89 के आसपास आते-आते बोफोर्स घोटाले को spearhead करने वालों में भारतीय जनता पार्टी थी और उसी प्रकार से तीन विधायक हों या आठ विधायक हों दिल्ली की जनता के सरोकारों को हम बोलते रहे थे चाहे वहां बैठें चाहे यहां बैठें सरकार में जो भी अगर गलत काम हुए होंगे तो उसके के संदर्भ में बोलना हमारी जिम्मेदारी है। अभी सीएजी की रिपोर्ट नंबर-4 2018 से 23 के बीच में यूनिवर्सिटीज की

फंक्शनिंग के बारे में बताती है। अब अगर आज यह बताना पड़े कि पिछली सरकार ने सीएजी ने बताया कि पिछली सरकार ने केवल और केवल, केवल और केवल बिना ग्राउंड वर्क के अनाउंसमेंट्स की जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में अपने आर्टिकल छपवा के गाल बजाकर अपने, अपने तारीफ करने का शौक था केवल वही किया। आपको हैरानी होगी सीएजी रिपोर्ट बताती है दिल्ली टेक्निकल, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बना दिया यूनिवर्सिटी बना दी, वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया मगर एक स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है और आज उसकी दुर्दशा यह है कि तीन यूनिवर्सिटी में तीन विद्यार्थियों का दाखिला है तीन और पिछले साल में केवल 20 विद्यार्थी थे। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। केवल और केवल हमने यूनिवर्सिटी बना दी इसकी वाह-वाह लेने के लिए बात यही नहीं रुकी है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लुड्लो कैसल के एक स्कूल में चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लुड्लो कैसल के स्कूल के साथ बहुत सारे लोगों के भावनात्मक ताल्लुकात हैं।

माननीय अध्यक्ष: ये जो टीचर्स यूनिवर्सिटी है ना मंत्री जी ये एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर छः कमरों में चल रही है। स्कूल उसमें स्कूल भी चल रहा है और छः कमरों में पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं गया था उस समय।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: अध्यक्ष जी एक यूनिवर्सिटी मेरी विधानसभा में भी चल रही है।

माननीय अध्यक्ष: बता रहे हैं वो बताइए, आप बता रहे मंत्री जी वो सब।

श्री आशीष सूद(माननीय शिक्षा मंत्री): उसी तरीके से उसी तरीके से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लुड्लो कैसल के स्कूल में चल रही है। करीब 200-250 बच्चे उसमें हैं मगर वो 12वीं के बाद कहां जाएंगे? यूनिवर्सिटी का करिकुलम क्या होगा? यूनिवर्सिटी कहां शिफ्ट होगी? उसका, उसका उसके कोर्सेज क्या होंगे? वो डिग्री कैसी मिलेगी? उसके प्रोफेसर्स कौन होंगे? ऐसी कोई भी प्लानिंग किसी किस्म की किए बिना दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बना दी। अभी यह तो सीएजी की रिपोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। उसका सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी एक नया बड़ा स्कूल ताकि वह बच्चे वहां रह सकें और अच्छे से जो अभी की पढ़ाई कर रहे हैं उसके नए करिकुलम के लिए एक कमेटी अभी बनाई गई है। नया करिकुलम डिजाइन करने के लिए दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी बना दी। सीएजी की रिपोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं और दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी जो बनाई उस स्किल यूनिवर्सिटी में सारे पॉलिटेक्निक्स को समाहित कर दिया। आज सारे पॉलिटेक्निक्स जो हैं जितने पॉलिटेक्निक्स हैं वो पॉलिटेक्निक्स के विद्यार्थी भी हड़ताल की सी स्थिति में है। टीचर

भी हड़ताल की स्थिति में हैं। विद्यार्थी ये कहते हैं पॉलिटेक्निक में डिग्री मिलती एआईसीटी अप्रूव्ड उसकी वैल्यू ज्यादा है दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू कम है। पॉलिटेक्निक में जो कर्मचारी थे वो सरकारी कर्मचारी थे। यहां डीम डेपुटेशन पर आ गए। ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो रही है। बच्चों का भविष्य खतरे में है वो रोज हड़ताल करके घूमते हैं। बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच के, केवल हम एक-एक भ्रम जो मार्केटिंग की टेक्निक से फैलाया जा रहा था कि हमने एजुकेशन के सेक्टर में बड़ा काम कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट ऐसी अनेक गंभीर टिप्पणियां करती है माननीय अध्यक्ष जी। आपको हैरानी होगी एडमिशन सिस्टम फेलियर के बारे में सीएजी की रिपोर्ट ने बताया है। 16 सालों से 16 सालों से सीएजी ने ऑब्जर्व किया है for last sixteen years, after sixteen years in April 2023, the admission policy is formulated और उसमें भी, उसमें भी इतने वर्षों तक बिना किसी पॉलिसी के और अब भी इतनी सारी एनॉमलीज़ उस पॉलिसी एडमिशन प्रोसेस में है। सीएजी की रिपोर्ट उसकी ओर टिप्पणी करती है। बच्चे लगातार प्रतिवेदन देते हैं, अभिभावक प्रतिवेदन देते हैं। ना उस एडमिशन पॉलिसी को आनन-फानन में लाया गया, ना उसमें माइग्रेशन की कुछ पॉलिसी है, ना उसमें कोई बच्चा अगर कॉलेज चेंज करना चाहता है उसकी कोई पॉलिसी है। इस प्रकार की एनॉमलीज पूरे दिल्ली की यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हायर एजुकेशन में भरी पड़ी है, भरी पड़ी है और हैरानी की बात यह है यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज वो जगह है जहां पर बच्चे सीख कर निकलेंगे and it will be the play ground for the future makers of this country उनके लिए यह ग्राउंड है जहां से वो सीख कर निकलेंगे भारत के निर्माण करने में लगेंगे। उनके ना तो उन यूनिवर्सिटीज के ना तो खातों की जांच ना उनके ऑडिटेड रिपोर्ट्स 5 साल तक सदन में पेश ही नहीं की गई। अपनी और क्यों आपको जानकर हैरानी होगी दिल्ली की जनता को आपके मार्फ़त से पता चले उनके टैक्स के पैसे में मनमाने तरीके से नियुक्तियां करवाना उन नियुक्तियों के माध्यम से पैसे खर्चवाना, उन पैसों में कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन रजिस्ट्रार होगा, कौन असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, कौन पीवीसी होगा? ऐसी कोई भी अपनी नियुक्तियां भी मनमाने तरीके से करते थे इसीलिए और उनके माध्यम से funds siphon out होते थे इसीलिए पांच-पांच साल तक ऑडिटेड रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी नहीं गई और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह संवैधानिक संस्था भारत का सबसे बड़ा ऑडिटर सीएजी कह रहा है। इतना ही नहीं कहा है, इतना ही नहीं कहा है फाइनेन्शियल मिसमेनेजमेंट की बात कही है। स्कॉलरशिप का फंड ढंग से यूज नहीं किया इसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और जो टैक्स, जो टैक्स बचाया जा सकता था यूनिवर्सिटीज के उसमें से उस टैक्स में पैसा देना पड़ा। अवॉयडेबल टैक्स था उसमें पैसा देना पड़ा। ईडब्ल्यूएस के

छात्रों को दिए जाने वाला करोड़ों रुपया डायवर्ट करके दूसरे खातों में इस्तेमाल हो गया। केंद्र सरकार से जो केंद्र सरकार से जो बिल्डिंग और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए जो, जो बजट मिलता था वो एमओयू ना करने के कारण मिला नहीं। ऐसी अनेक 55% की फैकल्टी शॉर्टेज डीटीयू में, डिप्सारू में 54% की फैकल्टी शॉर्टेज ऐसी अनेक एनॉमलीस सीएजी की रिपोर्ट ने दी है। उसके विपरीत श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आने के बाद सुधार करते हुए 22-23, 24-25 में 3014 ईडब्ल्यूएस छात्रों को 44 करोड़ उनके हक की स्कॉलरशिप देकर उनकी पढ़ाई के रास्ते को आसान करने का काम किया है। कैंपस टू मार्केट विज़न के लिए स्टार्टअप युवा फेस्टिवल और ताकि स्टूडेंट अपने आईडिये को मार्केट तक ले जा पाए। आप सबको जानकर खुशी होगी ऐसे 100 स्टार्टअप्स को सरकार ने 10 स्टार्टअप्स को 10-10 लाख रूपये बाकी 90 स्टार्टअप्स को एक-एक लाख ऐसे लाजवाब आइडियाज ऐसे लाजवाब स्टार्टअप्स हमारे युवाओं ने दिल्ली की जनता के लिए देश के लिए बनाए हैं, 200 करोड़ रूपये के ड्रोन का आर्डर डीआरडीओ ने हमारे बच्चों को जो उन्होंने स्टार्टअप खड़े किए ₹200 करोड़ से ज्यादा के ड्रोन के आर्डर दिए। हमारी एक बेटी ने ऐसा सेनेटरी पैड बनाया जो वेस्टेज और उसको खत्म कर दें, जो फ्लशेबल है। ऐसे लाजवाब आइडियाज के साथ ऐसे लाजवाब लगेज के आइडियाज के साथ बच्चों ने काम किया है। उनको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। स्टार्टअप इको सिस्टम के लिए इनक्यूबेशन पॉलिसी 325 करोड़ रूपये की बजट में घोषित की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी ने मैं यह बहुत समय का अभाव है, बहुत लंबा सीएजी ने पूरी यूनिवर्सिटी की वर्किंग पे पॉलिसी वैक्यूम को लेके फाइनेंशियल मिसमनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस एकेडमिक फेलियर्स यूनिवर्सिटी में छः-छः वर्षों तक एनडबलएसी और एनबीए का एग्रिडेशन नहीं लिया गया। 16 वर्षों से सिलेबस अपडेट नहीं किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस फेलियर गलत एफिलिएशन दिए गए। ऐसे बेसिक फैसिलिटीज का अभाव, लिमिटेड ऑडिट और बिगर प्रॉब्लम क्रिएट की गई, तीन यूनिवर्सिटीज के सैंपल के आधार पर ऐसी अनेक बड़ी एनॉमलीस को यूनिवर्सिटी की के संबंध में सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस रिपोर्ट पे गंभीर और डिटेल चर्चा करने के हेतु इसको आप पीएसी के पास भी भेजें ताकि दिल्ली की जनता के पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ है। जो लोग अपने लिए भारत रत्न और जो लोग एक झूठा इको सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि हमने शिक्षा में बहुत क्रांतिकारी काम किया है। इन सबको दिल्ली की जनता के सामने सिलसिलेवार तरीके से पीएसी डेलीब्रेट करके दिल्ली की जनता के सामने लाने का काम करें। ऐसा अनुरोध करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

.....व्यवधान.....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: बस, नहीं वो पेज रिपोर्ट तो ऑलरेडी पेश है ना, वो तो मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो हां जी, वो तो काम मेरा है।

श्री आशीष सूद, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री: इसलिए अध्यक्ष जी वहां अव्यवस्था थी यहां व्यवस्था है, वहां ठहराव था, यहां विकास है, वहां प्रचार था, यहां परिणाम है। इसलिए पीएसी में भेजने की संतुष्टि आप करें सभी रिपोर्ट्स को ऐसी मेरी आपसे विनती है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हमारे नियमों के अनुसार सरकारी उपक्रम समिति कोगू डीजेबी पर बनी रिपोर्ट की जांच करेगी। बाकी सभी रिपोर्टों की जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा की जाएगी। मैं विधानसभा सचिवालय को निर्देश देता हूं कि वे इन रिपोर्टों को संबंधित विभागों को भेजने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने एक्शन टेकन नोट जमा कराने होंगे ताकि समितियां अपनी जांच शुरू कर सकें। इसके अलावा वित्त विभाग को भी निर्देश दिया जाता है कि वह एक्शन टेकन नोट जमा होने की प्रक्रिया पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि यह ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम मॉड्यूल में ठीक से दर्ज हो, जो हमने एक एपीएमएस सॉफ्टवेयर विकसित किया है, उसमें यह ठीक प्रकार से दर्ज हो जिससे कि तेजी से सारा काम हो सके। अब हम यहां पर श्री मोहन सिंह बिष्ट जो है वो सदन के सामने कार्य मंत्रणा समिति के प्रति प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त करते हुए यह सदन निर्णय लेगा, इसका प्रस्ताव पेश करेंगे।

<u>समिति के प्रतिवेदनों पर सहमति</u>

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 23 मार्च, 2026 को जो सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

अब विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। माननीय सदस्य गण अब विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर सहमति का प्रस्ताव सदन के समक्ष आएगा। इन्हें 23 मार्च 2026 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। यदि कोई माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो अपने विचार रख सकते हैं। माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रकाश। यह फांसीघर से संबंधित रिपोर्ट है जो प्रिविलेज कमेटी द्वारा सदन में लाई गई थी और इसका जो आधार है वो यह है कि समिति की और सदन की अवमानना का यह मामला है। समिति में अनुपस्थित रहकर के अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्री और बाकी सब लोग, उस पर अब बात करेंगे।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: माननीय अध्यक्ष जी, 7 अगस्त, 2025 को आपने दिल्ली विधानसभा में फांसीघर होने के और 9 अगस्त, 2022 को उसके उद्घाटन के मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा था। अध्यक्ष जी, समिति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल और उपाध्यक्षा श्रीमती रेखा बिरला को समिति के सामने पेश होने और फांसी घर के होने के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए बुलाया था। लेकिन उनमें से कोई भी इंस्पाइट ऑफ अगेन एंड अगेन चांसेस देने पर 13 नवंबर, 2025 और 20 नवंबर, 2025 को हुई समिति की बैठकों में पेश नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, इसके बावजूद समिति ने उनके जवाबों और दलीलों की जांच के बारे में सदन को पहले भी रिपोर्ट दी, जिसे सदन ने 9 जनवरी, 2026 को अपनाया था। अध्यक्ष जी, इस नतीजे के साथ ऊपर बताई गई घटनाओं से यह साफ है कि श्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, रामनिवास गोयल जी, श्रीमती रेखा बिरला ने जानबूझकर विशेष।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: राखी बिरला ने।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: श्रीमती राखी बिरला जी ने जानबूझकर विशेष अधिकार समिति की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला लिया। जबकि उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त मौके और समय दिया गया और वे जानते थे कि उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में उनके ऊपर हमारे फैसले को लेकर उनको कोई राहत नहीं दी और उनके वकीलों ने इस कार्यवाही के लिए अध्यक्ष जी इवन हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करी, उसमें भी यह राहत नहीं मांगी कि हमें पेश होने से रोका जाए। लेकिन वह बार-बार हमारे को एक बात कहते रहे कि हम सदन में पेश नहीं होंगे समिति के सामने क्योंकि समिति को यह अधिकार ही नहीं है कि वह इसके ऊपर जांच कर सके। अध्यक्ष जी समिति यह सुझाव देती है सदन श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री

रामनिवास गोयल जी, श्री मनीष सिसोदिया जी, श्रीमती राखी बिरला जी के खिलाफ उचित कार्रवाई, राखी बिरला जी राखी बिरला जी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके, क्योंकि वे 13 नवंबर, 2025, 20 नवंबर,2025 को होने वाली विशेष अधिकार समिति की बैठकों में बिना किसी उचित कारण या सभी समिति की इजाजत के जानबूझ के गैर हाजिर रहे। अध्यक्ष जी जहां तक उस महत्वपूर्ण मामले का सवाल है जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति को सौंपा था यानी फांसी घर के अस्तित्व की प्रमाणिकता से जुड़ा मामला समिति संबंधी पक्षों और गवाहों की जांच पडताल जारी रखेंगी और अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सदन ने समिति की सिफारिशों से सहमति जताई। 9 जनवरी 2026 को अपनी बैठक में रिपोर्ट को स्वीकार किया। सदन ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव भी पारित किया। अध्यक्ष जी यह सदन अरविंद केजरीवाल जी को, रामनिवास गोयल जी को, मनीष सिसोदिया जी को और श्रीमती राखी बिरला जी को निर्देश देता था कि वे जब भी तलब किए जाएं विशेष अधिकार समिति के सामने विधानसभा में अपीयर हो तथा समिति की उन बैठकों में अपनी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण भी दें जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को निर्धारित की गई थीं। विधानसभा परिसर में फांसी घर के अस्तित्व की प्रमाणिकता की सिद्ध करने हेतु उनके पास उपयुक्त कोई जानकारी या दस्तावेज भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। अध्यक्ष जी सचिवालय ने 27 जनवरी 2026 को रिपोर्ट की एक प्रति श्री अरविंद केजरीवाल जी को, श्री रामनिवास गोयल जी को, श्री मनीष सिसोदिया जी को, श्रीमती राखी बिरला जी को प्रेषित भी कर दिया उसके बावजूद भी उनको 7.2.2026 को नोटिस सम्मन के माध्यम से उनसे 16.2.2026 को समिति के समक्ष उपस्थित होने तथा आवश्यक समझे तो समिति को अपना कोई लिखित बयान पहले से प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। इसका मतलब यह है कि विशेषाधिकार समिति ने उनको बार-बार मौका दिया। उनको यहां तक कहा गया कि अगर आप कुछ लिख के भी देना चाहते हैं आने से पहले तो आपको वो भी मौका दिया जाता है। तो जो समिति के अधिकार क्षेत्र के अंदर और जबकि वो इस सदन के पहले सदस्य रहे हैं। कई साल उन्होंने सत्ता चलाई है और उनको एक-एक चीज का समितियों के बारे में उनको ज्ञान था। उनको संविधान का ज्ञान था। बैठक के दिन प्राप्त हुए हूबहू और उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई जवाब देते थे तो वो बिल्कुल साइक्लोपीडिया तरीके से चारों के जो लेटर आते थे वो एक ही लाइन में सिर्फ उनके दस्तखत होते थे। ऊपर का मजूम जो होता था वो सिर्फ ये बता देते थे कि जी मामला जो है हाई कोर्ट में हमने डाला हुआ है और वो ये बार-बार कहते रहे कि हमारे को, समिति को यह अधिकार ही नहीं है कि फांसीघर की प्रमाणिकता के ऊपर हमसे सवाल कर सकें। दिल्ली की विधानसभा और उनकी समितियों, अच्छा साथ में ये भी लिखते थे वो कि हम दिल्ली की

विधानसभा और उनकी समितियों का सम्मान करते हैं लेकिन सभी संस्थाओं और निकाय भारत के संविधान के तहत काम करते हैं और संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं। पर अगली बारी उसमें ये लिखते थे ये अपने अगले क्वेश्चन में कि दिल्ली विधानसभा उस समिति के पास फांसीघर की प्रमाणिकता के मुद्दे पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऊपर तो ये लिख रहे हैं अध्यक्ष जी कि हम दिल्ली विधानसभा की समितियों का सम्मान करते हैं और ये सभी संस्थाएं भारत के संविधान के तहत काम करती हैं और नीचे लिखते हैं कि इनको अधिकार नहीं है। इससे इनकी मानसिकता पता लगती है और फांसी घर की प्रमाणिकता के मुद्दे पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इसका फैसला विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक पक्ष से किया जा सकता है। अगर वो कोई बात भी पूछते थे जब उनसे बाद में पहले तो वो आए नहीं, तो मेरा इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी एक ही लास्ट में बात कहना चाहूंगा समिति की पहली रिपोर्ट 9.1.2026 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से सदन के सदन के निर्णय और जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 27.01.2026 के जरिए इन चारों माननीयों को दी गई थी। इसके बावजूद भी सदन के निर्देश अनुसार पत्र 7.2026 के माध्यम से समिति की उन बैठकों में अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए लिखित में उनसे टिप्पणी मांगी गई थी जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई थी। अध्यक्ष जी इसके अंदर जो निष्कर्ष है वो सिफारिश ये है कि इनको बार-बार बुलाने के बावजूद भी 13 नवंबर 2025 और 20.11.2025 को उन्होंने सदन की अवमानना की है। सदन के द्वारा दिए गए अधिकार के तहत जब समिति ने इनको बुलाया तो ये समिति के कहने के बावजूद बार-बार नहीं आए और ऊपर से ये कहते रहे कि समिति को ये अधिकार ही नहीं है कि वो फांसी घर के बारे में हमसे कुछ पूछ सके। तो इसलिए समिति ये सिफारिश करती है कि सदन दिनांक 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को निर्धारित विशेषाधिकार समिति की बैठक में बिना किसी उचित कारण या समिति की अनुमति के जानबूझकर अनुपस्थिति रहने के लिए इन चारों के खिलाफ माननीय श्री अरविंद केजरीवाल, श्री रामनिवास गोयल जी, श्री मनीष सिसोदिया जी तथा श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विरुद्ध उपयुक्त

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: राखी बिरलान ।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: राखी बिरला जी के खिलाफ अब क्या करें हमारे को तो जीवन में हमारी रेखा हमारी सीएम साहब ने इतना कुछ दे दिया दिल्ली को कि

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ये करैक्ट कर लिया जाए राखी बिडलान।

श्री सूर्य प्रकाश खत्री: हमारे को एक ही चीज याद आती है तो श्रीमती राखी बिरला जी के विरुद्ध उपयुक्त कारवाई करें जैसा कि उचित समझें और मैं बार-बार रेखा जी का नाम इसलिए है क्योंकि रेखा जी दिल्ली की एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और अब हमारे को दिल्ली का विस्तार, दिल्ली का विकास और दिल्ली की गति रेखा जी में नजर आती है क्योंकि हमारी भावनाएं बड़ी पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव लोगों के नाम भी हमारे दिमाग से निकल गए हैं। धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए, माननीय सदस्य श्री अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रिविलेज कमेटी के सदस्य होने के नाते ये जो रिपोर्ट आज सदन के सामने आई है, उसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे माननीय सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री जी ने सभी तथ्यों को बताया है। लेकिन मैं हाउस को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब फांसी घर की सत्यता के लिए कमेटी के पास मुद्दा आया और जब उनको फांसीघर के तथ्यों की जानकारी लेने के लिए सदन के सामने बुलाया गया था तो वो आए नहीं। फिर कमेटी ने हाउस के सामने अपने प्रोसीडिंग को रखा और उस प्रोसीडिंग के आधार पे हाउस ने उनकी अनुपस्थिति को लेकर एक अलग से केस बना के ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए फिर से भेजा और उसके बाद कमेटी ने उनको बुलाया। हालांकि वो आना नहीं चाहते थे। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाए। जब कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला तब प्रिविलेज कमेटी के जो चेयरमैन है प्रद्युमन राजपूत उनके सम्मन पे वो आए। अध्यक्ष जी, मैं हाउस को सिर्फ इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि उस प्रिविलेज कमेटी के बैठक में मैं भी था। काफी मशक्कत के बाद जब उनको कानूनी कोई लाभ नहीं मिला, किसी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला तो आए तो एकदम धींगा मस्ती के तरह आए। हाउस को आज ये इस बात को ध्यान में रखना होगा कि क्या इस हाउस की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है या नहीं। क्योंकि वह हाउस के तीन बार मेंबर थे। वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक व्यक्ति राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक राखी बिरलान जी इस सदन की उपसभापति जी रही हैं, लेकिन उन्होंने हाउस के जो मैंडेट थे उसको पहले तो उन्होंने डिसओबे किया और डिसओबे करने के बाद जब उनको कहीं भी किसी भी जगह से कोई रिलीफ नहीं मिला तो वह आके प्रिविलेज कमेटी को ही चैलेंज कर रहे थे। उनके अस्तित्व की बात कर रहे थे। उनसे बार-बार हमारे अध्यक्ष ने माननीय प्रद्युमन राजपूत जी ने पूछा कि आप दो डेटों पे नहीं आए। उसका कोई अच्छा कारण दे दीजिए। कोई भी आप रीजन दे दीजिए ताकि हम कमेटी को संतुष्ट कर सकें और हाउस को बता सकें। लेकिन उन्होंने सीधे यही कहा छूटते कि हम नहीं आए क्योंकि हमें लग रहा था कि कोर्ट से रिलीफ मिले। मतलब वो किसी भी प्रकार से इस हाउस के मैंडेट को महत्व नहीं देना चाहते थे। तो

अध्यक्ष जी यह पूरा हाउस जो है वो इस हरे रंग के किताब के रूल से चलता है और रूल में बहुत स्पष्टता से लिखा है कि हाउस का जो भी मैंडेट आता है वो हाउस ही डिसाइड करेगा। बहुत लिमिटेड मैटर में कोर्ट इंटरफेयर किया है। बहुत इक्का दुक्का देखने को मिलेगा। तो मैं आज हाउस को बताना चाहता हूं कि जो यह प्रिविलेज कमेटी डेलीब्रेट की इनके अनुपस्थिति वाले इशू पर आज यह डिस्कशन चल रहा है। अध्यक्ष जी, उस अनुपस्थिति को देखते हुए जब हमारे पास कोई अच्छा तथ्य या कोई प्रमाण नहीं आया तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इस हाउस के माध्यम से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यही हाउस इसी प्रिविलेज कमेटी को लेकर कई लोगों को जेल भेज चुकी है। ये इतिहास के पन्नों में है और एक सिंसियर व्यक्ति जो इस हाउस का लीडर रहा हो, इस हाउस का उप लीडर रहा हो और वो व्यक्ति अगर इस तरह से डिसओबे करेगा तो दिल्ली के लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए उनकी यह जो उदंडता है मैं तो स्पष्टता से कहूंगा उनका जो यह डिसओबे है इस डिसओबे के ऊपर हाउस को आज संज्ञान लेना चाहिए और मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इस रूल बुक के हिसाब से 77 में दंड को परिभाषित किया गया है और इसमें पांच छह प्रकार का दंड है अध्यक्ष जी, एक तो चेतावनी है, दूसरा फटकार है, तीसरा सदस्य का निलंबन है, जो कि वह सदस्य हैं नहीं, चौथा जुर्माना है और पांचवा सदस्य का निष्कासन है। मुझे लगता है कि आज हाउस को इस बारे में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: पांचवा कारावास भी है।

श्री अभय कुमार वर्मा, मुख्य सचेतक: हां कारावास भी है। जब तक उसमें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जो अभय जी बता रहे हैं मैं दो लाइन में ये स्पष्ट कर दूं। प्रिविलेज कमेटी का अधिकार क्षेत्र और हाउस का, यह घटना है। मैं आपकी बात कोई खड़े रहो आप, खड़े रहो, बस खड़े-खड़े बता रहा हूं। एक घटना बता रहा हूं 1977 की छठी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, सदस्य थी, मेडक से जीत कर आई थीं, उनके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलज का मामला कमेटी को सौंपा गया, कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि इनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए और दूसरा इनको जेल भेज दिया जाए। दोनों सजाओं का क्रियान्वयन हुआ, इतना पावरफुल होता है हाउस और प्रिविलेज कमेटी। अब आगे बोलिए आप।

श्री अभय कुमार वर्मा, मुख्य सचेतक: हां, तो अध्यक्ष जी, यह सारा विषय अब हाउस के।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: और वो जेल गईं। सदस्यता रद्द हुई और जेल गई।

श्री अभय कुमार वर्मा, मुख्य सचेतक: यह सारा विषय अब हाउस के सामने है। मैं चाहता हूं कि हाउस इस पे डिस्कशन करके कोई ना कोई निर्णय ले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? माननीय सदस्यगण यह सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वास्तविकता यह है कि इस मामले पर यह सदन इतना गंभीर क्यों है, यह हमको समझना पड़ेगा और ये हमको लोगों के समक्ष रखना है। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है। इसमें हमारे शहीदों की आज भी आवाजें गूंजती हैं। मैं इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। गांधी जी अपने जीवन काल में अगर किसी सदन में विजिटर्स गैलरी में कार्यवाही देखने गए तो वो ये पवित्र सदन है। वो लिखते हैं अपनी किताब में उनकी पुस्तक है सत्य के प्रयोग, पृष्ठ नंबर 396 पर, मैं जीवन में एक ही बार विधानसभा की बैठक में गया हूं। रॉलेट बिल की चर्चा सुनने गया था, शास्त्री जी ने अपना जोशीला भाषण किया। यह श्रीनिवास शास्त्री जी हैं जो कर्नाटक से सदस्य चुनकर आए थे। रॉलेट बिल की चर्चा सुनने गया था। शास्त्री जी ने अपना जोशीला भाषण किया। सरकार को चेतावनी दी और फिर आगे उस दिन उन्होंने जो कार्रवाई देखी, उसके बारे में उन्होंने क्या-क्या देखा। यह मार्च 1919 की घटना है जो इस सदन में हुई है। इसके बाद ये जो सदन है इसमें जो यह प्रश्न खड़े किए गए कि ये फांसी घर था। आज इस गौरवशाली सदन को फांसी घर से जोड़ना, जबकि जब यह रॉलेट एक्ट पास हुआ 18 मार्च, 1919 को इसी सदन में जिसकी कार्रवाई देखने के लिए गांधी जी यहां आए थे और कार्रवाई देखने के बाद यहीं से उन्होंने असहयोग आंदोलन की घोषणा भी की। उस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत 30 मार्च, 1919 को, मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं जो इसके इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं। 30 मार्च, 1919 को इस सदन के अंदर जब रॉलेट एक्ट को 18 मार्च को पास किया गया गांधी जी ने आंदोलन का आह्वान किया तो 30 मार्च, 1919 को दिल्ली की चांदनी चौक में उस आंदोलन के समय शांतिपूर्ण इकट्ठे हुए लोगों पर मशीन गन से गोलियां बरसाई गईं, आर्मी बुलाई गई और इसके बारे में भी उस घटना के बारे में भी गांधी जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं पृष्ठ नंबर 574 और 575 पर 'सत्य के प्रयोग' में दिल्ली में उस दिन 30 मार्च, 1919 जैसी हड़ताल हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई, जान पड़ा हिंदू और मुसलमान एक दिल हो गए, स्वामी श्रद्धानंद जी को जामा मस्जिद में आने का निमंत्रण दिया और वहां उन्हें भाषण करने दिया गया। यह सब अधिकारियों के बर्दाश्त के बाहर था। रेलवे स्टेशन की ओर जाते जलूस को पुलिस ने रोका, गोलियां चलाईं, कितने ही लोग जख्मी हुए, अनेक जान से मारे गए। दिल्ली में दमन का दौर दौरा हुआ। जो आखिरी लाइन है गांधी जी की पुस्तक में जो उन्होंने अपनी

आत्मकथा में लिखी वह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों जिससे यह सदन जाना जाना चाहिए इसको जाना जाना चाहिए था, बजाय इसके उन शहीदों को हम यहां याद करते और उनकी बात करते गांधी जी कहते हैं जो 30 मार्च, 1919 को, जो कुछ दिल्ली में हुआ वही लाहौर और अमृतसर 13 अप्रैल, 1919 में भी हुआ। यानि कि गांधी जी कहते हैं कि 30 मार्च, 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जो दिल्ली में जानें गईं वही घटना का रिपीटेशन हुआ अमृतसर में जलियांवाला बाग में। यानि कि ये सदन जलियांवाला बाग जैसी घटना से, दिल्ली में हुई घटना से जुड़ा हुआ है और 30 मार्च 1970 को जहां पर यह घटना हुई थी चांदनी चौक में, वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी का स्टेचू जो है पूरा कद का टाउन हॉल के बाहर लगाया गया उसी याद में। उस दिन का अखबार है मेरे पास, जब यह घटना हुई 30 मार्च को, अखबार लिखता है tragedy at Delhi. several killed and injured. machine gun in action, amazing conduct of police and military यानी कि मिलिट्री थी, पुलिस थी, मशीन गन इन एक्शन थी, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या उन शहीदों को कभी याद करने की, इस सदन में कोई यहां पर कोई स्मारक बनाने की क्या चेष्टा की गई? एक और वाक्या आपको बताता हूं इस सदन का। इस सदन में 1918 में वायसराय ने एक वॉर का्फ्रेंस बुलाई तीन दिन की युद्ध सम्मेलन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको कहते हैं और उसमें पूरे देश के राजा महाराजा यहां आए, गांधी जी आए, इस सदन में गांधी जी तीन बार आए हैं। एक बार कार्यवाही सुनने, एक बार युद्ध सम्मेलन जब यहां पर आयोजित किया गया, उसमें आए और एक 1931 में जब ये पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स की यहां पर एक प्रोग्राम था वो अटेंड करने आए। तो उस सम्मेलन में फैसला हुआ कि भारतीय लोग फौज में भर्ती किए जाएंगे और विश्व युद्ध में लड़ेंगे। उस दिन जो फैसला यहां हुआ, आप जानते हैं 13 लाख लोग गए और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र का मैं योगदान बताना चाहता हूं। जो इस सदन में फैसला हुआ उस का्फ्रेंस में, आज भी दिल्ली के गांवों में युद्ध में गए हुए लोगों के पत्थर लगे हुए हैं। यह पत्थर मेरे पास है। मैंने गांव से ही फोटो खिंचवाई है। बवाना में लगा हुआ है, बवाना उस समय जैल सिस्टम होता था, जैलदार होते थे। तो जैल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चार गांव का, पांच गांव का, छह गांव का, दो गांव का तो यह लिखते हैं पत्थर एक पत्थर लगा हुआ है बवाना, कंझावला एंड अलीपुर from the jail of Bawana, Kanjhawla and Alipur. 1231 men went to the great war 1914 से 1919 के बीच में वह चली थी of these 81 gave up their lives यानि 1231 गए और 81 लोग बवाना के, कंझावला के, अलीपुर के युवा शहीद हो गए। ऐसा ही एक पत्थर लगा हुआ है बादली गांव में the jail of Delhi Badli, Nangloi और Shahdara ये एक जैल थी बादली, नांगलोई और शाहदरा, 835 लोग गए जिसमें से 50

लोग शहीद हो गए। ऐसा ही एक पत्थर लगा हुआ है नजफगढ़ में। उस समय नजफगढ़ का नाम था नजब ग्राम। वह पत्थर आज भी लगा हुआ है। नजफगढ़ में जो पत्थर लगा है उसमें लिखा हुआ है नजफगढ़, ईसापुर और पालम, 1605 ग्रामीण युद्ध में गए और 159 शहीद हो गए। इसी तरह से मेहरौली, बदरपुर में 1261 गए, 92 शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि फांसीघर की झूठी कहानी, मनगढ़ंत और यह दिल्ली के ग्रामीण लोगों ने शहादत दी, इनके बारे में कोई जिस जमीन पर यह स्ट्रक्चर बना 1912 में, आप जानते हैं यहां पर गांव था चंद्रावल। चंद्रावल गांव ने 1857 में गुर्जरों का गांव था, गुर्जर समाज का, 1857 में मैटकाफ हाउस जो अंग्रेजों का एक ऑफिशियल रेजिडेंस था, उस पर चढ़ाई की और पूरा तहस नहस कर दिया अंग्रेजी शासन, हुकूमत को। पूरे देश में अगर आवाज गई तो दिल्ली की वो आवाज गई गुर्जरों के गांव चंद्रावल की जिसको उन्होंने उजाड़ा। क्या उन शहीदों को कभी आपने श्रद्धांजलि देने की बात की, कभी नहीं की। अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता हूं इसकी जो हमारे इसकी जो एक डिग्निटी है उसके बारे में, उसको दिखाया जाए जरा। इस इतिहास से हम सब वाकिफ होने चाहिए कि यह केस क्यों चल रहा है फांसी घर पे? इस हाउस को इसकी डिग्निटी को, गांधी जी अपने जीवन काल में एक बार गए किसी सदन में उसके लिए याद किया जाएगा, इस हाउस को यहां पर चंद्रावल गांव को उजाड़ा गया। आप देखिए पहले फिर, इसको शुरू करिए।

श्री कुलवंत राणा: अध्यक्ष जी, फांसीघर तो हटवा दो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: वो तो हट चुका है।

....व्यवधान....

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं वो बताएंगे आपको। आगे शुरू करिए। दिखाइए, ऑन करिए। आप ऑन करिए।

(विधान सभा पर आधारित डाक्यूमन्ट्री फिल्म चलाई गई)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण ये जो परिसर है इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। हम चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक महत्व को हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। यह वो तथ्य है जो अभी सरफेस पर नहीं है। यह सरफेस पर आएंगे देश दुनिया इसको जानेगी और इसके बलिदान को समझेगी। लेकिन इसमें अगर एक झूठ का पुलिंदा जोड़ दिया गया जिसका कोई आधार नहीं है और यह फांसी घर वाली असेंबली बनकर रह गई तो क्या हम अपने इतिहास के साथ न्याय कर पाएंगे? इसलिए आवश्यक है इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना

और ऐसे लोगों को इस पूरे मामले पर दुनिया के सामने सच लाना। अब इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए यह जो प्रतिवेदन है विशेषाधिकार समिति के द्वितिय प्रतिवेदन पर सहमति, श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन, प्रस्ताव करिए आप।

श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन 23 मार्च 2026 को सदन में विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वह हां कहेंगे।

जो इसके विरोध में है वह ना कहेंगे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पासे हुआ।

अब ये जो प्रतिवेदन है इसको सदन ने अपनी इजाजत दी है। इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए। यानि कि यह सदन में जो प्रतिवेदन आया है इस पर सहमत है सदन इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब सदन ने विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर सहमति दे दी है। इस प्रतिवेदन में समिति ने अपनी सिफारिशों में श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री रामनिवास गोयल और श्रीमती राखी बिरलान को समिति की अवहेलना करने और दिनांक 13.11.25 और 20.11.25 को आयोजित बैठकों में उनकी जानबूझकर और स्वेच्छा से अनुपस्थिति के लिए सदन और समिति की अवमानना का दोषी माना है। अब यह विषय सदन के समक्ष है। मेरा अनुरोध है कि सदन इस पर निर्णय ले कि उनको इसपर क्या जो धारा-77 के अंतर्गत क्या दंड निश्चित किया जाए। इस संदर्भ में श्री जितेंद्र महाजन जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर वही दंड सदन उसके ऊपर अपनी सहमति देगा।

श्री जितेंद्र महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी। यह सदन दिनांक 23 मार्च, 2026 को सदन में प्रस्तुत की गई विशेषाधिकार अधिकार समिति की दूसरी रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह सदन समिति की सिफारिशों से सहमत है। यह सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री रामनिवास गोयल और श्रीमती राखी बिरला को इस सदन की अवमानना का दोषी मानता है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत विशेषाधिकार

समिति के सम्मन की अवहेलना की और 13 नवंबर, 2025 तथा 20 नवंबर, 2025 को आयोजित समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हुए और अतः यह सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री रामनिवास गोयल और श्रीमती राखी बिडला के कृत्यों की निंदा करता है और उन्हें यह चेतावनी देते वह सचेत करता है कि भविष्य में वे अधिक सावधान रहे तथा विधानसभा और उसकी समितियों के निर्देशों का सम्मान करें, धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने। हां जी आप बोलना चाहते हैं।

श्री राज कुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र महाजन जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करते हुए, अभी आपने बताया है कि इस सदन की पवित्रता और प्रतिष्ठा जो है वह सर्वोपरि है और हम एक संवेदनशील राजनीति करते हैं। अगर हमारी जगह वो लोग बैठे होते तो उसका कुछ कुछ और मतलब निकालते। लेकिन मैं आपके नेतृत्व में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यह जो सदन चल रहा है भाई जितेंद्र जी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूं कि इन चारों व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी देकर उन्हें इस हेतु सूचित किया जाए कि भविष्य में सदन इस प्रकार की कारवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री नीरज बैसोया, माननीय सदस्य: अध्यक्ष जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जी।

श्री नीरज बसोया: अध्यक्ष जी, जैसा कि मैं भी उस समिति का मेंबर हूं, सबने कहा चेतावनी मतलब सबने तो नहीं कहा, सबने तो कहा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सुझाव है। मेरा एक सुझाव सिर्फ इतना है कि कम से कम 1 रूपए का तो उनके ऊपर दंड लगाना चाहिए। सिंबॉलिक भी हो जाएगा और कड़ा से कड़ा भी हो जाएगा।

...व्यवधान.....

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक मिनट एक मिनट आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। ये जो प्रस्ताव आया है, इसमें मुझे लगता है कि जो बात अभी राजकुमार भाटिया जी ने कही है और जो प्रस्तुत प्रस्ताव यहां है क्योंकि अभी जो फांसीघर का मामला है इसके दो हिस्से हैं। पहला तो अनुपस्थिति जानबूझकर और फिर उसके बाद भी झूठ बोलना और समिति की भी अवेलना करना और दूसरा पक्ष है इसका कि फांसीघर का जो झूठ फैलाया गया उसके संबंध

में समिति अपना तीसरा प्रतिवेदन देगी। मुझे लगता है कि जो चेतावनी का पक्ष है वो भी एक सजा का हिस्सा है, दंड का ही हिस्सा है और यहां पर सदन चूंकि इस पूरे मामले पर बहुत ही न्यायसंगत तरीके से बातचीत कर रहा है। डिग्निटी का विषय है। इसके इतिहास के जो मूल में जो बलिदान है जो शहादत है जो जिसको लेकर के ये सदन पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है जो व्यवस्था के अंतर्गत उस दौरान जो कुछ दिल्ली में घटित हुआ इस सदन में लिए गए निर्णयों के विरोध में, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षी है जो उन्होंने अवहेलना की है, सदन की अवमानना जो सिद्ध हो गई है उस पर बड़ी से बड़ी सजा दी जा सकती है, उनको जेल भी भेजा जा सकता है और मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की किसी अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिल सकता क्योंकि प्रिविलेज के मामले में दिल्ली की विधानसभा या अन्य कोई भी विधानसभा या फिर देश की संसद सर्वोपरि है और सबके लिए ये अधिकार समान है, चाहे देश की संसद है, चाहे अन्य विधानसभाएं है, चाहे दिल्ली की विधानसभा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि हम न्याय संगत तरीके से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रस्ताव आया है वो अपने आप में एक सजा के रूप में देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने ये सजा चेतावनी जो कि 'क' खंड है धारा-77 का दंड का जो पहला जो पार्ट है उसका 'क' है ये यानी कि 77 (1) का ए चेतावनी। चेतावनी पर हम इसको वो रखते हैं और बाकी अगर इसमें मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो। ठीक है और किसी को अगर कुछ कहना है इसपे, तो अभी यह प्रस्ताव जो है मैं इसको वोटिंग के लिए ला रहा हूं। श्री जितेंद्र महाजन, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे,

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब हमारे सामने लेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर हम यहां पर बातचीत करेंगे और उसके लिए मेरे पास नाम आए हैं। संक्षिप्त में ही अपनी बात रखेंगे और इसमें हम पहले शुरू करते हैं पोल्यूशन पे। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से सीएजी की रिपोर्ट पोल्यूशन पर जो सदन के समक्ष रखी गई थी जिस पर आज सदन को फैसला लेना है कारवाई का और इसको संक्षिप्त में अपनी बात कहनी है हमें 5:00 बजे तक सदन की कार्यवाही को पूरा करना

है। उसके बीच में ही सारी कार्यवाही को पूरा करना है। तो पोल्यूशन पर श्री करनैल सिंह जी माननीय सदस्य।

श्री करनैल सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पोल्यूशन पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बजट के अंदर एक पोल्यूशन पर बहुत बड़ा बजट रखके दिल्ली के लोगों को जीवन की रेखा बचाने का जो काम किया मैं उनके लिए उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ 11 साल से आप सरकार ने जिस तरह प्रदूषण के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उसकी उनको सजा भी मिलनी चाहिए और लोगों को पता भी चलना चाहिए। जैसा कि सदन को पता है कि पराली के नाम पर एक छोटा सा अमाउंट को उस योजना में लगाकर के और करोड़ों रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में प्रदूषण पर खर्च किया, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। दूसरी बात 11 साल तक कूड़े के जो पहाड़ थे लोगों को भ्रमित करते रहे कि हम ये कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे। भ्रष्टाचार करते रहें, उस पर भी कोई काम उन्होंने नहीं किया। मैं रेखा सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वयं कूड़े के पहाड़ पर जाकर के चाहे वहां कितनी भी बदबू हो, कितना भी कुछ हो, बिना रुमाल के, बिना मास्क के जाकर के लोगों के, अधिकारियों के साथ जाकर के जो काम किया उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। ना ही उन्होंने किसी कचरे पर काम किया, ना ही किसी प्लास्टिक पर काम किया और नकली उपकरण जो दिल्ली को भ्रमित करने के लिए कि हमने इतने बड़े उपकरण प्रदूषण के लिए लगा दिए, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसे को खराब किया लेकिन बाद में जब पता चला कि वह उपकरण किसी काम के नहीं है, उनको कूड़े के भाव में बेच दिया, यह बहुत बड़ा उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे पता है आज सदन का टाइम कम है। मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): माननीय सदस्य- श्री सतीश उपाध्याय जी।

श्री सतीश उपाध्याय: आदरणीय सभापति जी, लोक लेखा समिति का मैं सदस्य हूं और पिछली सरकार ने पिछले 11 साल के अंदर एक भी रिपोर्ट सीएजी की सदन में सम्मिलित नहीं की और उससे पहले 16 साल तक कोई भी रिपोर्ट सीएजी की समिति में नहीं आई। पिछली सरकार ने जनलोकपाल के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी। हमारे विपक्ष के साथियों के साथ यह पिछली सरकार के मुखिया भी संविधान के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने की है। लेकिन संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने ही किया था। सरकारी

खर्च का चौकीदार जो है वह सीएजी होती है और परफॉर्मेंस ऑडिट का काम भी सीएजी करती है। एक तरफ हमारी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर और पारदर्शिता को पूरी तरह क्लेरिटी के साथ रखा है। और दूसरी तरफ इस सरकार की रिपोर्ट को अगर हम देखें जब हम इस समिति में थे और उस समय भी जो समिति के सदस्य थे विपक्ष के वो नहीं चाहते थे कि समिति की फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट बने और आज जो उनकी अनुपस्थिति यहां पर है वो चूंकि तीनों रिपोर्ट हमारे पास इस एक साल के अंदर आई हैं उनकी अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार उस, इस प्रदूषण के मामले पर हुआ। किस तरीके से सरकारी खर्च का दुरुपयोग हुआ। सरकार की लापरवाही सामने आई और सरकार ने कुल मिलाकर के इस प्रदूषण के मुद्दे पर जिससे दिल्ली पूरी तरह परेशान थी उस पर कुछ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, समिति के पास जो समिति ने सिफारिशें की हैं उसमें स्पष्ट है कि प्रणालीगत खामियां इस प्रदूषण के समय उस समय सरकार ने की थी। वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या सीमित और संचालन में खामियां थी। प्रदूषण की अधूरी और असंगत निगरानी थी। वैकुलर इंडस्ट्रियल डस्ट पर विश्वसनीय डाटा की कमी थी। नीति निर्माण में वैज्ञानिक और वास्तविक डाटा का भी अभाव था।

सार्वजनिक परिवहन पर बसों की संख्या जनसंख्या की मांग के अनुरूप नहीं थी। कई क्षेत्रों में बस कवरेज बहुत कम थी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भारी कमी थी। बस रूट की प्लानिंग उनके क्रियान्वयन में समन्वय की कमी थी। वैकल्पिक परिवहन जैसे ई बस फीडर सेवाएं को लागू करने में अनावश्यक देरी हुई। दिल्ली में प्रतिदिन लाखों लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। लेकिन अपर्याप्त व्यवस्था के कारण मजबूर होकर निजी वाहनों का उपयोग कर रहे थे। वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण की जो विफलता थी उसमें पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल केंद्रों का अपर्याप्त करवरेज था, पीयूसी प्रमाण पत्र करने में पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी थी, आधुनिक तकनीकों और रिमोट सेंसिंग, एआई मॉनिटरिंग के उपयोग की धीमी गति थी।

विशेष चिंता का विषय है कि बड़ी संख्या में एंड ऑफ लाइव व्हीकल्स, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन जो अभी भी सड़कों पर चल रहे थे उनके बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी। इनके स्ट्रैपिंग की व्यवस्था भी पूरी तरीके से नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रयास बहुत अपर्याप्त थे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा नहीं दिया गया। चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ावा दिया गया। ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया और यहीं से यह सारी जो पूरी पॉल्यूशन की जो समस्या है वह दिल्ली के लिए बढ़ती गई। अध्यक्ष महोदय, समिति ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिए हैं और वह सुझाव आपके सामने हैं। वह सुझाव मैं आपसे

कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस समय पर्याप्त तरीके से चाहे वह ईवी पॉलिसी हो, चाहे वो बसेस को बढ़ाना हो, चाहे वो मेट्रो को बढ़ाना हो, चाहे प्रदूषण के सुधार के लिए नई नीति बनानी हो, उसके लिए काम कर रही है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों को समय के अनुसार उनको लागू किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): अब लोकलेखा समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर सहमति, श्री अजय महावर प्रस्ताव करेंगे।

श्री अजय महावर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 23 मार्च, 2026 को सदन में प्रस्तुत लोकलेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब यहां पर जो दूसरा प्रतिवेदन है वो उस पर बात होगी और उसकी शुरुआत करेंगे दूसरे प्रतिवेदन पर श्री गजेंद्र यादव जी,

श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक: एक्साइज..

श्री विजेन्द्र गुप्ता (माननीय अध्यक्ष): अच्छा, एक्साइज शुरू करना है, ठीक है। माननीय सदस्य- श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट (माननीय उपाध्यक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, वास्तव में शराब नीति में जिस प्रकार का घोटाला हुआ, नियम और कायदे कानून को ताक में रख के दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार से बर्बाद करने का एक केजरीवाल साहब ने एक ऐसी नीति अपनाई थी। यही नहीं ये शराब नीति की 2021 और 22 का मुख्य उद्देश्य केजरीवाल साहब की सरकार के अंतर्गत पूरी तरह से शराब नीति को निजीकरण से तक सीमित रखना था। इस नीति के तहत शराब की दुकानों का निजीकरण किया गया। यही नहीं जो शराब की दुकानें थी जो सरकारी

माध्यम से उनको चलाया जाता था और उनको कैंसिल करके 849 दुकानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। यही नहीं दिल्ली की इस शराब नीति में इसको 32 जोनों में इसको तय किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमने राजनीति के अंदर पहली बार ऐसी सरकार को देखा जिसने वार्ड के नाम से चार-चार दुकानें शराब के एक वार्ड में खोली जाएंगी। इस प्रकार से जोन के माध्यम से बांटकर एक ही व्यक्ति को इनका लाइसेंस दे दिया और जिसकी जिम्मेदारी उस इलाके में 27 दुकानें चलाने की थी। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि इसमें यह नीति के तहत यह भी तय था कि शराब की दुकानें ना तो अनथराइज्ड कॉलोनीज में खोली जाएंगी। यह डीडीए के मॉल्स के अंदर खोली जाएंगी। नियमों को ताक में रख के यह अनथराइज्ड कॉलोनीज हो या जहां पे मास्टर प्लान की रोड नहीं हो वहां भी खोल दी गई। अध्यक्ष महोदय, इस कानून की हद तो तब हो गई कि दिल्ली के अंदर शराब की दुकान को रात्रि के 3:00 बजे तक खोलने की जो परमिशन दी गई, क्षेत्रों के अंदर एक गुंडागर्दी का या जिस प्रकार का आलम किया गया। वास्तव में इस शराब नीति को खुले स्तर पर परोसने पर जिस प्रकार की छूट केजरीवाल साहब की सरकार ने दी वास्तव में इससे बड़ी घृणा कोई नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, यह भी था कि इसमें एक काम और किया गया शराब जो पीने की उम्र थी वो 25 वर्ष की थी लेकिन शराब को इतना बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इसकी उम्र में भी बदलाव कर दिया और 21 साल इसके लिए तय कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह भी यह भी सत्य था कि हम जब उसको देख रहे थे, इस नीति के बारे में सुन रहे थे, नई नीतियों के बारे में एमआरपी पे शराब की बिक्री थी और यही नहीं एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का जिस प्रकार से केजरीवाल ने काम किया निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही घिनौना इस प्रकार का कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, टैक्स में जिसको एक मुश्त टैक्स देना था, एक मुश्त उसके लाइसेंस के अंदर फीस देनी थी तो उस फीस में भी बहुत बड़ी भारी छूट दी गई। अध्यक्ष महोदय, हमने इतिहास में यह भी देखा है कि ड्राइड डे, ड्राई डे जो कोई त्यौहार हो, कोई ऐसे दिन हो उनमें ड्राई डे की छुट्टी की जाती थी। केजरीवाल साहब की सरकार एक ऐसी सरकार आई जिसने दिल्ली के अंदर जो 21 दिन ड्राइ डे होते थे उनको तीन दिन तक सीमित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो और 2 अक्टूबर हो वो उनको भी उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं उनके बाद भी इस प्रकार की प्रक्रिया रही। मेरा सीधा-सीधा कहना है अध्यक्ष महोदय, यह वही व्यक्ति था वास्तव में दिल्ली के ऊपर कलंक था। मैं दिल्ली की जनता का आभारी हूं जिसने 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और रेखा गुप्ता जी की सरकार हम सब लोगों के लिए एक विकास की नई कड़ी के रूप में दिल्ली में आई। अध्यक्ष महोदय, यह इतनी निकम्मी सरकार पिछले दिनों के अंदर रही। इसमें टैक्स के अंदर लाइसेंस

धारकों को अनुचित लाभ के तहत 144.36 करोड़ की लाइसेंस माफ करने वाली भी यही केजरीवाल की सरकार रही बदले में रिश्वत जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई जब कोर्ट ने इनको पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट के बाद जब निचली अदालत से इस प्रकार का फैसला देने आया तो निश्चित रूप से यह हमारी जैसी सरकार जो लोकहित के लिए कार्य कर रही है उनको किस प्रकार से कैसी टिप्पणियां कर रहा था। निश्चित रूप से मैं अभिनंदन करता हूं हाईकोर्ट का जिन्होंने इस पर स्टे लगाकर के पुनः इन चार आरोपियों, इनके 23 आरोपियों को दोबारा से आरोप सिद्ध कर दिया और यही नहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में जिस प्रकार का इनकी जांच की वास्तव में यह अपने आप में और सीबीआई द्वारा जिस प्रकार अपना पक्ष इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जांच में, स्वतंत्र जांच में जो अपना पक्ष नहीं किया, पक्ष नहीं रखा और ईडी के दावे के आधार पर जिस प्रकार का यह अपने आय को उस पैसे को गोवा के प्रचार में लगाया यह अपने आप में बहुत ही ऐसा घिनौना कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपनी सरकार का तो आभार प्रकट करता हूं, मेरी सरकार के माध्यम से इन वर्षों एक वर्ष के अंदर कहीं भी इस प्रकार के शराब के ठेके नहीं खोले गए, लोगों को रियायत दी गई।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्षः और इस कार्य के लिए निश्चित रूप से कोर्ट के आभार के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्षः माननीय श्री मंजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्री।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्रीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट ना केवल दिल्ली के एक घोटाले को उजागर करती है बल्कि दिल्ली के हर महकमे में लगभग हर महकमे में घोटाले किए गए ये कैग की रिपोर्ट बताती है। चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, चाहे चिकित्सा की बात कर लें, चाहे बसों की बात कर लें, चाहे बिजली की बात कर लें, चाहे हर मसले के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के घोटाले सामने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सबसे एक बड़े घोटालों में से घोटाला है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को लंबे समय तक जेल भी जाना पड़ा। इस कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा गया। जैसे की आप भी जानते हैं कि इस कैग रिपोर्ट को दबाकर रखने के बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ा और आप कोर्ट से आर्डर लाने की बात हुई तब तक यह सरकार आई और आपने इस कैग रिपोर्ट को टेबल किया। अब यह कैग रिपोर्ट जो कुछ बता रही थी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस रिपोर्ट को

पीएसी के लिए भेजा और आज पीएसी की भी वही सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। एक से बढ़कर एक घोटाला क्या रास्ते थे घोटाले करने के यह पीएसी में निकल कर आया है। अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी जब उनकी जमानत हुई तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने शोर मचाया देखिए-देखिए मैं जेल से बाहर आ गया, देखिए मैं बेकसूर हूं। कोई भी मुजरिम जो होता है उसकी जमानत होती है, जमानतों के बाद ही लोगों को उम्र कैद भी हुई, लोगों को फांसियां भी हुई, लोगों को रेप के केस के अंदर फांसियां भी हुई। ये सब केसों में होता है लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने बेईमान और ऐसा मुखौटा लगाकर चलते हैं। अभी डिस्चार्ज का उनका केस आया। क्या है केस, 3000 पन्ने की चार्जशीट को हाईकोर्ट ने यह माना। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि बिना इतनी बड़ी चार्जशीट के डिस्चार्ज हो नहीं सकता और उस डिस्चार्ज पे स्टे दिया गया। ये माननीय हाईकोर्ट ने दिया तब तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं नहीं दिखाई देते, तब तो भाग जाते हैं लेकिन जो पीएसी की रिपोर्ट से बातें सामने आई मैं आज आपके सामने वो रखना चाहता हूं। केजरीवाल जी की दो-तीन बातें हैं, एक ये मुझे क्लीन चिट मिल गई। आपको मैं आज यह बात कहना चाहता हूं जो मैं पीएससी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं और जो कैग की रिपोर्ट हमने देखी है कोई ताकत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बच पाएं इतने पुख्ता सबूत उनके खिलाफ हैं। आप देखिए, यह कैग की रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि 17 नवंबर, 2021 से लेकर 31 अगस्त, 2022 तक दिल्ली को दो 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, 2000 करोड़ का, एक्साइज पॉलिसी यह जानबूझकर बनाई पॉलिसी थी। यह पॉलिसी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने खुद अपने घर बैठकर यह पॉलिसी बनाई और जो दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने पॉलिसी दी थी उसको उन्होंने लागू करने से इंकार किया और यह भी सामने आया कि किस तरह से एक्साइज पॉलिसी पहले से ही तैयार करके और उनको एक कंप्यूटर में डाल के दी गई डिपार्टमेंट को कि इस एक्साइज पॉलिसी को मान लिया जाए। अब देखिए, कैसे-कैसे घोटाले किए। पुराने सिस्टम में 77 आईएमएफएल के होलसेलर थे, जो Indian made foreign liquor है उसके 77 होलसेलर थे लेकिन नए सिस्टम में जब इन्होंने 12 फीसदी बेईमानी से उसके ऊपर प्रॉफिट देने की तय किया तो केजरीवाल जी के इस दौरान पॉलिसी में केवल 13 लोग बचे जो लोग अब होलसेल का काम करते हैं। मोनोपोली बना ली होलसेल की क्योंकि पैसे लेने थे 12-13 लोगों से आसानी से लिए जा सकते हैं और इनमें से मात्र तीन कंपनियां, इन 13 में से भी तीन कंपनियां ऐसी थी जो 71.7% पूरी की पूरी आईएफएल मार्केट को कंट्रोल कर रही थी। यह कार्टल बनाया गया जैसे ड्रग्स के कार्टल बनते हैं। आपने देखा होगा टीवीयों पर चलती खबर वो कार्टल को उठा के ले गए। इन्होंने कार्टल बनाकर तीन लोगों को 71% शराब का धंधा देने का काम किया। फिर

इससे पहले सरकार की हर शराब की बोतल वाइज उस पर एक्ससाइज ली जाती थी इन्होंने आकर खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी कि एक के साथ एक बेचो और जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। इन्होंने लाइसेंस फीस लागू कर दी और इस लाइसेंस फीस के चलते, आप सुनिए शराब की बोतलें तो 58.19 करोड़ पिछले साल बिकी थी। इनकी नई पॉलिसी में 64.82 करोड़ बिकी जो की लगभग 8 करोड़ शराब की बोतलें फालतू बिकी 8 करोड़। इसके बावजूद प्रोपोशनेटली इनका रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि ये 2000 करोड़ अब शराब का पैसा प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा था। इसी तरह 32 जोन बनाए गए, 32 जोन में से मात्र 22 एंटटीज को सारा काम दे दिया गया और इसमें से भी हैरान आप होंगे इन 22 एंटटी जो सक्सेसफुल बिडर्स दिखाए गए उनमें से केवल 10 ऐसे बिडर्स थे जिनको 1 लाख से ज्यादा साल की आमदनी थी। देखिए, साल की 1 लाख से ज्यादा आमदनी है और शराब का पूरा जोन वह एक से दो जोन लेने जा रहे हैं जो 200-200 400-400 एक जोन है तो 1000-1000 करोड़ का काम लेने जा रहे हैं तो उनकी खुद की कंपनी का प्रॉफिट कितना है 1 लाख से कम है और आप सुनिए आगे 9 तो ऐसे थे जिन्होंने कभी प्रॉफिट दिखाया ही नहीं, जिनकी कंपनी को कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ था उनको भी काम दिया गया और तो और उनमें से कुछ ऐसे थे जो पिछले सालों में लॉस में गए इसके बावजूद उनको काम दे दिया गया। अब आप देखिए एक इसी तरह का एक मिसाल है pathways, path two ways HR solution ये दो कंपनियां ऐसी हैं एक ने 52 करोड़ का लॉस दिखाया दूसरे ने 37 करोड़ का लॉस दिखाया इनकी नेटवर्थ नेगेटिव है इसके बावजूद इनको लाइसेंस इनके रिन्यू किए गए, क्यों किए गए? क्योंकि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी ने अंडरटेबल पैसे ले लिए तो इनको लाइसेंस मिल गया। देश में किसी को नहीं मिल सकता। एक एक बार रेवेन्यू लॉस में आप आ गए आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता लेकिन इनको दे दिए गए। आगे देखिए कोविड के दौरान जब बाकी किसी डिपार्टमेंट के पैसे नहीं किए गए तब इन लोगों ने 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी। और यह भी तब किया जब एक्साइज ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बकायदा लिखकर मना किया कि आप यह पैसा नहीं रिफंड कर सकते और एक्साइज मंत्री साहब ने नोटिंग को ओवराइड करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने कहा ये माफ कर दो। आज मैं पूछना चाहता हूं यह किसके बाप का पैसा है, यह किसके बाप का पैसा है जो माफ किया जा रहा है, यह दिल्ली के लोगों का पैसा है। केजरीवाल जी आपके बाप का पैसा नहीं है ना ही मनीष सिसोदिया जी के बाप का पैसा है कि आप दो 200 करोड़, चार 400 करोड़ शराब के माफियों को माफ कर देंगे आज आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इसी तरह 67 नॉन कंफर्मिंग वार्डों के अंदर उनको दुकान खोलने का आश्वासन दे दिया और यह मिलीभगत की गई, पता था वहां दुकानें

नहीं खुलेंगी। जब नहीं दुकानें खुली तो 941 करोड़ रूपया एक फिक्स्ड मैच के तहत हाई कोर्ट से उनको माफ करा दिया। अध्यक्ष जी 941 करोड़ रूपया इससे दिल्ली के कितने गरीब लोगों के मकान बन जाते, कितने गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लेते, कितने गरीब लोगों की चिकित्सा मिल जाती। 941 करोड़ रूपया फिक्स मैच के तहत उनको वापस करवा दिया और आप देखिए इस पॉलिसी के तहत ना तो इन्होंने जब ईएमडी रिफंड करी, ना तो इन्होंने एलजी से मांगा परमिशन ली, ना ही इन्होंने एलजी को फाइल मूव की जबकि एयरपोर्ट की ईएमडी जो इन्होंने रिफंड की थी उसकी फाइल एलजी साहब तक जानी चाहिए थी। मनीष सिसोदिया जी ने अपने लेवल में फाइनल करके उसको ईएमडी रिफंड कर दी। अब देखिए 12% उनको फिक्स प्रॉफिट दिया। इस देश में पहला काम हुआ था इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया इससे पहले देश में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें 12% फिक्स्ड प्रॉफिट किसी को दिया जाए और इसका नाम क्या लिया गया, हम इसलिए फिक्स फिक्स प्रॉफिट दे रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन को बढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया है कि यहां पे वेयर हाउसिंग के ऊपर सीधी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी शराब की इसलिए इनका मार्जिन बढ़ा दिया गया लेकिन सुन हैरानगी इस बात की है उन वेयर हाउसेस के अंदर जब जाकर जानकारी ली 19 वेयर हाउस में तो लैब चल ही नहीं रही थी 19 वेयर हाउस में तो फिर मार्जिन क्यों बढ़ाया गया? अच्छा मैं एक बात आज आपको और याद करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी हजारों करोड़ का घोटाला करके भोला सा चेहरा बना के अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात कह देते हैं देखिए जी, मैं तो ईमानदार हूं। अब यही काम शराब का जो यहां दिल्ली में किया आप याद करना आज इस विधानसभा के पटल पर मैं यह बात कह रहा हूं यही काम पंजाब में शराब लूटी गई है। जब अगली सरकार बनेगी वहां पर अरविंद केजरीवाल अगले साल बाहर होंगे। जो, जो सुपर सीएम बनकर पंजाब में घूम रहे सरकारी तंत्र लेकर आप याद रखना ये सारी शराब का घोटाला पंजाब का भी इसी तरह बाहर आएगा। अंत में मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी बचने के जितने मर्जी रास्ते निकाल लें। जो घोटाला गरीब लोगों का पैसा लूटा गया है, जरूरतमंद पैसा लोगों का पैसे को लूटा गया है। इसका हिसाब अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को सजा भी होगी और पूरी दिल्ली भी देखेगी कि जिस आदमी ने छोटे-छोटे बच्चों को नशे पे लगाया था उसको सजा कोर्ट से भी मिलेगी। दिल्ली के लोगों ने तो दे ही दिया है भगवान भी देगा और साथ-साथ में कोर्ट से भी आने वाले दिनों में सजा मिलेगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष: लोकलेखा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर सहमति, श्री अजय महावर माननीय सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि।

श्री अजय कुमार महावर: अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन दिनांक 23 मार्च, 2026 को सदन में प्रस्तुत लोकलेखा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें।

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब लोकलेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर सहमति के लिए प्रस्ताव आए इससे पहले श्री माननीय सदस्य श्री गजेंद्र यादव जी।

श्री गजेन्द्र सिंह यादव: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी पीएसी की रिपोर्ट और उसमें जो जानकारी माननीय सदस्यों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। केजरीवाल सरकार ने अपने दो मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर बहुत ढिंढोरा पीटा लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी विशेष तौर पर मैं स्वास्थ्य मॉडल पर बताना चाहता हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो लगभग 21% स्टाफ की कमी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती रहीं। लोकनायक हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर को औसतन 87 मरीज देखने पड़ते थे। जिससे हर मरीज को 5 मिनट से भी कम समय मिलता था यह बहुत खराब व्यवस्था थी। माननीय अध्यक्ष जी, सर्जरी के लिए भी मरीजों को तीन-तीन, चार-चार महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी छः से आठ महीने तक का इंतजार करना पड़ता था। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बने होने के बावजूद स्टाफ की कमी के कारण यह बंद पड़े रहे। एक तरफ मरीज लाइन में और दूसरी तरफ सुविधाएं खाली पड़ी रहीं ये सरकार की नाकामी का स्पष्ट उदाहरण है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपातकालीन सेवाओं की स्थिति भी बेहद खराब रही। कैट्स की एंबुलेंस में जरूरी उपकरण और दवाइयां तक भी उपलब्ध नहीं हो पाईं। कोविड

के दौरान भी पूरी की पूरी सरकार वो छिप कर रही और सरकार के जो मुखिया थे वह अपने शीश महल में अपने सुविधाओं का ख्याल रखते रहे। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल जो बहुत जोर शोर से शुरू किया था जिसका ढिंढोरा बहुत पीटा गया था। उस मोहल्ला क्लीनिक मॉडल में भी यह बातें निकल कर आ रही हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को किराए के नाम पर वो सरकारी पैसा उनको देते रहे। डॉक्टरों की उपलब्धता की कमी दवाइयां तक नहीं होना और मोहल्ला क्लीनिक केवल और केवल औपचारिकता बनकर रह गए। माननीय अध्यक्ष जी कोविड जैसी महामारी में जो कोविड एक-एक परिवार के एक-एक व्यक्ति तक बहुत डर का माहौल था। जिसमें मुझे लगता है कि मोहल्लों में जो चिकित्सा सेंटर के नाम पर इन्होंने उघाई के केंद्र बनाए थे। किस तरह से उसमें नकली दवाइयां परोसी जाए, किस तरह से अपने पहचान वालों को तनख्वाएं दी जाए, वे मोहल्ला क्लीनिक भी ताले बंद करके कोविड के दौरान बंद पड़े रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी आज जो यह केजरीवाल सरकार का स्वास्थ्य का जो एक मॉडल था उसमें बहुत सारी कमियां और भ्रष्टाचार निकल कर हमारे सामने आया है। पीएसी की रिपोर्ट में भी यह बातें निकल कर आई हैं, कैग रिपोर्ट में बातें आई हैं। मैं इस सदन के सामने कुछ सवाल छोड़ता हूं कि इतने वर्षों तक केजरीवाल सरकार चली, क्या कारण है कि इतने वर्षों तक स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल रही? सब जानते हैं कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली के पीछे केजरीवाल सरकार का जो भ्रष्टाचार था वह रहा। आज दिल्ली में नई सरकार आई है और मैं विशेष तौर पर क्योंकि दो दिन पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है तो उसमें मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के श्री मुख से जो बातें आई है वो दिल्ली के लोगों तक पहुंची हैं और उसमें मैं यह जरूर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी जो एक लाइन है वो मैं जरूर अंत में कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति को मिलने वाला उपचार वह उपकार नहीं दिल्ली के एक-एक नागरिक का अधिकार है। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं दिल्ली के लोगों के सामने पवित्र विधानसभा से यह बात कहना चाहता हूं कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी सरकार दिल्ली के एक-एक परिवार की स्वास्थ्य के लिए चिंता करती तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला वो निकल कर नहीं आता मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: लोकलेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर सहमति। श्री अजय महावर माननीय सदस्य प्रस्ताव करेंगे।

श्री अजय महावर: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 23 मार्च, 2026 को सदन में लोकलेखा समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे।

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

माननीय सदस्य गण लोकलेखा समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में 15 साल से भी ज्यादा समय के बाद सदन ने पीएसी की रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने सीएजी की रिपोर्टों की प्रतियां सदन में पेश नहीं की थी और पीएसी को लगभग निष्क्रिय बना दिया था। उस दौरान सदन में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी, 11 वर्ष में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की। हालांकि अब सरकार को मिली सीएजी की सभी रिपोर्ट सदन के सामने पेश कर दी गई है और उन्हें पीएसी और कोगू को भेज दिया गया है। पीएसी सदन की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, जिस पर कार्यपालिका और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली विधानसभा ने पीएसी को फिर से पटरी पर ला दिया है। एक साल के भीतर ही पीएसी ने स्वास्थ्य, आबकारी और वाहन प्रदूषण पर सीएजी की रिपोर्टों के आधार पर सफलतापूर्वक तीन रिपोर्ट पेश की है। मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए पीएसी के अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई देता हूं। समिति ने अपने निष्कर्षों पर बहुत ही उचित सुझाव दिए हैं। समिति ने बताया है कि विभागों ने अपने कामकाज में पाई गई अनियमितताओं और कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। संसदीय प्रथा और परंपरा के अनुसार विभागों को पीएसी के सुझावों पर अपनी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट एक्शन टेकन नोट जमा करनी होती है। इसलिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाता है कि रिपोर्टों में बताई गई समय सीमा के भीतर अपनी एक्शन टेकन नोट जमा करें। विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आगे की कार्रवाई के लिए इन रिपोर्टों को तुरंत संबंधित विभागों को भेज दें।

विधेयक पर विचार करना और पारित करना

अब सदन के समक्ष विधेयक पर विचार करना और पारित करना। अब जो सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5), अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीया मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि 25 मार्च, 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) पर विचार किया जाए।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 25 मार्च 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) पर विचार किया जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे।

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

इस पर किसी को अगर कोई विचार रखना है तो अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड तीन जिसमें धारा 12 सी के बाद धारा 12 डी को जोड़ा गया है। विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे।

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक का खंड तीन विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड एक एवं खंड दो प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे।

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड एक और खंड दो प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बन गए। अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 25 मार्च, 20 26 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) को पारित किया जाए।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 25 मार्च, 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए सोसायटी पंजीकरण (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2026 (वर्ष 2026 का विधेयक संख्या-5) को पारित किया जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वे हां कहे।

जो इसके विरोध में है वे ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ।

वार्षिक बजट 2026-27 पर चर्चा। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्रस्तुत वार्षिक बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना भाषण बजट से संबंधित विषयों तक सीमित रखें तथा समय का विशेष ध्यान रखें ताकि सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने

विचार रखने का अवसर मिल सके। अब सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य श्री मनोज शौकीन।

वार्षिक बजट (2026-27) पर चर्चा

श्री मनोज शौकीन: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो एक शानदार बजट पिछली बार 1 लाख करोड़ और अबकी बार 1 लाख करोड़ का जो हमारी बहन रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है और उन्होंने अपने बजट को भी नाम दिया है विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली। अगर आप देखोगे क्योंकि कई बार जब हम चर्चा करते हैं करते रहे हैं विदेशों की भी करी अपने देश की भी करी, तो हमारे देश के अंदर पिछले आजादी के बाद से चुनाव लड़ते रहे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है और इस पर चुनाव हुआ। आज हम यहां पहुंचे हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा बजट जो बजट का लगभग आधा हिस्सा आधे हिस्से में से क्योंकि अगर किसी भी देश के लिए किसी भी देश की राजधानी या किसी राज्य के लिए अगर जरूरी होता है तो वह है शिक्षा और शिक्षा के ऊपर लगभग 20% बजट हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर दिया है जो एक तारीफ के काबिल बेहतरीन बजट जिसे कह सकते हैं। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, बाकी चीजें तो उसी के माध्यम से हो जाती हैं। और शिक्षा के साथ-साथ अगर डेवलपमेंट कहीं देखा जाता है तो वह देखा जाता है कि उस शहर के उस राज्य के रास्ते कैसे हैं, उसके पुल कैसे हैं। लगभग 13% इस हिस्से के लिए उन्होंने दिया है और उसके बाद कुछ बच गया तो कोई बीमारी है जो दिक्कतें रही हैं दिल्ली में। आयुष्मान भारत जैसे कार्ड को लागू नहीं किया गया और अनेकों हॉस्पिटल जो अधूरे पड़े। मेरे यहां पर भी संत दुर्बलनाथ हॉस्पिटल जो पिछले जब मैं 2013 में विधायक बना था तो तब वह शुरू कराया था लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। मुझे बेहद खुशी के साथ कहना पड़ता है कि 13% बजट का जो हिस्सा है वह स्वास्थ्य को दिया है वो जो एक शानदार तरीका है दिल्ली को स्वस्थ बनाने के लिए लगभग 44% बजट 50 हजार करोड़ के आसपास इन सेवाओं को दिया है। लगभग 20% एजुकेशन इसी तरह से मिलाकर के मैं बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करना चाहूंगा अध्यक्ष जी। जब हमने विधानसभा का चुनाव जीता और जीतने के बाद जब अपने स्कूलों में गए हर रोज विज्ञापन देखते थे, टीवी में देखते थे, रेडियो में सुनाई देता था दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था इतनी बढ़िया है वर्ल्ड क्लास है विदेश से लोग आते हैं तो सीधे स्कूलों में जाते हैं और देखते हैं कि ये असली भारत है। कितना बढ़िया भारत है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब मैं गया अपने सुल्तानपुरी रोड के स्कूल में और स्कूल में जब मैंने देखा एक ही स्कूल में सुबह भी कक्षा लगती है और शाम को भी कक्षा

लगती है और स्कूल के बाथरूम देखे तो टूटे पड़े। जर्जर हालत में क्लास रूमों की हालत खराब और बुरी हालत में जो वहां पर बच्चे जो हैं पढ़ने को मजबूर हो रहे। मैंने माननीय मंत्री जी को भी लिखा उनको भेजा भी लेकिन आज जब मैंने देखा कि एक शिक्षा के लिए आपने लगभग 20% बजट दिया है तो मुझे एक आशा की किरण एक रोशनी नजर आई है कि मेरे वो सुल्तानपुरी रोड जैसे स्कूलों की मरम्मत भी होगी और वहां नई अच्छी बिल्डिंग बनेंगी क्योंकि आपने ऐसा प्रावधान उसके अंदर किया है। मैंने जाकर के ये भी देखा अभी पीएसी की रिपोर्ट जो पढ़ रहे थे जो उस रिपोर्ट के अंदर जिस तरह से मेरे साथी बता रहे थे घोटाले उजागर हो रहे थे। मेरे यहां पर एक अमलवास ज्वालापुरी में जे जे कॉलोनी है। वहां पर एक स्कूल है अध्यक्ष जी और उस स्कूल को आप बाहर से जाकर के देखोगे तो इतना शानदार स्कूल लगता है। चमक रहा है। क्योंकि उन्होंने इसी के ऊपर ध्यान दिया। करोड़ों रुपए उसके अंदर खाए होंगे। लेकिन उस स्कूल के अंदर जाओ तो नीचे की बिल्डिंग काम कर रही है और ऊपर की बिल्डिंग सीज कर रखी है। क्योंकि वहां पर डेंजर घोषित हो रखी है वो बिल्डिंग। इस तरह से ये स्कूल चला रहे थे। तो हमने नए स्कूल बनाने के लिए भी बजट रखा है। स्कूलों के अंदर कमरे बनाने के लिए भी बजट रखा है और नौवीं क्लास से ऊपर की जो हमारी बच्चियां हैं जो पीछे ही अभी हमारी बहन हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा जी ने जो 1000 बच्चियों को साइकिलें बांटी हैं तो मुझे भी हम बैठे थे तो बचपन याद आ रहा था। बचपन में जब आठवीं नौवीं क्लास में होते थे और जाने के लिए जब हमें दूर पढ़ना जाना पड़े और साधन नहीं हो नजदीक में स्कूल नहीं हो अगर साइकिल मिल जाए तो कितना आनंद का अनुभव होता है। वो जो बच्चियों की चिंता की है ये एक ऐतिहासिक कार्य है और ना नजदीक में कोई चुनाव है। दूसरी दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये यूपी में जाकर के साइकिल का चुनाव प्रचार करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन ना आज कोई चुनाव है दिल्ली में ना नजदीक में कोई चुनाव है लेकिन उन बच्चियों की चिंता अगर की है मेरी बहन रेखा गुप्ता ने तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और नियत की जो है उसको दर्शाता है। अध्यक्ष जी आप घड़ी की तरफ मत देखना मैं टू द पॉइंट बात करूंगा लंबा नहीं करूंगा जब कहोगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं टाइम तो आपका ओवर हो चुका है।

श्री मनोज कुमार शौकीन: हां हां दो चार मिनट और दे दो बस।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं दो चार मिनट नहीं एक मिनट और मिलेगा बस।

श्री मनोज कुमार शौकीन: अच्छा एक और दे दो एक तो दोगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हां एक मिनट एक मिनट में कर लीजिए।

श्री मनोज कुमार शौकीन: तो 90 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा है। सीएम श्री विद्यालयों में दुनिया भर के हमारे काम हो रहे हैं। चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बताया। अध्यक्ष जी मैं बहुत सारी बीच बीच में जो चीजें हैं वो काट देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं जो हमने शिक्षा का जो बजट रखा है हमने जो शिक्षा का बजट रखा है तो मैं एक बार दोहराना चाहूंगा बीच के 27 साल निकल गए लेकिन 27 साल से पहले जब हमारी 1993 से 98 के बीच में जो सरकार थी उस सरकार के दौरान आज जो जिक्र आया कि भई यूनिवर्सिटी खोल दी, छह कमरों में खोल दी, कहीं किसी स्कूल में खोल दी, किसी कॉलेज के छह कमरों में खोल दी लेकिन हमने ये उस टाइम टाइम पे जो यूनिवर्सिटी खोली थी आईपी यूनिवर्सिटी जो ना केवल देश के अंदर हमारे समय की खोली हुई आईपी यूनिवर्सिटी आज हमारे पूरे देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में जिसमें कोर्स लेते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारी सरकार खोलेगी। घेवरा मोड़ पर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज की जगह है वो बहुत बढ़िया शानदार कॉलेज बना करके हमारी सरकार जो है इस पैसे का सदुपयोग करेगी। इसी तरह से अध्यक्ष जी हमारे नए मैं एक और बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी पीछे जब हम सब बैठे थे हमारी हजारों एकड़ भूमि जो ग्राम सभा की है और वो ग्राम सभा की भूमि के अंदर हमारे मेरे ख्याल से कम से कम गांव के अंदर 400-500 ऐसे मल्टीपल एमपीसीसी जो हैं सेंटर खोले थे मल्टीपर्पस कम्यूनिटी सेंटर। उन सेंटर्स के अंदर आईटीआई के कोर्सेस चलते थे। सिलाई कढ़ाई सेंटर अपना स्कूटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, लाइब्रेरी और अपने बाजार की दुकानें भी होती थीं। लेकिन वो सारे के सारे कम से कम भी आज अगर हम स्कूल खोलना चाहे तो हमारी अगर वो जो वो लैंड हमें मिल जाए एमपीसीसी सेंटर मल्टीपर्पज कम्यूनिटी सेंटर हमें मिल जाएं। डीडीए ने जो ले लिए हैं अभी वो हमें लेने चाहिए हर हाल में और उनके अंदर तुरंत हम जो ये एक-एक जगह पे सुबह शाम दो-दो शिफ्ट में स्कूल चलते हैं। हम नए स्कूल वहां पर खोल सकते हैं। नई बिल्डिंग वहां बना सकते हैं। ये कार्य हमें करने की आवश्यकता है। जो पैसा हमारा उसमें सदुपयोग हो जाएगा। अध्यक्ष जी ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी बहुत सारे काम जो करने के लिए हमने ये एक बहुत बढ़िया काम किया। आप देखोगे कि हमारी जब सरकार बनी 1993 से 98 के बीच में एक केवल डिस्ट्रिक्ट होता था और एक डीसी बैठता था तीस हजारी में उसके बाद में हमारी सरकार ने नौ डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। नौ के बाद में 11 हुए और आज जो निर्णय लिया है दो डिस्ट्रिक्ट और हमारी सरकार ने हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने बढ़ाए हैं और एक बेहतरीन जो कार्य होने जा रहा है वो बेहतरीन कार्य आज सबसे

ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा कोई बना हुआ है तो वह सब रजिस्ट्रार का ऑफिस बना हुआ है और उसको खत्म करके उस सिस्टम को खत्म करके जिस प्रकार से आज हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं और पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो घर से टाइम फिक्स होता है। वहां जाकर के बैठने का टाइम फिक्स होता है। टाइम से वहां फोटो होता है। सारे कागजात पहले तैयार हो जाते हैं और टाइम पे अपने घर पे जो आ जाता है इसी तरह से रजिस्ट्री भी होगी और घर पे अपना रजिस्ट्री हो करके पेपर भी जब आ जाएगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक बहुत बढ़िया साधन।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: एक-एक मिनट रुकेंगे जरा आप। ये समय सदन का

सवा 5 बजे तक, 6 बजे तक कर लें। नहीं पहले कर दें 5:30 तक आप 5:15 के करीब आप बोल लें तो समय का जो समय बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो 6:00 बजे तक का सदन के सामने है ठीक है 6:00 बजे तक सदन की कारवाई चलेगी।

श्री मनोज कुमार शौकीन: अध्यक्ष जी मैं खत्म कर रहा हूं बस। तो यह जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस को जो करने का पासपोर्ट की तर्ज पे जो किया है, इसकी जितनी भी सराहना करें हमारी बहन रेखा जी की और हमारी सरकार की उसकी उतनी ही कम है। भूरे-भूरे शब्दों में मैं इसकी सराहना करता हूं और बहुत से विषय हैं। लेकिन आपने समय जो है ना रखा है। इसलिए अध्यक्ष जी मेरे दूसरे साथी इस बाकी विषयों पर जो रखेंगे रखेंगे। लेकिन बेहतरीन काम और एक और बार-बार मैं सराहना करूंगा। हमारा कोई भी साथी हमने कभी मैं पहले भी दो बार सदस्य रहा हूं इस हाउस का और पहले पार्षद भी रहा हूं लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि हम देखते थे कि भई पैसे के लिए डेवलपमेंट के काम के लिए जब कोई स्कीम बनाते थे तो सोचना पड़ता था कि इतने की बनवाए पता नहीं पास होगा नहीं होगा, लेकिन रेखा जी के नेतृत्व में भाजपा की यह सरकार दिल्ली की यह सरकार और पूरा मंत्रिमंडल बहुत शानदार कार्य कर रहा है और तेजी से विकास हो रहा है बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने बोलने का समय दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी।

श्री अनिल कुमार शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी द्वारा वित्तीय वर्ष बजट 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट की दिल खोलकर प्रशंसा करता हूं। यह बजट जिसे ग्रीन बजट का थीम दिया गया है यह बजट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकाता, मानववाद और अंत्योदय से प्रेरित एवं लोकप्रिय

प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास' की नीति पर आधारित है। यह बजट सर्वस्पर्शीय, सर्व समावेशी, सर्व कल्याणकारी और सर्वग्रही बजट है। स्कोप, स्केल, स्पीड, स्किल को दिल्ली के विकास का मंत्र बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि नवजात शिशुओं के लिए कोई जेनेटिक समस्या ना हो उसकी निगरानी के लिए एक नई पहल 56 प्रकार के लैब टेस्ट रक्त की एक बूंद से निशुल्क परीक्षण किए जाएंगे और यूं इस योजना का नाम आपने अनमोल रखा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ यह एक योजना ही नहीं बल्कि दिल्ली वासियों के लिए यह पूरा बजट ही एक अनमोल बजट है। क्योंकि इसमें आपने नवजात बच्चे, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, थर्ड जेंडर, किसान, गांव, अनधिकृत कॉलोनी, स्लम सभी के लिए आपने इस बजट में झोली खोलकर उपहार के उपहार दिए हैं। सबका इसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग को इससे फायदा हुआ है। दिल्ली की कक्षा नौ की लगभग 1 लाख 30 हजार विद्यार्थी बेटियों के लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन के चिंता करते हुए निशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने का जो काम आपने किया है जिसका जिक्र अभी हमारे साथी आदरणीय मनोज शौकीन साहब भी कर रहे थे। यह बहुत बड़ा काम है। बिटियों को खासकर सरकारी स्कूल में, के बच्चियों को देने का काम जो अपना शहर स्कूल में जाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता था उनको वो खर्चा ही बचेगा और कहीं ना कहीं पोल्यूशन की कमी भी इससे होगी जब वो साइकिल उनको बच्चों को मिलेगी। आपने दुर्गा योजना के तहत पहले चरण में 1000 महिलाओं और 100 थर्ड जेंडरों को रोजगार फॉर वुमेन और ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो के तहत निशुल्क ऑटो परमिट देने का अनमोल उपहार दिया है। पहली बार दिल्ली में ट्रांसजेंडरों की सुध ली। साथ ही उनके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाने की बात कही। आपने नवजात बेटियों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से धनराशि जमा करने का निश्चय किया। बिटिया के ग्रेजुएशन पूरा करने पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रूपये देने का अनमोल उपहार दिया। जैसा कि आपने कहा भी कि दिल्ली की बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। आपने बहनों को 260 करोड़ की योजना से होली और दिवाली पर गैस सिलेंडर का भी अनमोल उपहार दिया। तो साथ ही 450 करोड़ बसों में निशुल्क, बसों में निशुल्क यात्रा के लिए पिंक कार्ड में महिलाओं के लिए साथ ही ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा। महिलाओं के लिए अलग से 10 करोड़ की लागत से रानी हाट बनाने का अनमोल उपहार भी दिया। दिल्ली में पहली बार एक सैनिक स्कूल खोलने का उपहार भी आपने दिया। आयुष्मान कार्ड हो, आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन तो दिल्ली के जरूरतमंद लोगों के लिए अनमोल उपहार बना गया है जिसे आपने और बढ़ाने का काम किया है। विद्यार्थियों की चिंता करते हुए प्रत्येक विद्यालय में एक चिकित्सा कक्ष स्थापित करने का संवेदनशील फैसला किया तो दूसरी ओर

शैक्षणिक नवाचार और एक्सपोज़र विजिट के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं जब हम इस सदन में नए-नए आए थे तो पहली बार जब बोलने का मौका इस सदन में मिला तो माननीय अध्यक्ष जी को याद होगा, सदन को याद होगा, तो हमने ये कहा था कि अगर हम चुनाव जब जीते तो बड़े-बड़े वादों से नहीं जीते थे हमने जब वादा किया चुनाव में तो हमने कहा कि जब चुनाव जीतेंगे तो हम सीवर की समस्या को ठीक करेंगे, पानी की समस्या को ठीक करेंगे, आज मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मंत्री गणों का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मेरी विधानसभा आरकेपुरम के अंदर जो बजट का दिया गया है उससे आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारे चार गांव हैं मुनीरका गांव है, बसंत गांव है, माधवपुर गांव है, गांव मोतीबाग गांव है, सभी के अंदर 90% से ज्यादा सीवर की समस्या हल हो चुकी है। साथ ही जो हमारे गांव के अंदर एक समस्या रहती थी गली की ना बनने की बुरा हाल होता था सड़कें टूटी हुई थी उनके लिए भी काफी बजट आपने दिया है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या गांव के अंदर काफी हद तक थी उसको काफी ठीक किया गया पर मैं ये कह नहीं सकता आज की तारीख में कि 100% ठीक हुआ है क्योंकि 11 साल तक जो सरकार थी उससे पहले जो सरकार थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया पर एक साल के अंदर हमने काफी ट्यूबवेल भी लगाए हैं और पानी की लाइन भी चेंज करी है। उससे पानी की समस्या भी काफी हद तक ठीक हुई है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव की चौपालों की हालत कोई अच्छी नहीं थी। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट दिया गया उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ज्यादातर चौपालों का काम अभी शुरू हो गया है, कुछ का शुरू होने वाला है। चाहे हमारी वाल्मीकि चौपाल हो, चाहे हमारी जाटव समाज की चौपाल हो, चाहे हमारी प्रजापति चौपाल हो, चाहे हमारी पंडित समाज की चौपाल हो, हर समाज की चौपाल का काम वहां पर शुरू हो चुका है। तो मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथ ही मेरे जो क्षेत्र है माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि मेरे इधर स्लम बस्ती जिसको हम झुग्गी बस्ती भी बोलते हैं।

(समय की घंटी)

श्री अनिल कुमार शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी मेरा 10 मिनट में बजाई थी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: 10 सेकंड तो इसमें चले गए। आप बोलते रहो ना मैं अभी आपको, बस आपकी ही, कॉन्क्लूड कर लो।

श्री अनिल कुमार शर्मा: धन्यवाद जी। मैं एक मिनट और लूंगा दो मिनट बस।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हां बस एक मिनट में करिये।

श्री अनिल कुमार शर्मा: मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी मेरे इधर जो झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है दिल्ली के अंदर अगर मैं कहूं कि ऊपर की जो तीन चार विधानसभाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर झुग्गी बस्ती कहीं रहते हैं तो सलम बस्ती मेरे क्षेत्र में है। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चुनाव में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद की वजह से माननीय मोदी जी की वजह से उन्होंने आरकेपुरम से हर बूथ से हमें जिताया और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे मंत्री जी का कि हमारे जितने भी कैंप है 22 के 22 झुग्गी कैंप के अंदर एक साल के अंदर हमने हर जगह पर नाली, गली, खडंजा बना दिया, सीवर की लाइन डाल दी, बोरिंग करा दिया, ये सब हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रूपये का जो बजट हमारे आर के पुरम के लिए दिया है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही अटल कैंटीन भी हमारे यहां दो बनी है। हमने तो रिक्वेस्ट करी है कि हमारे इधर झुग्गी बस्ती गरीब ज्यादा लोग रहते हैं और भी कैंटीन बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि आने वाले समय में हम और भी देंगे, पर मैं दो कैंटीन का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही आरोग्य मंदिर हमारे यहां पांच बनकर तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में अभी और भी बनेंगे। हाई मास्ट लाइट हो, चाहे हमारे इधर जिम और झूले, हमारे इधर आरकेपुरम के अंदर सरकारी कर्मचारी भाइयों का इलाका बहुत बड़ा है। वहां पर उनकी डिमांड रहती थी जिम भरने की, झूले लगने की, वो भी बहुत तादाद में लगे हैं। हाई मास्ट लाइट भी बहुत ज्यादा लगी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रवेश जी का पीडब्ल्यूडी के नाते हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी रोड थे जहां खासकर रोड जो खराब थे उनके ज्यादातर टेंडर हो चुके हैं और आने वाले समय में हमारी वो सारी डैंस कारपेटिंग भी होगी। आपने मुझे समय दिया बोलने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रीगण का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी चाहे वो विधानसभा हो और दिल्ली हो उसको तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं और यह बजट ये बजट ऐसा बजट है कि दिल्ली तरक्की की तरफ जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना जी।

श्री हरीश खुराना: धन्यवाद जी। सबसे पहले तो यह सदन इस ऐतिहासिक बजट इसमें 1 लाख 3 हजार करोड़ का जो प्रावधान किया गया है ये सदन बहुत-बहुत बधाई देता है और बहुत-

बहुत प्रशंसा करता है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। ये जो विकास की यात्रा पिछले साल शुरू हुई इसमें 1 लाख करोड़ का बजट जब रखा गया तो कुछ विपक्षी दलों को हजम नहीं हुआ था। उनका कहना था कि यह बजट कहां से आएगा? कैसे होगा? बहुत सारी बातें की थी। लेकिन बधाई है माननीय रेखा गुप्ता जी को कि जो विकास यात्रा पिछले साल शुरू करी है उसको कंटिन्यू करते हुए एक नया पैमाना हिस्टोरिक दिल्ली के उसमें पहली बार हुआ कि 1 लाख 3 हजार करोड़ का बजट रखा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो अब तक का हाईएस्ट बजट पूरी दिल्ली के अंदर इस बार माननीय रेखा गुप्ता जी ने रखा और ये लोग कहते हैं कि काम क्या हो रहे हैं। कैपिटल बजट दिखाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाता है कि किस प्रकार से 2021 के अंदर अगर 15,000 करोड़ रखा तो 2025 में रेखा गुप्ता जी के आने के बाद 28,115 करोड़ हुआ और इस बार 1 लाख 3 हजार करोड़ के बजट में 29% से ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा। यह दिखाता है कि हमारी सरकार विकास की यात्रा पर निकल चुकी है और दिल्ली के अंदर किस प्रकार से काम हो रहे हैं। दिल खोल के पैसा हर क्षेत्र के अंदर हर उसके अंदर दिया जा रहा है चाहे एजुकेशन के अंदर हो 19 हजार करोड़ रूपया हो, हेल्थ सेक्टर के अंदर 13 हजार करोड़ रूपया हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर 12 हजार करोड़ रूपया हो, हाउसिंग के अंदर 11 हजार करोड़ रूपया हो, सोसाइटी और सोशल वेलफेयर के 10 हजार करोड़ रूपया हो, वाटर एंड सेनिटेशन के अंदर 9 हजार करोड़ रूपया हो, एनर्जी में 3900 करोड़ रूपया हो, एग्रीकल्चर में 1000 करोड़ रूपया हो, यह दिखाता है कि हर सेक्टर का ख्याल मेरी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया। अब विपक्षी मैं देख रहा था कि क्या कोई रिएक्शन आएगा। अध्यक्ष जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी कि क्या है बजट के अंदर, ये दिखाता है कि उनको सांप सूंघ गया है। लेकिन इनका एक बेरोजगार नेता है, उसने बढ़-चढ़कर एक बात करी कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी बड़े-बड़े क्लेम कर रही हैं। उनको शॉक में हैं कि क्या हुआ है। यहां तक कि हर साल जो दावे करते थे कि रेवेन्यू बजट हमारा रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। माननीय रेखा गुप्ता जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ₹1 लाख करोड़ के budget के आने के बाद भी हमारा जो दिल्ली का budget है वह revenue surplus रहा है। ये बधाई के पात्र हैं हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी। 2023 के अंदर अगर ₹6462 करोड़ इनका revenue surplus था तो ₹103000 करोड़ के budget के आने के बाद भी दिल्ली का जो revenue surplus है उल्टा बढ़ा है ₹9661 करोड़ revenue surplus हो गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी के लिए इस बार बधाई की बहुत-बहुत पात्र हैं कि कैसे इन्होंने सब कुछ जो ईमानदारी का budget है वो पेश करते हुए revenue surplus लेके आए एक लाख करोड़ के बाद भी। अध्यक्ष जी, यहां तक कि अगर मैं कंपेयर करूं इंडियाज की जो GDP ratio और दिल्ली का, यह वो लोग भी सामने

बैठे हुए थे जब दिल्ली का जो GDP के बड़े-बड़े दावे करते थे। लेकिन सच्चाई यह है अगर 2023 की बात करूं अगर GDP 11.7 थी ऑल इंडिया की तो दिल्ली की 9.71 थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने GDP को भी पछाड़ कर अगर ऑल इंडिया 6.9 है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर भी GDP 7.92 हुई है। ये हमारी रेखा गुप्ता जी की ईमानदार सरकार है। ये बधाई की पात्र है कि इन्होंने इस बार ऑल इंडिया के अंदर भी हमने क्रॉस करते हुए दिल्ली को पहला स्थान करा है, ये हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार है। अब ये बातें करते हैं मैं देख रहा था press conference की थी इनके अध्यक्ष ने लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी के लिए किया, उनके पिताजी के बारे में किया ये सदन घोर शब्दों में उसकी निंदा करता है और सौरभ भारद्वाज जो यहां की पूर्व मंत्री थे उनके खिलाफ यहां पे मेरे ख्याल से प्रस्ताव आना चाहिए कि उनके खिलाफ उनके खिलाफ आलोचना होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बात करी कि दिल्ली की सरकार loan ले रही है, पहली बार ऐसा ऐसा हुआ है कि दिल्ली ने loan ले लिया है। अध्यक्ष जी, मैं यह आंकड़ा प्रस्तुत करना चाह रहा हूं उनके सामने। अगर देख रहे हैं तो यह देख लें सदन के अंदर ही उनका जवाब था कि 2018 के अंदर उन्होंने ₹2800 करोड़ loan लिया। 2019 के अंदर ₹4500 करोड़ loan लिया। 2020 के अंदर ₹9500 करोड़ का loan लिया। 2021 के अंदर ₹5000 करोड़ का loan लिया, 2022-23 में ₹3251 करोड़ का loan लिया। जब वो गए हैं अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर लगभग 40 हजार करोड़ का public debt दिल्ली को वो देके गए हैं। तो ये जो बातें करते हैं विपक्ष के लोग कि दिल्ली के अंदर पहली बार रेखा गुप्ता जी ने loan लिया है इनको शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और अगर मैं दिल्ली की वो बात कर रहे हैं तो मैं जरा पंजाब की तरफ भी ले जाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। ये पंजाब में इनकी खबर छपी है पंजाब डेब्ट क्रॉस ₹4 लाख करोड़। यह है इनकी सच्चाई अध्यक्ष जी। अगर हमारे ऊपर यह कह रहे हैं कि इन्होंने रेखा गुप्ता जी public debt ले रही है तो यह जरा बता दें, ये देख ले अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब के अंदर आपके आने के बाद आपने अपने टेन्योर में 1 लाख 28 हजार करोड़ का loan लिया है और आज पंजाब 4 लाख के करोड़ के loan के ऊपर बैठे हैं। ये है इनकी सच्चाई आम आदमी पार्टी की सच्चाई। दिल्ली के अंदर लूट के गए हैं, अब पंजाब में लूट रहे हैं, यह है इनकी सच्चाई। बधाई देना चाहता हूं green budget, 21% budget किया है green budget. साहब कह रहे हैं सब कुछ तो सेम है। क्या हुआ इसके अंदर? तो भैया उनको नजर आना चाहिए अगर दिल्ली के अंदर आज सीवर की लाइन बिछ रही है तो उनके आंखें अगर बंद है तो मेरा कसूर नहीं है। दिल्ली के अंदर आज पानी की लाइनें बिछ रही हैं तो उनका कसूर है।

अगर अगर दिल्ली के अंदर सड़कें बन रही हैं तो उनको नजर नहीं आ रहा तो उनका कसूर है। दिल्ली के अंदर आज खुद आशीष जी कल बोल रहे थे कि अटल कैंटीन के लिए विपक्षी लोग मांग कर रहे हैं। तो यहां पैसा यहां खर्च हुआ है। दिल्ली के अंदर EV buses आ रही हैं अगर उनको नहीं दिख रही तो उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। तमाम तरह की बातें 21% अगर budget रखा है तो अगर wall to wall सड़कें बनेंगी तो वहां वहां लगेगा। अगर दिल्ली के अंदर EV buses आएंगी तो green budget वहां होगा। अगर दिल्ली के अंदर अगर forest area बढ़ेगा तो green budget वहां होगा। तो इसलिए बातें वो बहुत जो भी कर लें लेकिन मैं बधाई दूंगा एक बार फिर अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली का इतना शानदार budget पेश किया है और हम बधाई पूरी ministry को कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, विकास के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रवि नेगी जी।

श्री रविन्द्र सिंह नेगी: आदरणीय अध्यक्ष, जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि दिल्ली का ऐतिहासिक budget इस बार आया और ऐसा budget आया कि जो पहले कभी हुआ नहीं और ना मेरे को लग रहा है भविष्य में भी जब तक हमारी सरकार है, हमारी सरकार में ही होगा और कोई कर भी नहीं पाएगा। मैं इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस budget में जिस education की बात ये लोग करते थे, मैं खुद पटपड़गंज विधानसभा से आता हूं जहां से Deputy CM सिसोदिया जी थे जिन्होंने लोगों को 12 साल तक बेवकूफ बनाया। एक 12वीं पास से शिक्षा मंत्री दिल्ली के model को चला रहा था। यह कितना दुर्भाग्य की बात थी। बात बहुत ऊंची ऊंची थी। पर इस बार जो budget आया 103700 करोड़ का जिसमें से 19% budget शिक्षा विभाग को दिया गया और जिसमें पहली बार हो रहा है कि दिल्ली की उन बच्चियों को साइकिल देने की बात की जा रही है जिन बच्चों के जिन बच्चों के पास साधन सीमित होते हैं उन बच्चों को आज साइकिल दे रहे हैं। उन मेधावी बच्चों को laptop देने की बात हो रही है। आप सोचिए ये budget उन्हें अंतोदय की बात जो हम करते हैं माननीय दीनदयाल जी के सपनों को जो पूरा करने की हम बात करते हैं इस budget से साफ जाहिर होता है ये budget पंडित दीनदयाल जी के सपनों को पूरा कर रहा है और आज आप देखिए आप आ जाएंगे स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य में 12.6% और इस budget का 12893 करोड़ रुपए इस budget में दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनमोल एक ऐसी पहल करी है अनमोल आप सोचिए

जिसमें एक बच्चा जब शिशु पैदा होता है तो 50 तरह की उसे बीमारियां हो सकती हैं। तो उस बच्चे का 60 से ज्यादा उसके टेस्ट होंगे और यह टेस्ट दिल्ली के अस्पतालों में मुफ्त होंगे और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो बच्चे इलाज करा रहे हैं उनके लिए भी मुफ्त होंगे। यह ऐतिहासिक एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाई जिसमें पैसे दिए। आयुष्मान आयुष्मान भारत जो 700 जन आरोग्य मंदिर 750 खोलने की बात और करी है। 350 खुल चुके हैं एक हजार total इस time हो चुके हैं। DTC की बात करेंगे। DTC में 12.16 प्रतिशत total budget का 12613 करोड़ दिए जिसमें 5800 ईवी बसें 2027 में बेड़े में शामिल हो जाएंगी। total बसें 7500 बसें 2027 में टारगेट रखा हुआ है। आप सोचिए जो प्रदूषण की बात जो पुरानी सरकारें हमें प्रदूषण दे गई थी उनको खत्म करने के लिए ईवी बसों की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जब पटपटगंज से जीत के आए मेरे आगे चुनौती थी क्योंकि Deputy CM थे। उस क्षेत्र में ₹250 करोड़ इस बार माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मुझे उस उस क्षेत्र के विकास के लिए ₹250 करोड़ मिले। मैंने जब पिछला खंगाला मुझे पता चला माननीय Deputy CM सिसोदिया जी ने 23 और 24 और 25 में एक रूपया भी उस क्षेत्र में लगाया नहीं है 3 साल उन लोगों ने और आज 250 करोड़ का budget उस क्षेत्र के लिए मुझे मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक इस green budget के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीया सदस्य श्रीमती शिखा राय।

श्रीमती शिखा राय: धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी को इस ऐतिहासिक, दूरदर्शी और जनहितकारी budget के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूं और अपने ग्रेटर क्लास विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों की ओर से आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि जिस विषय पर सालों साल सावित्री सिनेमा का वो पुल जो एक तरफ बना दिया गया था जिसको दो side बनना था आपने उसको पहले ही वर्ष में इस योजना को लेकर उस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी राहत दी है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी यह आय का लेखाजोखा नहीं है यह दिल्ली के भविष्य की रूपरेखा है। यह समावेशी विकास का road map है और सबसे महत्वपूर्ण यह संवेदनशील शासन और मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। अध्यक्ष जी अगर किसी सरकार की नीयत समझनी हो तो यह देखा जाना चाहिए कि वह अपने यहां की महिलाओं और बच्चियों के प्रति क्या सोच रखती है। इस सब budget की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल

infrastructure आंकड़ों या घोषणाओं तक सीमित नहीं है। यह budget समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ महिला और बेटियों के विकास की दिशा तय करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित करता है। अध्यक्ष जी जब हमने इस देश में अपने प्रधानमंत्री को toilets और उज्जवला गैस योजना के माध्यम से अपने देश की महिलाओं की सेवा करते हुए देखा तो हम निश्चित रूप से यह जानते थे कि जब दिल्ली में भी हमारी सरकार आएगी तो हमारा नेतृत्व यही सब कुछ करेगा। इसीलिए महिला एवं बाल विकास के लिए जो 7406 करोड़ के बजट का प्रावधान हुआ है यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उन करोड़ों महिलाओं का विश्वास है जो आज खुद को इस व्यवस्था का केंद्र मान रही हैं। यह सिर्फ एक बजट हेड नहीं है, यह एक संदेश है कि दिल्ली की सरकार महिलाओं को सहायता नहीं सशक्तिकरण दे रही है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा तक जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी इसमें लगभग 1.2 लाख तक की सहायता सुनिश्चित होगी। लखपति बिटिया योजना पहले मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उसकी जानकारी दी है। यह केवल एक योजना नहीं है। यह समाज की सोच बदलने का प्रयास है। जहां बेटी बोझ नहीं बल्कि भविष्य की पूंजी बनती है, यह उस सोच को दर्शाता है। स्कूलों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम है। यह योजना केवल एक सुविधा नहीं देती है बल्कि बेटियों की गरिमा, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों को सुरक्षित करती है। अब कोई भी बेटी सिर्फ इस कारण से स्कूल से वंचित नहीं रहेगी कि उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। रानीहाट 10 करोड़ का यह प्रावधान यह पहल महिलाओं के उनके कौशल के लिए सीधा बाजार प्रदान करेगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वासी बनाएगी। अध्यक्ष जी, साइकिल योजना जिसका बार-बार जिक्र हर मेरे साथी ने यहां अपने वक्तव्य में किया है। यह वाकई ही एक बहुत ही और महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम है। यह योजना केवल सुविधा ही नहीं देती बल्कि बेटियों की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा फिर से एक बार तीनों को सुरक्षित करती है। यह पहल अपने आप में अनूठी और पहली है और हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष के नेता ने इस साइकिल योजना को मजाक बनाते हुए यह कहा कि इसके बाद हम अब दिल्ली की बेटियों को यूपी में प्रचार के लिए ले करके जाएंगे। अध्यक्ष जी, जो बेटियों को, जो युवतियों को, इस तरह से केवल एक प्रॉप के रूप में इस्तेमाल करने की बात करते हैं जो जिन्होंने अपनी बात कहते समय यह नहीं सोचा कि वह उस बात में बेटियों की गरिमा छुपी है। उनसे हम क्या उम्मीद करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह निंदनीय है। उनको दिल्ली की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। बहुत शर्मनाक बयान था उनका। One stop centers and CCTV के माध्यम से महिलाओं को त्वरित सहायता मिलेगी। सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण बनेगा सीसीटीवी के

विस्तार से। यह दर्शाता है कि सरकार केवल सशक्तिकरण की बात नहीं करती बल्कि सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। दुर्गा योजना, के तहत 1000 महिलाओं को ऑटो परमिट देना यह केवल एक योजना नहीं है। यह महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वावलंबन, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता देने की एक निर्णायक पहल है। अब महिलाएं केवल सफर करने वाली नहीं बल्कि सफर तय करवाने वाली बनेंगी। महिला सशक्तिकरण का एक व्यापक दृष्टिकोण इस बजट में लिया गया है। यह बजट महिलाओं को हर स्तर पर मजबूत करता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सुरक्षा के स्तर पर और अवसरों के स्तर पर। जिनके सपनों को कभी सीमाओं में बांधा गया था। आज वही सपने हमारी दीदी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उड़ान भरने को तैयार हैं। यह बजट उसी उड़ान की शुरुआत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नारी को सम्मान दे वही असली विकास है। जिस घर में बेटी मुस्कुराए वही देश खास है। यह बजट नारी सम्मान का संकल्प है। यह बेटियों के आत्मविश्वास की नींव है और यह दिल्ली के उज्जवल भविष्य की मजबूत शुरुआत है। मैं इस बजट के लिए हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूं।

(समय की घंटी)

(सांय 4..51 बजे श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्रीमती शिखा रॉय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट ऐतिहासिक बजट है। 2025 में एक लाख करोड़ रूपया देकर दिल्ली के बजट को एक अच्छी सशक्त नींव हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने रखी और इस वर्ष एक लाख तीन हजार सात सौ करोड़ का ऐतिहासिक बजट दिया। 2025 में जो इकोनॉमिक सर्वे बताते हैं कि हमारी जो जीडीपी थी 24 में 12 लाख 13000 करोड़ थी और इस वर्ष 2025 जो गया है 13 लाख 27 हजार 55 करोड़ यानी के एक लाख 14 हजार करोड़ से भी ज्यादा जीडीपी बढ़ी है 9.42% की दर से। यह दिखाता है कि दिल्ली सही डायरेक्शन में चल रही है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 05 लाख 31 हजार 610, 7.92% की दर से बढ़ी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में पहली बार प्रति व्यक्ति आय पांच लाख से ऊपर बढ़ी है। यह बहुत अभिनंदन के पात्र हैं और राष्ट्रीय औसत से यह ढाई गुना ज्यादा है। CAPEX

ऑल टाइम हाई है। inflation all time low ऑल टाइम लो है। fiscal deficit control कंट्रोल में है। यानी कि सारे इंडिकेटर जो आज बताते हैं कि सही दिशा में चल रहे हैं। जमाना बदल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली बदल रही है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है और चिराग आंधी में जल रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो माननीय हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया है, यह बजट दिल्ली के लोगों की आशा, विश्वास और सपनों को साकार करने वाला बजट। यह बजट विकसित दिल्ली की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा। इस बजट से दिल्ली के युवाओं को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी। इस बजट से दिल्ली में विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकरण होगा। 11572 करोड रूपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा और यह बजट महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा और महिलाओं के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। शिक्षा को भी बेहतर बनाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बजट 19,326 करोड़ रूपये शिक्षा को दिया। यह बजट ग्रीन बजट है। 21% यानी के 22,236 करोड़ रूपये। इसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सोलर सेक्टर तीनों पर विशेष बल दिया है। वाटर, सैनिटेशन, गुड गवर्नेंस, टूरिज्म, कल्चर और सोशल एंपावरमेंट पे भी माननीय अध्यक्ष जी इस पर विशेष बल दिया है। आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री:

''काबिले तारीफ है अंदाज एक-एक काम का

आपके काबिले तारीफ हैं अंदाज आपके एक-ए काम का,

गा रही है गीत दिल्ली रेखा जी के नाम का।''

क्योंकि एक एक काम जो हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं एक-एक काम के बारे में बताऊं तो आयुष्मान योजना सबसे पहली कैबिनेट में लागू की। साढे सात लाख लोगों से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। आरोग्य मंदिर साढे तीन सौ खुल चुके हैं, साढे सात सौ खुलने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी अटल कैंटीन, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में जब हम दिल्ली की सेवा बस्ती में जाते हैं तो मां अन्नपूर्णा के बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं। पांच रूपये में चार रोटी, 300 ग्राम चावल, दाल, सब्जी, आचार। मैं झुग्गी झोपड़ी में जाता हूं तो 13 रूपये में माननीय अध्यक्ष जी एक चाय मिलती है। लेकिन पांच रूपये में भरपूर पेट खाना यह कोई नहीं कर सकता है, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री कर सकती है। एक बार जोरदार मैं इनका अभिनंदन करता हूं। होली और दिवाली पर मुफ्त गैस

सिलेंडर, हिंदी फिल्म का एक गाना आज गुनगुनाते हैं लोग। तुम हो तो हर रात दिवाली हर दिन मेरी होली। माननीय मुख्यमंत्री ने आज साढे सत्रह लाख लोगों को आज दिल्ली के अंदर 260 करोड़ देकर होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर को पिंक कार्ड देकर साढे चार सौ करोड़ रूपये से फ्री डीटीसी बस की ट्रैवलिंग दी है। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को एक लाख 20 हजार उनको फ्री साइकिल उनके हौसलों के ऊपर उड़ान लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 10th पास के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष है हमारी छात्र है, छात्राएं हैं उनको लैपटॉप देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में किया है। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना मैं माननीय अध्यक्ष जी पढ़ रहा था पहली सरकारों में लाडली योजना थी । रुपए भी जमा थे, जमा करके भूल गए। मुख्यमंत्री खोज-खोज कर निकाल रही है पैसे दे रही है उनको। करीब 200 करोड़ से ज्यादा दे चुकी है और अभी 61 हजार रुपए दिल्ली सरकार जमा करेगी और एक लाख 20 हजार रूपये जब हमारी दिल्ली की बेटी ग्रेजुएशन करेगी तो दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री उनके खाते में जमा कराएगी। दुर्गा योजना, आज दिल्ली के जो आधी आबादी है वो माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रही है। 1000 महिलाएं, 100 ट्रांसजेंडर, 1100 लोग, 1100 को ऑटो परमिट देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी recreational activities के लिए 25 करोड़ रूपया है। शिक्षा में 25-26 में 7000 स्मार्ट बोर्ड क्लास रूम बनाए। अभी 26-27 में 8777 बनाने की योजना है और कुल मिलाकर डेढ सौ करोड़ रूपये में 21000 स्मार्ट क्लास रूम बनाने की योजना है। हमारे डीटी आयोग एक नई पहल है। दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक नीति आयोग के तर्ज पर दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली में नवाचार के लिए, दिल्ली की फोकस प्लानिंग के लिए ये जो नया इनिशिएटिव हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है उनका अभिनंदन और जो, जो समाज बिल्कुल पिछड़ा है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता गिग वर्करस, ट्रांसजेंडर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर इनके लिए इस बजट में वेलफेयर बोर्ड बनाने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है मैं उनका अभिनंदन करता हूं और सबसे बड़ी बात है महिला समृद्धि योजना। पिछले वर्ष भी बजट में रखा और इस बार भी 5100 करोड़ रूपए, 2500 रूपए हर महीने मिलने का जो काम है वो इस बजट से उसपे और गति मिलेगी। मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री का हमारी मॉडल टाउन विधानसभा के लिए अभिनंदन करता हूं कि हमारे यहां दो जगह से पानी आता है माननीय अध्यक्ष जी। हमारे चंद्रावल से और वजीराबाद से और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 475 करोड़ दिया है और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एशियन डेवलपमेंट बैंक से टाई अप करके जिससे कि आने वाले दिनों में हमारी विधानसभा में जो पानी की समस्या है

वो खत्म होगी और नजफगढ़ ड्रेन जो कि हमारी मॉडल टाउन विधानसभा से होकर गुजरती है जिस पे के 54 किलोमीटर दोनों साइड रोड बनाने का जो निर्णय लिया है। मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। विशेषकर आजादपुर और त्रिपोलिया गेट के ऊपर इंटीग्रेटेड फ्लाई ओवर भी इस बजट में 2.16 कि.मी. दिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। घंटाघर स्टेशन इंटीग्रेटेड फ्लाई ओवर इसके लिए भी आज .67 कि.मी. का हमारी विधानसभा में जो प्रस्ताव रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अटल कैंटीन खुल रही है, आयुष्मान मंदिर खुल रहा है और सबसे बड़ी बात हमारी विधानसभा में एक मेट्रो स्टेशन था जो गुरु नानक गुरुद्वारे के सामने था और उसका नाम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु नानक प्याओ मेट्रो स्टेशन रखने का काम किया है। मैं पिछले वर्ष में ₹100 करोड़ से भी ज्यादा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉडल टाउन विधानसभा के लिए दिया है। और मुझे तो मैं जिधर देखता हूं हर जगह काम हो रहा है और कभी-कभी तो ये भजन गुनगुनाने का दिल करता है माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है करते हो मुख्यमंत्री मेरा नाम हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सड़कें बन रही है, सीवर लाइन बन रही है, पाइप की लाइन बिछ रही है, नई वाटर की लाइन बदल रही है, अटल कैंटीन खुल रही है, आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। मैं इस बेहतरीन बजट के लिए जो कि विकसित दिल्ली के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रिमंडल का मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं बहुत-बहुत आभार।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: दो मिनट से ज्यादा तो नहीं लोगे ना।

....व्यवधान....

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं चार मिनट नहीं।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: दो मिनट सिर्फ।

...व्यवधान

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: नहीं अच्छा फिर अभी अब रहने दो फिर दो मिनट अगर कर सकते हो।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह:दो मिनट दो मिनट जी दो मिनट दो मिनट।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: हां दो मिनट में कर दीजिए।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी पहले तो रेखा जी मुख्यमंत्री जी के लिए मैं एक शेर कह दूं।

''रेखा जी के बजट में उम्मीदों की नई रोशनी आई है

दिल्ली वालों के चेहरे पर खुशियों की झलक आई है, खुशियों की झलक आई है।''

अध्यक्ष जी दूसरा बाद में कर दूंगा। अध्यक्ष जी सिर्फ मैं दो-तीन बातों में जाना चाहता हूं। बजट जो आया है तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और जो उन्होंने दिल्ली के लिए जो बजट दिया है सबसे बड़ी बात है नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो लैपटॉप हो और उसके बाद जो विपक्ष ने जो साइकिल के लिए कहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप इसी तरह काम करते रहे हम आपके साथ हैं दिल्ली वाले आपके साथ हैं। विपक्ष वाला जो मर्जी बोलता रहे उसकी परवाह नहीं करनी है। अध्यक्ष जी एजुकेशन के लिए 20% 20 हजार करोड़ रूपया एजुकेशन के लिए, की हमारी दिल्ली की जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं वो आगे बढ़े। उसके बाद दिल्ली नगर निगम को भी अध्यक्ष जी दिल्ली नगर निगम को पहले कई सालों से बिल्कुल बजट नहीं मिला। सड़कों का बुरा हाल, कूड़ादानों का बुरा हाल और कर्मचारी हर साल हड़ताल में जाते थे। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने जो करके दिखाया 1200 करोड़ रूपया दिल्ली नगर निगम को दिया और सबसे बड़ी बात मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह बाकी एमएलओं ने कहा है कि हमको इतना बजट दे दिया और कई एमएलए ने यह भी कहा बजट बस करो दीदी क्योंकि बजट बहुत मिल गया है हमको। मतलब सौ-सौ करोड़ रूपया बजट देने के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे यहां भी 120 करोड़ रूपया बजट आ चुका है बाकी और आ जाएगा। जोरदार मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद करो। सब मिलके एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करो।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह:जो आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री चर्चा का उत्तर देंगी।

...व्यवधान....

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस सदन का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं जिन्होंने अपने विचारों के साथ में इस बजट को और मजबूती दी। मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि विपक्ष के भी सुझाव हमें मिलेंगे, वो अपनी बात कहेंगे तो इस बजट को अगर कहीं स्कोप है तो और बेहतर करते हम। मुझे लगता है अध्यक्ष जी कि ईश्वर ने हमारे विपक्ष के इन भाई बहनों को मौका दिया सदन में बैठने का। परंतु उन्होंने इसका सम्मान नहीं किया। उन्होंने सड़क पर बैठना उचित समझा। अगली बार ईश्वर करे वो सड़क पे ही बैठें और सड़क पर बैठे ही रहें। हम बढ़िया सड़कें बनवा ही रहे हैं। हम बढ़िया सड़कें बनवा ही रहे हैं तो वो अच्छे से बैठें । जब सदन की मर्यादा का उनको अनुभव ही नहीं है तो फिर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरे साथी विधायकों ने बजट में दी जा रही योजनाओं के बारे में डिटेल में चर्चा करी। मैं केवल कुछ बिंदुओं पर इस सदन का ध्यान लाना चाहूंगी। विपक्ष के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं था तो उन्होंने दो-तीन चीजें जो यहां वहां से डाली उसमें भी ऐसे लोग ही ज्यादा बोले जिनका इस सदन में बोलने का भी कोई हक नहीं है, इस सदन की बातचीत पर कहने का भी कोई हक नहीं है। कहा कि लोन ले लिया, लोन ले लिया। हरीश खुराना जी ने बताया कि लोन आज का नहीं है। सालों से जिस तरीके से लोन लेने की परिपाटी यहां बनाई गई वो 1999 से शुरू हुई। 1999 में 1164 करोड़ का लोन लिया गया और वह भी 10.50% पे लिया गया लोन। 2000 में 1500, 2001 में फिर दोबारा 1773 और करते करते जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तब भी एक भी साल ऐसा नहीं है जब लोन नहीं लिया गया हो, एक भी साल और मजेदार बात ये है कि किस परसेंटेज पे लिया गया यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इतनी अधिक परसेंटेज पे उन्होंने लोन उठाया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था जिसको आज तक ये सरकार चुका रही है। मैं बताना चाहूंगी विशेष रूप से 2019-20 में 450 करोड़ का लोन उन्होंने लगभग 9% पे लिया। 2020-21 में 9500 का लोन लिया वो भी लगभग इसी प्रतिशत पे लिया। 2021-22 में 5000 करोड़ का, 2022-23 में फिर 3200 करोड़ का और ये बिल्कुल सही फिगर कही कि इनके कार्यकाल में जो लोन था वो 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन हो गया था। 47,000 करोड़ का लोन वो सरकार पे छोड़ के गए हैं। उनके हाथ का लिया हुआ, आके हमारी सरकार ने चुकाया, उसका ब्याज, उसका मूल और आज की डेट में उनके लिए हुए लोन का हिस्सा मैं बताना चाहती हूं, 27,547 करोड़ रूपये आज भी उनका लिया हुआ लोन सरकार के ऊपर खड़ा है, यह बात बताती हूं। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। खाली लोन नहीं है और भी बहुत कुछ है। जो उनकी देनदारियां हम दे रहे हैं। जब वो कहते हैं ना 2,500 रूपये नहीं दिए, 2,500 रूपये नहीं दिए, तो मैं बताना चाहती हूं कि हम क्या-क्या दे रहे हैं जो आप दिल्ली की जनता के लिए छोड़ करके गए, यह

गरीबी, यह देनदारियां, 3700 करोड़ रूपये एक्सप्रेसवे का। आपको मालूम है केंद्र की और राज्य की पार्टनरशिप होती है इन एक्सप्रेसवेज़ को बनाने के लिए। पर पिछली सरकार ने एक रूपया भी उस मद में दिया नहीं जबकि सब कुछ वो दिल्ली के लिए हो रहा था। ईस्टर्न पेरिफेरल वेज़, वेस्टर्न पेरिफेरल वेज़ सब कुछ दिल्ली के लिए था कि दिल्ली को डीकंजस्ट किया जा सके। पर 3700 करोड़ रूपये उनके नाम के आज भी हमारी सरकार दे रही है। इस बजट में भी हमने इसका एक हिस्सा देने के लिए रखा है।

मेट्रो, मेट्रो चली तो बताइए जरा किसका फायदा हुआ? आज लाखों लोग रोजाना मेट्रो में सफर करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन यह एग्जांपल बन गया है, जिससे सड़कों पर डीकंजेशन होता है, ट्रैफिक जाम नहीं होता। आप कल्पना करके देखिए मेट्रो के बिना दिल्ली का शहर क्या होगा? सोच नहीं सकता एक व्यक्ति। परंतु उन्होंने कभी एक रूपया इस हेड में दिया नहीं। और कोर्ट में कोर्ट ने जब कहा तो ग्रांट जो केंद्र सरकार से 958 करोड़ की हर साल मिलती थी उस ग्रांट को केंद्र ने फिर अपने पास मेट्रो के हेड में रखना शुरू किया। परंतु दिल्ली की सरकार ने, उस समय की सरकार ने एक रूपया नहीं दिया। आज भी 9 हजार 87 करोड़ रूपये उनके पेंडिंग थे फेज वन, टू और थ्री के जिसमें से 2700 करोड़ रूपये हमने आने के बाद उनके हेड का चुकाया है।

अस्पतालों की बात हो रही है। अस्पताल अधूरे छोड़ के भाग गए, पूरे नहीं किए और अधूरे कोई 2025 में जब सरकार बदली तब के नहीं हैं, चार-चार साल से इन अस्पतालों का काम बंद पड़ा है। केवल उनकी मिसमैनेजमेंट, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई दूरदृष्टि नहीं थी। उन सारे हस्पतालों के हेड में आज भी 2000 करोड़ से ऊपर की देनदारी दिल्ली सरकार के ऊपर चढ़ी हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों स्कूल अधूरे, कहीं कुछ काम बाकी है, कहीं कुछ है और कई पूरी नई बिल्डिंग जो बननी शुरू हुई थी, वो सात-सात साल से अधूरी पड़ी है, उसकी कॉस्ट चार-चार गुना हो गई। 20 करोड़ के स्कूल को 80 करोड़ में भी पूरा नहीं हो पा रहा। इतना भ्रष्टाचार किया। उस हेड में भी 1 हजार करोड़ से ज्यादा की देनदारी आज भी सरकार पे चढ़ी हुई है। शर्म आती है मुझे यह सोच के भी कि कैसी सरकार थी, कैसे नेता बैठे थे। बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के जो पैसे देने थे, जो इनाम देने थे, 24 करोड़ रूपये, दिए नहीं खिलाड़ियों को। ईडब्ल्यूएस वेलफेयर के 18 करोड़ रूपये दिए नहीं उन्होंने। यह आके हमने चुकाए हैं। स्कॉलरशिप के पैसे.. 17.5 करोड़ रूपये आके हमने दिए। अवार्ड के पैसे 14.5 करोड़ रूपये आके हमने दिए हैं। किशोरी योजना के 12 करोड़ रूपये। और ऐसे ही सारे मदों में पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के

आर्बिट्रेशन के पैसे हमने दिए। मतलब बारापुल्ला पुल की बात बताती हूं, उसमें ठेकेदार को बिना काम किए कि मेरी मशीनरी खड़ी थी और इनकी वजह से 2 साल काम रुका रहा, इसके लिए उसने कोर्ट में जाकर 250 करोड़ रूपये मांगे और सरकार को देने पड़े, 250 करोड़ रूपये उस हेड में देने पड़े, बिना काम के वो ठेकेदार लेकर के चला गया। मैं पूछना चाहती हूं कि यह क्या है, किस बात का उनकी पढ़ी लिखी सरकार का काम है?

इसी तरीके से ईवी पॉलिसी के, पॉलिसी दिखा दी परंतु ईवी पॉलिसी में एक रूपया दिया नहीं। हमने आने के बाद 48 करोड़ में से 24 करोड़ रूपये अभी पिछले कुछ दिनों हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के माध्यम से दिए हैं।

एससी, एसटी, ओबीसी की ट्यूशन फीस 114 करोड़ रूपये हमने आने के बाद दिए हैं। और इसी तरीके से डीएमआरसी और पीडब्ल्यूडी के जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट थे उसमें 1031 करोड़ का बकाया था वो हम आ करके उन प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जा रहे हैं। ना कभी ड्रेस टाइम पे दी, ना कभी किताबें टाइम पे दी। किस, किस सरकार चलाने की बात करते हैं और किस मुंह से बात करते हैं?

जिस शहजानाबाद बोर्ड की वो बातें करते हैं कि हमने चांदनी चौक को बहुत बढ़िया बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया। जब फाइलें खुली, हमने देखा तो 50 करोड़ रूपये वो जो सड़क एक बनी है उसके मद में 50 करोड़ रूपये आज भी कॉन्ट्रक्टर की देनदारी पेंडिंग है दिल्ली सरकार के ऊपर, पैसा नहीं देके गए, नंबर बनाते रहे, ऐड कराते रहे। यह हाल है।

12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं उनकी 538 करोड़ की देनदारी यानी टीचर्स की, प्रोफेसर्स की सैलरी नहीं दी, ग्रांट इन एड नहीं दी, वह भी हमने आके चुकाई।

और तो और धिक्कार है ऐसे नेताओं पे और ऐसी सरकार पे जो थी यहां पर जिसने गौशालाओं की ग्रांट इन एड रोक ली, 24 करोड़ रूपया हमारी सरकार ने आके दिए हैं। गौशालाओं का पैसा खा गए, गायों का पैसा खा गए, एक पैसा नहीं दिया। बात किस मुंह से करते हैं ये लोग हमसे?

'जय भीम स्कीम' बड़ा अंबेडकर जी के अनुयायी बनते हैं, 'जय भीम योजना' में 31 करोड़ रूपये हमारी सरकार ने आकर के हमारे ऊपर देनदारी चढ़ी हुई है।

हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप हमने आके बांटी। एक बार 25 करोड़ बांटी, एक बार 19 करोड़ बांटी, दी नहीं उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप, हमने आने के बाद दी है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे?

कोविड, यह देखिए नेतागिरी करनी होती थी, कहीं पे ऐसा कोई मर्डर हो गया, कहीं दंगा हो गया तो तुरंत केजरीवाल साहब पहुंच जाते थे एक करोड़ रूपये का चेक लेके नेतागिरी करने के लिए, अगले दिन अखबार में छपने के लिए पर कोविड में जो सरकार के एम्पलाइज, जो डॉक्टर मरे उनको एक रूपया नहीं दिया। हमारी सरकार ने आने के बाद 20 करोड़ रूपये उस हेड में दिए हैं कोविड में मरे हुए लोगों को जो हमारी सरकार के एम्पलाइज थे।

यह वो लोग हैं जिनको केवल हर चीज में राजनीति चाहिए। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की बात करते हुए भी, वो बात करते हैं 1 हजार करोड़ का लोन ले लिया, 1 हजार करोड़ का। उनसे मैं पूछना चाहती हूं डीटीसी की फिगर बताऊं कितने घाटे में चल रही है डीटीसी, 99 हजार करोड़ के कर्ज में है डीटीसी आज भी। जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड 91 हजार करोड़ के लॉस में है, उभर नहीं पाया कभी ऊपर, उभर नहीं पाया।

और यह अभी हमारे जल बोर्ड विभाग एमनेस्टी स्कीम लेके आया। हमारा मन था एमनेस्टी स्कीम पहले दिन से ही ले आए। पर पता चला कि उनका जो पूरा बिलिंग का सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम वो पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से डिफंग था। महीनों से लोगों के पास में पानी के बिल नहीं गए थे। और बिल नहीं जाने के कारण जब एकदम से बिल आए तो वो इतने enormously बढ़ गए कि किसी का बिल 5 लाख का, 10 लाख का और वो घूम रहे थे 2 साल से। हमारा बिल देखिए अचानक कितना आ गया है पर किसी को समाधान नहीं दिये उन्होंने। आज क्या हालत है ड्यूसिब की, क्या हालत थी जल बोर्ड की, क्या हालत थी डीटीसी की, यह सारी दुनिया जानती है, पूरी दिल्ली जानती है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है हमें। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को हाल किया।

वो बोलते हैं दिन में तीन बार मुझको गाली देते हैं, दिन में तीन बार मुझको गाली देते हैं, सरकार ऐसे चल रही है। अरे आप दिल्ली शहर के लिए टीबी बन गए, टीबी, ऐसे फेफड़ों से चिपक गए कि हम कुछ भी दवा दारू कर रहे हैं हट नहीं रहें। टीबी बन गए आप दिल्ली शहर के लिए, चिपक गए दिल्ली के फेफड़ों के साथ में। हमने बड़ी कोशिश की कि अब धुल जाए, अब धुल जाए, पर यह दाग है कि धुलने का नाम नहीं ले रहें। हर रोज एक नई फाइल खुलती है, हर रोज एक नई फाइल खुलती है, नया घोटाला, नया भ्रष्टाचार दिखाई देता है। दिल्ली की

जनता कैसे ऐसे गुनहगारों को माफ कर सकती है और ये लोग अपने आप को ज्ञानी कहते थे। पढ़े लिखे, आईआरएस ऑफिसर हैं। ऐसे पढ़ी लिखी सरकारें चलती थी। किस तरीके से पैसा तो खर्च हुआ, सड़क नहीं पूरी हुई। पैसा खर्च हुआ, अस्पताल नहीं पूरा हुआ। ठेकेदारों को पेमेंट दे दी गई पर प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए। बच्चों के स्कूल अधूरे रह गए अध्यक्ष जी, बच्चों के स्कूल अधूरे रह गए। और फिर भी यह दावा कि हमने दिल्ली बदल दी। शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे लोगों की बातचीत सुनकर के।

ये सरकारें कोई सपनों से और नारों से नहीं चलती है। सरकारें सिस्टम से चलती है। और जब सिस्टम जवाबदेही से खाली हो जाए तो परिणाम यह होते हैं जो वो देकर के गए हैं। यह सीधा-सीधा गवर्नेंस का फेलियर है अध्यक्ष जी। गवर्नेंस का फेलियर है। जब दिल्ली को आगे बढ़ना था, तब इन्होंने टकराव चुना। जब दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी जानी थी तब इन्होंने राजनीति चुनी। जब काम करना था तो केवल आरोप लगाए। आरोप लगाए कभी केंद्र सरकार पर, कभी प्रधानमंत्री पर, कभी एलजी पर, कभी बाकी अन्य राज्यों पर और कभी अधिकारियों पर, कभी काम नहीं किया। जब जवाब देना था तो जिम्मेदारी से बचते रहे। ऐसी सरकार यहां बैठी थी अध्यक्ष जी पर अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। अब हर रुपए का, जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई का हिसाब हम देंगे। हर काम को पूरा करेंगे। अब दिल्ली बहानों से नहीं परिणाम से चलने वाली है, परिणाम से चलने वाली है। अध्यक्ष जी, इस टकराव की राजनीति ने जनता को मरहूम किया उन सारी सुविधाओं से जो केंद्र सरकार देती थी राज्यों को। इन्होंने कभी उन योजनाओं को लेने की और तकलीफ नहीं करी। सोचा की हमारा नाम नहीं होगा इन योजनाओं को अगर ले लेंगे। इस मद में भी मैं बताना चाहती हूं दिल्ली का कम से कम हर, हर साल का 5000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 5000 करोड़ रुपये का और जीएसटी का जब वो मिल रहा था कंपनसेशन तो फटाफट ले लिया। 1200 करोड़ रुपये, कभी 5000 करोड़ रुपये, 12000 करोड़ रुपये तक भी 5 साल तक जीएसटी का कंपनसेशन आया वो तुरंत दबा लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया पर जो योजनाएं केंद्र की थी वो नहीं ली। कहीं पीएम आवास योजना ले ली तो नाम प्रधानमंत्री जी का ना हो जाए। आयुष मिशन के अंतर्गत पैसे ले लिये तो नाम केंद्र सरकार का ना हो जाए। पीएम श्री स्कूल बनवा लिए, केंद्रीय विद्यालय बनवा लिए तो इसका नाम, इसका क्रेडिट केंद्र सरकार को ना मिल जाए यह हाल था उनका। यहां तक कि हमारे किसान भाइयों को भी उससे उन योजनाओं से अलग रखा जो केंद्र सरकार लगातार देती है और इसका फर्क सिर्फ कागजों में नहीं दिखा अध्यक्ष जी, इसका फर्क जमीन में दिखा, रिजल्ट्स में दिखा। दिल्ली बद से बदतर होती चली गई। नगर निगम की सेवाएं, उनकी

क्वालिटी गिरती गई। दिल्ली की स्वच्छता खराब होती गई। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता रहा। दिल्ली में यमुना गंदी होती रही पर यह लोग केवल आरोप लगाते रहे। इनके लोग मुख्यमंत्री आरोप लगाते थे, मंत्री खुद ही धरने पर बैठ जाते थे, नहीं तो आपस में लड़ते थे, समय मिलता था तो अधिकारियों को पीटते थे। यह, यह कल्चर था उनका, यह वर्किंग कल्चर था जिस तरीके से उन्होंने यहां काम किया। किसी पड़ोसी राज्य से उनकी बनती नहीं थी हैं जब तक जब तक वो पंजाब में नहीं थे तो पराली से प्रदूषण हो रहा था। जैसे ही पंजाब में हुए तो पराली से प्रदूषण खत्म हो गया। फिर पंजाब का कोई लेना देना ही नहीं रहा फिर तो बाकी सब कर रहे हैं। बाकी तो हम दिल्ली सरकार ही जनरेट कर रही है सारा पोल्यूशन। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सरकारें पहले भी होती थी परंतु वह ईमानदार होती थी अपने राज्य के लिए। हमारा यह बजट आया, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं इस सदन को हमारा यह बजट आया तो हमारे इस बजट में अभी तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पूरी दिल्ली सरकार का है, सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। केवल फ्रीवीज नहीं इस दिल्ली में विकास करके दिखाना है और विकास के कार्य लगातार दिल्ली में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने इन विकास कार्यों के माध्यम से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया और इस साल फिर से हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। यह गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा बदलाव है और हमने हर एक प्रोजेक्ट, यह नहीं की प्रोजेक्ट दसियों साल तक चलता रहेगा। हमने सीएम प्रगति पोर्टल, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पीएम प्रगति पोर्टल चलाते हैं अपने राज्य में हमने सीएम प्रगति पोर्टल बनाया ताकि हर एक प्रोजेक्ट की निगरानी हो सके, मॉनिटरिंग हो सके और समयबद्ध तरीके से हर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके अध्यक्ष जी। यह, यह होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जनता के प्रति और जनता के एक-एक पैसे के प्रति। हमने जिस तरीके तरीके से अपनी इस सरकार का बजट बनाया मैं जरूर इस सदन को बताना चाहूंगी। जब विपक्ष तोहमत लगाता है। ऐसे लोग जो अपने आप को पढ़ी-लिखी सरकार कहते हैं। आज हमने जो बजट पेश किया उस बजट में जो लोन हम ले सकते हैं हमेशा जीएसडीपी का एक परसेंटेज होता है 3% तक कोई राज्य उस पर लोन ले सकता है, फिसिकल डेफिसिट उसका 3% तक हो सकता है। हमने कितना लिया, हमने मात्र 1.17% जो कि इस राज्य के लिए बेहद ही जरूरी है और वो भी देश में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7.4% पर हमने यह लोन लिया है ताकि दिल्ली में विकास कार्य हो सके। पंजाब की कहानी तो भाई हरीश खुराना जी ने बता ही दी है कि 4-4 लाख करोड़ के लोन उन्होंने ले रखे हैं और उनकी outstanding debt ratio जो है वो 44% की है अध्यक्ष जी। पंजाब को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। दिल्ली को बर्बाद करके गए और अब पंजाब

को बर्बाद किया है पर हमारी सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। ऑनेस्ट है, कमिटेड है, एफिशिएंट है। हमें कुछ भी चीज छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने है और पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट ने एफ.आर.बी.एम. टारगेट्स और कमिटमेंट्स को ओपनली जनता के सामने, सदन के सामने रखने की जिम्मेवारी ली है। हम fiscal discipline बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। हमारे यहां दिल्ली शहर में, दिल्ली राज्य में sustainable economic growth को हम आगे बढ़ाने के लिए रिस्पांसिबल हैं और सही तरीके से fiscal management कर रहे हैं और लगातार इस दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है। मैं इतना कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, हमारे लिए हर सेक्टर प्रायोरिटी है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जल हो, हर एक विभाग में हमें काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्षों से दिल्ली तरस रही है इन सारी सुविधाओं के लिए। दिल्ली को मिल नहीं रही थी वो सुविधाएं और इसीलिए हमने शिक्षा में एक बड़ा बजट दिया और इतने बड़े बजट के साथ में हमने यह कोशिश की कि बच्चों को समय पर किताबें मिले, बच्चों को समय पर ड्रेसेस मिले। यह पूरे के पूरे हमारे जितने दिल्ली में स्कूल हैं हर क्लास को हम स्मार्ट क्लासेस बनाएं। कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, साइंस लैब हो, अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड हों ये सारी सुविधाएं हमारे स्कूलों में हों इसके लिए हमने काम किया। पर पिछली सरकार क्या करती थी, पिछली सरकार अपना मॉडल तो बताती थी कि शिक्षा का मॉडल हमारा बेहतरीन मॉडल है पर कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगी अध्यक्ष जी। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो सच्चाई बयां करते हैं कि किस तरीके का एजुकेशन मॉडल वो फॉलो करते थे। मैं बताना चाहूंगी उन एनरोलमेंट के आंकड़ों को जब 2022-23 में एक बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है वो 17 लाख 90 हजार था, 17 लाख 90 हजार जो घट के 2023-24 में मात्र 17 लाख रह गया। 90 हजार बच्चों ने छोड़ दिए स्कूल, कह रहे नहीं जा सकते हम। उसके बाद 2024-25 में ये 16 लाख 66 हजार रह गया। हर साल एनरोलमेंट की दर घटती गई, घटती गई। ये बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़े? वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे? क्या इस बात का जवाब ये लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते थे इसीलिए शायद इस सदन में नहीं हैं। उन्हें मालूम था कि हम जवाब क्या देंगे इन सीएजी रिपोर्ट्स का, इन पीएसी रिपोर्ट्स का, इस बजट का जो इतना शानदार बजट है। अपने कामों की क्या बात कहेंगे और क्या प्रश्न पूछेंगे इसलिए वो नहीं आए और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि अरे ये लड़कियों को साइकिल दे रहे हो, हम उनको यूपी ले जाएंगे। यह घटिया सोच, यह नीचता की हरकत करने वाले लोगों को मैं यह पूछना चाहती हूं कि बेटियां तो सबकी साझी होती है। बेटियों को तुम ऐसी बात कहते हो कि हम इलेक्शन कैंपेन में ले जाएंगे। वो पेड दिहाड़ी की लेबर मान रखा है क्या तुमने दिल्ली की बेटियों को। ये दिल्ली की बेटी है आगे

बढ़ेगी, पढ़ेगी, अपना कैरियर बनाएगी, तुम्हारी घटिया बातों में ना तुम्हारी घटिया राजनीति का शिकार बनेगी। हम भी 27 साल विपक्ष में रहे, 27 साल विपक्ष में रहे परंतु हमारे किसी नेता की, किसी कार्यकर्ता की इस तरह की ओछी बातचीत कभी किसी ने कही नहीं। आज हमने यह योजना लाए ताकि हमारी बेटियों का आत्मविश्वास बढ़े। हमारी बेटियां स्कूल जाना चाहे उन्हें सुविधा मिले और ड्रॉप आउट ट्रेड जो है वह कम हो सके। हमने पूरी तरीके से दिल्ली में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। हमने हेल्थ में भी और बाकी पूरे सिस्टम में सालों से जो अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, सालों से जो वैकेंसीज थी हमने उस पर काम किया। पहली बार हेल्थ विभाग में 4478 वैकेंसीज को अप्रूव किया गया और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग की 1194 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर हमने दिए। हमने रेवेन्यू में लगभग 300 लोगों को लगाया। हमने बाकी विभागों में अलग-अलग जगह पर लोगों को अपॉइंट किया, उनको काम दिया ताकि दिल्ली सरकार में जो वैकेंसीज है वो भरी जा सके। लगातार हर एक सेक्टर में इन 365 दिन में सरकार ने काम किया है और केवल अपने बजट से और अपने सोर्सेस से नहीं अध्यक्ष जी हमने पूरी कोशिश की कि केंद्र सरकार की हर मदद, हर योजना का हम हिस्सा बने। हमने दिल्ली में एक बहुत ही शानदार प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट हम केंद्र सरकार की मदद से लाने वाले हैं। मुनक कैनाल उसके ऊपर 5 हजार करोड़ की लागत का एलिवेटेड रोड हम केंद्र की मदद से बनाएंगे जो दिल्ली को, दिल्ली को डीकंजेस्ट करने में बेहतरीन माध्यम साबित होगा। हमने दिल्ली की कुछ रोड भी एनएचआई को देकर के उनको उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बातचीत की है। हमने सीएसआर में भी अनेकों कंपनियों से हमारे जितने दिल्ली के चौक-चौराहे हैं उन पर उनके सौंदर्यकरण के लिए काम किया। हमने टूरिज्म के विभाग के माध्यम से दिल्ली के entry gates को बेहतर करने के लिए योजना बनाई। हमने दिल्ली में नए शौचालय बने उसके लिए काम किया और पहली बार नगर निगम को और बाकी एजेंसीज को इतना फंड दिया ताकि सब लोग मिलकर के एक प्लेटफार्म पे आकर बेहतर दिल्ली स्वच्छ दिल्ली हरित दिल्ली के लिए मिलकर के काम करेंगे। इस, इस पूरी काम को हमने इस विज़न के साथ में आगे बढ़ाया है कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए। दिल्ली का विकास होना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं कि इस दिल्ली में केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। आज दिल्ली में इस वर्ष मेट्रो के दो नए कॉरिडोर्स का उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और तीन नए कॉरिडोर और इसी साल पूरे होने की स्थिति में आएंगे जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है और मेट्रो के फेज फोर के तीन नए कॉरिडोर इसी साल पूरे होंगे और ऐसे ही मेट्रो फेज फाइव के तहत 16 कि.मी. का और एक्सटेंशन दिल्ली की मेट्रो को मिलेगा और दिल्ली देश में सबसे बड़ा मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बन जाएगा,

इस बात को कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। हमने दिल्ली की जितनी एजेंसीज हैं एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, कैंटोनमेंट बोर्ड हर एक एनडीएमसी सबको एक दिशा निर्देश के साथ में कि दिल्ली की हर सड़क वॉल टू वॉल कारपेटिंग होनी चाहिए ताकि डस्ट मिटिगेशन हो सके। दिल्ली को प्रदूषण से बचाया जा सके। लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम Zero-emission Vehicle Transportation पे हम आना चाहते हैं। उसके लिए हमने पहली बार दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में Automated Testing Station बनाए जा रहे हैं। तीन इस साल हमने पूरे करने हैं और पांच और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि कमर्शियल व्हीकल्स का जो फिटनेस है वो कायम रह सके। हम पूरी तरीके से अपनी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को ईवी पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम OEMs के साथ में मिलकर के दिल्ली का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। हर-हर चीज जो आने वाले भविष्य को आने वाली पीढ़ियों को सुविधा देगी और हमारे दिल्ली का आज और कल बेहतर कर सकती है, यहां की हवा साफ कर सकती है उस हर एक एंगल पे उस हर एक सेक्टर पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। कभी पिछली सरकारों ने नहीं सोचा था कि दिल्ली में यह जो रिज एरिया है यह फॉरेस्ट नोटिफाई होना चाहिए। पहली बार हमारी सरकार ने आकर के 4200 हेक्टेयर रिज एरिया को फॉरेस्ट नोटिफाई किया और आगे आने वाले समय में 35 लाख पेड़ों को लगाने का प्रण किया है जो 4 साल में हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार दिल्ली आगे बढ़ रही है। जिस, जिस उसको बातें वो करते हैं लाइट लाइट कोई दिल्ली में किसी भी प्रकार की बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारी सरकार ने बल्कि आने वाले 50 सालों की प्लानिंग करते हुए आज से क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरे शहर में ट्रांसमिशन की और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। नए-नए सबस्टेशंस लगा के दिल्ली को बेहतर करने की ओर दिल्ली आगे बढ़ रही है। और इस सरकार ने पूरा एक मजबूत इको सिस्टम डेवलप करने का काम किया है। जहां हर सेक्टर डेवलप होना चाहिए क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक सेक्टर पे काम छूट जाता है तो यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने जहां इंडस्ट्रियल एरिया के ऑथराइज अनऑथराइज दोनों सेक्टर्स के लिए सड़कें बनाने के लिए फंड दिया तो हमने अनऑथराइज कॉलोनीज में भी इस बार विशेष प्रबंध करके वहां के अंदर की सारी सड़कें बनाने के लिए फंड दिया जो कि पहली बार इतना बड़ा फंड दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को दिया जा रहा है। झुग्गियों में लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने 700 करोड़ का बजट देकर झुगियों में काम किया और इस साल भी एक

बड़ा फंड दिया है हमने लगभग उतना ही 700 करोड़ का। दिल्ली के गांव देहात के लिए हमने पिछले साल भी बहुत बड़ा 1 हजार करोड़ के करीब का फंड खर्च किया और इस साल भी हम 800 करोड़ दिल्ली डेवलपमेंट दिल्ली के गांव देहात के लिए कर रहे हैं। दिल्ली में क्लीन एनर्जीस बढ़े इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। पहली बार दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड पर सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इस पर पॉलिसी लाई गई है। दिल्ली के नालों के ऊपर सोलर सिस्टम लगा के कैसे क्लीन एनर्जी जनरेट की जा सकती है उस पे सरकार काम कर रही है और दिल्ली में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ease of doing business के लिए सरकार ने सैकड़ों निर्णय लिए हैं दृढ़ निश्चय के साथ में। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि हमने लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पुलिस विभाग को अलग किया ताकि बहुत ही आसानी से हमारा यह सेक्टर जो है वह अपनी परमिशंस ले सके। हमने फायर की सारी एनओसीस को ऑनलाइन किया ताकि लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यू करने में फायर का जो लाइसेंस है वो रिन्यू करने में दिक्कत ना हो। हमने पहली बार जो एमसीडी द्वारा बुक्ड प्रॉपर्टीज होती है जो सालों से बिजली के मीटर्स का इंतजार कर रही थीं जहां पर बिजली की खपत तो हो रही थी पर किन माध्यमों से जाती थी वहां बिजली उसमें चोरी थी, उसमें भ्रष्टाचार था परंतु पहली बार दिल्ली की डेढ़ लाख प्रॉपर्टीज को हमने यह अधिकार दिया कि वहां बिजली के मीटर भी लगेंगे और बिजली भी दी जाएगी। अध्यक्ष जी यह सब मिलकर के एक ऐसी सरकार बनाता है जो मॉडर्न भी है एफिशिएंट भी है और रिस्पांसिव भी है। हम हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ उन लोगों को घर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं। ये सब कुछ नहीं हो पाया था आज तक पिछली सरकारों के राज में क्योंकि उनकी नियत ही नहीं थी कि कभी झुग्गी वालों को एक सम्मानपूर्वक जीवन मिल सके। 15 साल की कांग्रेस हो या 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वो चाहते थे ये लोग सदा इसी स्थिति में यहीं बसे रहें और हमारे, हमारे जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं भई, उपकार के आगे उपकार के आगे दबे रहें कि हमने तुम्हारे जीवन पर कितना बड़ा उपकार किया है अगर हम नहीं होंगे तो यह बीजेपी झुग्गी तोड़ देगी, हम नहीं होते तो बीजेपी पता नहीं क्या कर देती। पहली बार झुग्गी निवासियों ने यह महसूस किया है कि बीजेपी आई है सरकार बदली है तो उन्हें सम्मान का जीवन मिल रहा है। उनके नाली सड़क खरंजा बन रहे हैं, उनके शौचालय नये बन रहे हैं, उनके बच्चों के लिए शिशु वाटिका उनके कार्यक्रम करने के लिए वहां पर बस्ती विकास केंद्र ये सारे काम और तो और जो अटल कैंटीन दिल्ली में बनाई गई, आज एक गरीब, गरीब एक श्रमिक भाई-बहन जाकर के सम्मान के साथ 5 रूपये में वहां भोजन करता है ये सारे काम किए तो ये हमारी सरकार ने किए। अध्यक्ष जी सालों से राशन कार्ड नहीं बने थे नए, वर्षों से नहीं बने लोगों के, सुनते-

सुनते कितने साल निकल गए कि नया राशन कार्ड बन नहीं रहा, बन नहीं रहा, हमने दिल्ली में चार कैटेगरीज के लोगों के राशन कार्ड की स्क्रूटनी करी, एक जिनके डबल राशन कार्ड हैं दिल्ली में भी है, किसी और राज्य में भी है, दूसरा जिनकी मृत्यु हो गई, तीसरा जो इनकम टैक्स पेई है। भई मोदी जी ने 12 लाख की इनकम पे टैक्स फ्री कर रखा है। यानी 12 लाख से भी ऊपर जिसकी इनकम है जो टैक्स पेई कर रहा है तो वो कैटेगरी इसमें शामिल नहीं है तो उनके और जो लोग राशन ले ही नहीं रहे तो ऐसी चार प्रकार की कैटेगरीज के नाम निकाल करके उनके राशन कार्ड होल्ड पे किए गए कि भाई आप आकर के जवाब दीजिए और नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की और दिल्ली सरकार आगे बढ़ी तो एक मनघड़ंत स्टोरी इन दिमाग से दिवालिया लोगों ने बना लिया है। अरे अगर यह राशन कार्ड बने, अगर राशन कार्ड बनते हैं 8 लाख, 8 लाख राशन कार्ड बने तो 1 लाख पे अगर कोई रिश्वत लेगा तो 10 हजार की लेगा और 10 हजार की लेगा तो यानि कि हॉं अगर हम लोग होते तो इतनी रिश्वत लेते, ये तो इतना बड़ा घोटाला है!, देखिए मतलब उन्होंने पूरी इमेजिनेशन बना ली कि कितना बड़ा घोटाला होने वाला है अगर ये नए राशन कार्ड बन गए। देखिए, कैसी सोच के लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि दिल्ली की जनता को नए राशन कार्ड मिलें, नए एलिजिबल लोग आगे आयें, वो चाहते हैं जो उनकी चोर बाजारी चल रही थी, जो डबलिंग ऑफ राशन कार्ड चल रही थी, जो इन्होंने अपने-अपने लोग बीच में घुसा करके वहां पे भ्रष्टाचार किया हुआ था, वो यूं ही चलता रहना चाहिए। ना कोई नई पेंशन लगे, ना कोई नया राशन कार्ड बने ऐसी सोच के लोग हैं ये परंतु हमने बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ नए राशन कार्ड बनें इसके लिए काम कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली में होली और दिवाली दो सिलेंडर की बात मेरे साथियों ने कही सरकार उस पर अडिग है और वो सरकार ये सिलेंडर और सिलेंडर छोड़ो हमने तो जो पीएनजी गैस लाइन जिन-जिन घरों में थी हमने उनको भी डीबीटी किया है, कोई मीडिएशन नहीं है। जिसका जो सिलेंडर यूज़ कर रहा था, जो पाइप लाइन यूज़ कर रहा था, जो राशन कार्ड की पूरी कैटेगरी थी एज इट इज हमने एक बटन दबाया और सर, हर एक व्यक्ति को 853 रूपये उसके खाते में मिल गए, सीधासीधा डीबीटी कर दिए। अध्यक्ष जी, आज के समय पर जब सिलेंडर की बात हो रही है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी इस समय जिस तरीके की वैश्विक परिस्थितियां चल रही है और जिस तरीके की एलपीजी की आपूर्ति में बाधा आई और हमारी गवर्नमेंट दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के पूरे समन्वय के साथ में इस सिचुएशन को मजबूती से संभाले हुए हैं और मैं यह मानती हूं कि जब भी देश किसी विकट परिस्थिति से होकर के गुजरे तो जनता का, सरकार का, नेताओं का सबका यह फर्ज बनता है कि विकट परिस्थिति में एकजुट होकर के उस परिस्थिति का सामना करें। पैनिक

नहीं, पैनिक नहीं प्लानिंग के साथ काम करें ये हम सबका फर्ज बनता है। पर देखिए कैसे लोग हैं इन मुद्दों पर राजनीति करने के लिए आते हैं कोई टीशर्ट पहन के आ रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कट-आउट लेकर घूम रहा है। परंतु उन्हें यह समझ नहीं है कि आज हमारा देश किन बेहतर स्थिति में अपने आप को रखे हुए हैं। जहां एक और विश्व के इतने सारे देश युद्ध में लगे हैं, उनके जनता का जीवन संकट में है। आज हम एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां अपने इस देश में रह रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि ये वेस्ट एशिया में जो युद्ध के कारण से चल रहे विकट परिस्थितियों के कारण जिस तरीके से पूरे विश्व में पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी। आज ही उन्होंने हमारे पूरे देश में हर राज्य के लिए पेट्रोल और डीजल के रेटों में स्टेबिलिटी लाने के लिए पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी को 13 रूपये से घटाकर के 3 रूपये कर दिया 3 रूपये प्रति लीटर और डीजल पे 10 रूपये से घटा करके जीरो करके प्रति लीटर जीरो, अब एक्साइज ड्यूटी होगी। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी परिस्थिति में पैनिक नहीं प्लानिंग के साथ में काम करते हुए पूरे देश की जनता को यह संबल दिया है और किसी भी तरीके का कोई एडवर्स इफेक्ट कीमतों का प्रभाव हमारे देश की जनता पर पड़ने वाला नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, बहुत कुछ है इस एक साल में हमने बहुत कुछ देखा, सहा, बहुत कुछ किया चलते रहे हम क्योंकि इस दिल्ली को इस दिल्ली को अब बहानों की जरूरत नहीं है, परिणाम देने होंगे। यहां पे हेडलाइंस के साथ काम नहीं होगा, गाइडलाइन के साथ में काम होगा और 11 साल जिस दिल्ली को उन्होंने अटकाया, लटकाया और भटकाया। हम पूरी तरीके से नई गवर्नेंस के साथ, नई सोच के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जवाबदेही के साथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हर काम, हर अधूरा काम अब पूरा होगा। हर रुपए का हम हिसाब देंगे और हर नागरिक को उसके अधिकार देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का होगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में अब टकराव नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राजनीति नहीं परफॉर्मेंस होगी और इतना कह सकती हूं अध्यक्ष जी इस सदन के आगे कि-

''कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए

कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए

कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए।''

बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।

अनुदानों की मांगें(वर्ष 2026-27)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब अनुदानों की मांगे। अब सदन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 से संबंधित डिमांड फॉर ग्रांट्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा।

डिमांड नंबर एक लेजिसलेटिव असेंबली, जिसमें रेवेन्यू में 44 करोड़ 36 लाख तथा कैपिटल में 4 करोड़ 31 लाख है। कुल राशि 48 करोड़ 67 लाख सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर एक पास हुई।

डिमांड नंबर दो एलजी सेक्रेटेरिएट, जिसमें रेवेन्यू में 10 लाख रूपये हैं। सदन के सामने हैं।

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर दो पास हुई।

डिमांड नंबर तीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें रेवेन्यू में 23 अरब 57 करोड़ 36 लाख 50000 रूपये हैं तथा कैपिटल में 4 अरब 93 करोड़ 49 लाख 50000 कुल राशि 28 अरब 50 करोड़ 86 लाख रूपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर तीन पास हुई

डिमांड नंबर चार फाइनेंस जिसमें रेवेन्यू में 5 अरब 19 करोड़ 66 लाख 50000 रूपये हैं तथा कैपिटल में 56 करोड़ 3 लाख 50000 रूपये हैं। कुल राशि 5 अरब 75 करोड़ 70 लाख सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर चार पास हुई।

डिमांड नंबर पांच होम जिसमें रेवेन्यू में 12 अरब 11 करोड़ 63 लाख रूपये हैं तथा कैपिटल में 4 अरब 50 करोड़ 37 लाख रूपये कुल राशि 16 अरब 62 करोड़ रूपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर पांच पास हुई।

डिमांड नंबर छः एजुकेशन जिसमें रेवेन्यू में 178 अरब 58 करोड़ 52 लाख 90000 रूपये हैं तथा कैपिटल में 12 अरब 84 करोड़ 91 लाख 10000 रूपये कुल राशि 191 अरब 43 करोड़ 44 लाख सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर छह पास हुई।

डिमांड नंबर सेवन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ जिसमें रेवेन्यू में 111 अरब 92 करोड़ 69 लाख 75000 रूपये हैं तथा कैपिटल में 14 अरब 32 करोड़ 40 लाख 50000 रूपये कुल राशि 126 अरब 25 करोड़ 10 लाख 25000 रूपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर सात पास हुई।

डिमांड नंबर आठ सोशल वेलफेयर जिसमें रेवेन्यू में 98 अरब 83 करोड़ 23 लाख 10000 रूपये हैं तथा कैपिटल में एक अरब 42 करोड़ 29 लाख रूपये कुल राशि 100 अरब 25 करोड़ 52 लाख 10000 रूपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर आठ पास हुई।

डिमांड नंबर नाइन लेबर एंड एंप्लॉयमेंट जिसमें रेवेन्यू में 64 करोड़ 63 लाख 50000 रूपये तथा कैपिटल में एक करोड़ 76 लाख 50000 रूपये कुल राशि 66 करोड़ 40 लाख रूपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर नौ पास हुई।

डिमांड नंबर 10 रेवेन्यू जिसमें रेवेन्यू में 41 अरब 24 करोड़ 38 लाख 74000 रूपये हैं तथा कैपिटल में 2 अरब 19 करोड़ 89 लाख 45000 रूपये कुल राशि 43 अरब 44 करोड़ 28 लाख 19000 रूपये सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में है वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

डिमांड नंबर 10 पास हुई।

डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट जिसमें रेवेन्यू में 88 अरब 1 करोड़ 24 लाख 75 हजार रूपए है तथा कैपिटल में 80 अरब 85 करोड़ 59 लाख 25 हजार रूपए कुल राशि 168 अरब 86 करोड़ 84 लाख रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 11 पास हुई।

डिमांड नंबर 12 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब 61 करोड़ 63 लाख 6 हजार रूपए है तथा कैपिटल में 8 करोड़ 35 लाख रूपए कुल राशि 3 अरब 69 करोड़ 98 लाख 6 हजार रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 12 पास हुई।

डिमांड नंबर नंबर 13 सर्विसेज जिसमें रेवेन्यू में 27 करोड़ 89 लाख तथा कैपिटल में 3 करोड़ 2 लाख रूपए कुल राशि 30 करोड़ 91 लाख रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 13 पास हुई।

डिमांड नंबर 14 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिसमें रेवेन्यू में 39 करोड़ 43 लाख 70 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 1 करोड़ 15 लाख 30 हजार रूपए कुल राशि 40 करोड़ 59 लाख रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 14 पास हुई।

डिमांड नंबर 15 विजिलेंस जिसमें रेवेन्यू में 18 करोड़ 41 लाख रूपए तथा कैपिटल में 60 लाख रूपए कुल राशि 19 करोड़ एक लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 15 पास हुई।

डिमांड नंबर 16 इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जिसमें रेवेन्यू में एक अरब 29 करोड़ 74 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 34 लाख रूपए कुल राशि एक अरब 30 करोड़ 8 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 16 पास हुई।

डिमांड नंबर 17 सिलेक्शन बोर्ड इसमें रेवेन्यू में 1 अरब 71 करोड़ 17 लाख 50 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 65 लाख रूपए कुल राशि 1 अरब 71 करोड़ 82 लाख 50 हजार रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 17 पास हुई।

डिमांड नंबर 18 इलेक्शन जिसमें रेवेन्यू में 37 करोड़ 17 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 27 करोड़ 5 लाख रूपए कुल राशि 64 करोड़ 22 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 18 पास हुई।

डिमांड नंबर 19 प्लानिंग इसमें रेवेन्यू में 67 करोड़ 60 लाख 50 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 44 अरब 94 करोड़ 10 लाख 50 हजार रूपए कुल राशि 45 अरब 61 करोड़ 71 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 19 पास हुई।

डिमांड नंबर 20 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें रेवेन्यू में 71 करोड़ 11 लाख रूपए तथा कैपिटल में 4 करोड़ 10 लाख रूपए कुल राशि 75 करोड़ 21 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 20 पास हुई।

डिमांड नंबर 21 आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 65 करोड़ 79 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 7 करोड़ 97 लाख रूपए कुल राशि 1 अरब 73 करोड़ 76 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 21 पास हुई।

डिमांड नंबर 22 ट्रांसपोर्ट जिसमें रेवेन्यू में 45 अरब 73 करोड़ 99 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 38 अरब 16 लाख रूपए कुल राशि 83 अरब 74 करोड़ 15 लाख रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वेे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 22 पास हुई।

डिमांड नंबर 23 इंडस्ट्रीज जिसमें रेवेन्यू में 90 करोड़ 18 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 2 अरब 8 करोड़ 48 लाख रूपए कुल कुल राशि 2 अरब 98 करोड़ 66 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 23 पास हुई।

डिमांड नंबर 24 टूरिज्म जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 2 करोड़ 29 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 3 अरब 10 करोड़ रूपए कुल राशि 4 अरब 12 करोड़ 29 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 24 पास हुई।

डिमांड नंबर 25 सिविल सप्लाई जिसमें रेवेन्यू में 5 अरब 69 करोड़ 74 लाख 95 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 10 करोड़ 35 लाख रूपए कुल राशि 5 अरब 80 करोड़ 9 लाख 95 हजार रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 25 पास हुई।

डिमांड नंबर 26 डेवलपमेंट जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 25 करोड़ 52 लाख 28 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में 8 अरब 36 करोड़ 26 लाख 50 हजार रूपए कुल राशि 9 अरब 61 करोड़ 78 लाख 78 हजार रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 26 पास हुई।

डिमांड नंबर 27 कोऑपरेटिव जिसमें रेवेन्यू में 26 करोड़ 36 लाख रूपए तथा कैपिटल में 2 करोड़ 46 लाख 25 हजार रूपए कुल राशि 28 करोड़ 82 लाख 25 हजार रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 27 पास हुई।

डिमांड नंबर 28 इरीगेशन एंड फ्लड जिसमें रेवेन्यू में 2 अरब 84 करोड़ 55 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 3 अरब 25 करोड़ 60 लाख रूपए कुल राशि 6 अरब 10 करोड़ 15 लाख रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 28 पास हुई।

डिमांड नंबर 29 एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसमें रेवेन्यू में 6 अरब 99 करोड़ 57 लाख 80 हजार रूपए हैं तथा कैपिटल में एक अरब 61 करोड़ 75 लाख 50 हजार रूपए कुल राशि 8 अरब 61 करोड़ 33 लाख 30 हजार रूपए सदन के सामने हैं

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 29 पास हुई।

डिमांड नंबर 30 पब्लिक वर्क्स जिसमें रेवेन्यू में 21 अरब 16 करोड़ 24 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 38 अरब 5 करोड़ 46 लाख रूपए कुल राशि 59 अरब 21 करोड़ 70 लाख रूपए सदन के सामने हैं जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 30 पास हुई।

डिमांड नंबर 31 लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें रेवेन्यू में 22 करोड़ 7 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 1 करोड़ 47 लाख रूपए कुल राशि 23 करोड़ 54 लाख रूपए सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 31 पास हुई।

डिमांड नंबर 32 पावर जिसमें रेवेन्यू में 36 अरब 7 करोड़ 29 लाख रूपए हैं तथा कैपिटल में 3 अरब 35 करोड़ चार लाख रूपए हैं। कुल राशि 39 अरब 42 करोड़ 33 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 32 पास हुई।

डिमांड नंबर 33 लोन्स जिसमें कैपिटल में 1 करोड़ 30 लाख रूपए सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 33 पास हुई।

डिमांड नंबर 34 पेंशन्स जिसमें रेवेन्यू में 7 करोड़ 51 लाख रूपए हैं। सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 34 पास हुई।

सदन ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 693 अरब 73 करोड़ 13 लाख 53 हजार रूपए कैपिटल में और कैपिटल में 265 अरब 16 करोड़ 74 लाख 85 हजार रूपए कुल राशि 958 अरब 89 करोड़ 88 लाख 38 हजार रूपए की डिमांड को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026

अब दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) The Delhi Appropriation (No.3)Bill,2026 (Bill No.7 of 2026) सदन की कारवाई 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है। अब मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की परमिशन चाहती हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सत्ता पक्ष के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूं।[1]

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड दो, खंड तीन व शेड्यूल बिल का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सत्ता पक्ष के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खंड दो, खंड तीन एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए।

प्रश्न है कि खंड एक, प्रियमबल और टाइटल बिल का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

(सत्ता पक्ष के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

खंड एक, प्रियमबल और टाइटल बिल का अंग बन गए।

अब मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) को पास किया जाए।

श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) को पास किया जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वे ना कहें,

[1] दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23573 पर उपलब्ध।

(सत्ता पक्ष के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

दिल्ली विनियोजन(संख्या-3) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-7) पास हुआ।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि सदन के सत्रावसान के लिए मैं उपराज्यपाल महोदय के पास प्रस्ताव भेज रहा हूं। वर्तमान सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सदन की नेता एवं माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, सभी मंत्रीगण तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रगान के लिए खड़े हो।

(राष्ट्रगान- जन गण मन)

भारत माता की जय। अब सदन की कारवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कारवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

.....समाप्त.....